रजिस्टर्ड सं. डी. एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 1992/भाद्रपद 7, 1914
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1992/BHADRA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का. आ. .. 2342 : आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, पुणे" को 1992-93 से 1994-95 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधयधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(1) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उप-धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यता उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर-निर्धारिती उपर्-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खंड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा;

(4) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना संख्या 9058/फा.सं. 196/9/92-आ.क.नि.-2]

केशव देव, उप सचिव

2066 GI/92—1

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st July, 1992

S.O. 2242.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the 'Maharashtra Cricket Association, Pune' for the purpose of the said clause for assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application in consonance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds [other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third proviso to the aforesaid clause (23)] for any period during the previous year(s) relevant to the assesment year(s) mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9058/F. No. 196/8/92-IT(A)]

KESHAV DEV, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1992

का.आ. 2243 :--केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

पहली अनुसूची में, "गांधी जी विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे "बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी.....एम.बी.बी.एस." प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"डाक्टर आफ मेडिसिन (आयुर्विज्ञान).....	एम.डी. (आयु)
डाक्टर आफ मेडिसिन (संवेदनाहरण).....	एम.डी. (संवेदना)
डिप्लोमा इन अनेस्थीसियोलोजी.....	डी.ए

टिप्पण :--ये अर्हताएं जब 27 जनवरी, 1988 को या उसके पूर्व अनुदत्त की जाती हैं तब मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी।"

[संख्या वी-11015/11/88-एम ई० (पी.)]

आर० विजया कुमारी, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th July, 1992

S.O 2243.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the First Schedule, under the heading "GANDHIJI UNIVERSITY" after the entry "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.....M.B.B.S.", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Medicine).....	M.D. (Med.)
Doctor of Medicine (Anaethesiology) ...	M.D. (Anaes.)
Diploma in Anaesthesiology	D.A.

NOTE.—These qualifications shall be recognised medical qualifications when granted on or before the 27th January, 1988."

[No. V-11015/11/88-ME(P)]

R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1992

का.आ. 2244 :--केंद्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अनुसूची में "दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर

डाक्टर ऑफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)	--एम डी (सा आ वि.)
डाक्टर ऑफ सर्जरी (सामान्य शल्य विज्ञान)	--एम.एस. (सा.श.वि.)
डाक्टर ऑफ मेडिसिन (एनेस्थीसियोलोजी)	--एम.डी. (एनेस्थ)

टिप्पण: --उपरोक्त अर्हताएं केवल तब मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी जब वे 1 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात् प्रदान की जाती है।"

[संख्या वी.-11015/28/92-एम.ई. (यू जी.)]

आर विजय कुमारी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1992

S.O. 2244.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, after the heading "South Gujarat University" and entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"SHER-I-KASHMIR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SRINAGAR.

Doctor of Medicine (General Medicine)	M.D. (Gen. Med.)
Master of Surgery (General Surgery)	M.S. (Gen. Surg.)
Doctor of Medicine (Anaesthesiology)	M.D. (Anaes.)

NOTE.—The above said qualifications shall be recognised medical qualifications only when granted on or after 1st July, 1986."

[No. V. 11015/28/92-ME(UG)]

R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2245:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अधिसूचना का.आ.सं. 3195 तारीख 14-11-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे.एन.ए.एफ से जोटाणा-2 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला और तालुका—मेहसाना।

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टर	आर	सेंटीय
सीडोसना	40	0	07	68
	39/1	0	05	52
	39/1	0	08	88
	39/1	0	02	40
	38	0	10	44
	38	0	05	16

[सं. ओ.-11027/72/87-ओ.एन.जी.डी.-III]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2245.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3195 dated 14-11-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JNAF to Jotana-2

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Sidosana	40	0	07	68
	39/1	0	05	52
	39/1	0	08	88
	39/1	0	02	40
	38	0	10	44
	38	0	05	16

[No. O-11027/72/87-ONG-D-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2246:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 की 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग का अधिसूचना का.आ.सं. 3043 तारीख 20-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी.सी एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसकोई

गांव	ब्लाक न.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कठवाडा	133	0	19	50
	134	0	32	30
	123	0	13	50
	122	0	19	50
	121	0	30	00
	219	0	25	50
	221	0	09	00
	223	0	09	00
	224	0	00	60
	228	0	01	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	20
	225	0	27	00
	227	0	21	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	328	0	12	00
	327	0	24	00
	321	0	06	00
	324	0	32	25
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	439	0	15	00
	436	0	12	00
	434	0	20	25
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	465	0	27	00
	467	0	015	75
	468	0	06	00
	563	0	10	50
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	569	0	09	00
	568	0	09	75
	567	0	10	50
	592	0	10	50
	595	0	00	60
	224	0	00	60
	593	0	30	00
	594	0	04	80
	589	0	09	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	685	0	16	50
	715	01	29	00
	कार्ट ट्रेक	01	50	
	716	01	02	00
	718	0	06	00

[सं. ओ.-11027/143/89-ओएनजी डी-III/IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2246.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3043 dated 20-1189 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat Dist : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kathawada	133	0	19	50
	134	0	32	30
	123	0	13	50
	122	0	19	50
	121	0	30	00
	219	0	25	50
	221	0	09	00
	223	0	09	00
	224	0	00	60
	228	0	01	50
	Cart track	0	01	20
	225	0	27	00
	227	0	21	00
	Cart track	0	01	50
	328	0	12	00
	327	0	24	00
	321	0	06	00
	324	0	32	25
	Cart track	0	02	40
	439	0	15	00
	436	0	12	00
	434	0	20	25
	Cart track	0	01	50
	465	0	27	00
	467	0	015	75
	468	0	06	00
	563	0	10	50
	Cart track	0	02	40
	569	0	09	00
	568	0	09	75
	567	0	10	50
	592	0	10	50
	595	0	00	60

1	2	3	4	5
	224	0	00	60
	593	0	30	00
	594	0	04	80
	589	0	09	00
	Cart track	0	01	50
	68	0	16	50
	715	0	29	00
	Cart track	0	01	
	716	01	02	00
	718	0	06	00

[No. O-11027/143/89-ONG-D-II]/IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2247.—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का आ स. 227 तारीख 30-1-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा;

अनुसूची

एल.एन. ए.सी. से लिच ई.पी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : —गुजरात जिला व तालुका : —मेहसाना

गांव	ब्लाक सं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
हरसुन्डल	11, 12,, 13	0	11	52
	474	0	09	00
	466	0	13	44
	465	0	09	12

[सं. ओ-11027/9/87-ओ.एन जी डी III]
एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2247.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 227 dated 30-1-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LNAC to LINCH EPS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Harsundal	11, 12 & 13	0	11	52
	474	0	09	00
	466	0	13	44
	465	0	09	12

[No. O-11027/9/87-ONG D-III]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2248.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 3145 तारीख 22-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अत: अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त

भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

टी. पो.—रनासन से रामोल जी. जी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—दसक्रोई

गांव	ब्लाक .	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
इनासन	313	0	35	84
	302	0	00	06
	315	0	08	50
	311	0	29	45
	316	0	01	50

[सं. ओ-11027/74/90-ओ. एन. जी. डी.—III]
एम मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2248.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3145 dated 22-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from T.P. Ranasan to Ramol GGS

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Enasan	313	0	35	84
	302	0	00	06
	314	0	08	50
	315	0	29	45
	316	0	01	50

[No. O-11027/74/90-O.N.G. D III]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2249 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3146 तारीख 22-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे वर्णिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

टी. पो. रनासन से रामोल जी. जी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—दसक्रोई

गांव	ब्लाक .	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
बिलासिया	148	0	00	14
	149	0	13	53
	150	0	04	50
	201	0	53	90
	कार्टट्रेक	0	02	00
	200	0	19	7
	199	0	16	7
	14	0	96	3
	13	0	16	3
	कार्टट्रेक	0	02	00
	38	0	20	96
	47	0	00	69
	46	0	22	80

[सं. ओ.-11027/127/90—ओ. एन. जी. डी -III]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2249.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3146 dated 22-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from T.P. Ranasan to Ramol GGS

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bilasiya	148	0	00	12
	149	0	13	53
	150	0	04	50
	201	0	53	90
	Cart track	0	02	00
	200	0	19	70
	199	0	16	78
	14	0	96	36
	13	0	16	32
	Cart track	0	02	00
	38	0	20	96
	47	0	00	69
	46	0	22	80

[No. O-11027/126/90-ONG-D-III
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2250.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3202 तारीख 29-10-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल एन ए सी से लिंच ई पी एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला और तालुका — महेसाना

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
सीडोसना	185	00	15	96
	186	00	18	84

[सं. ओ.-11027/67/87-ओ. एन. जी. डी.-III]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2250.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3202 dated 29-10-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LNAC to Linch EPS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Sidosna	185	00	15	96
	186	00	18	84

[No. O-11027/67/87-ONG-D-III]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2251.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 232 तारीख 30-1-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. बी. ए. एफ. से सोभासन—7 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
हेबुवा	152	0	08	00
	262/1	0	16	32
	264/1	0	03	12
	262	0	04	92
	266	0	04	80

[सं. ओ-11027/18/87—ओ एन जी डी-III]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2251.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 232 dated 30-1-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SBAF to Sobhasan-7

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	152	0	08	00
	262/1	0	16	32
	264/1	0	03	12
	262	0	04	92
	266	0	04	80

[No. O-11027/18/87-ONG-D-III]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2252.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3037 तारीख 20-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात तालुका—दस क्रोई जिला अहमदाबाद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
वस माल	542	0	1	50
	539	0	6	00
	538	0	6	00

1	2	3	4	5
	540	0	9	60
	536	0	3	60
	535	0	0	60
	529	0	6	00
	530	0	12	00
	कार्ट ट्रेक	0	1	50
	345	0	6	60
	346	0	14	40
	347	0	0	60
	348	0	8	55
	349	0	6	00
	340	0	6	00
	341	0	6	60
	339	0	0	60
	338	0	15	60
	334	0	6	75
	335	0	0	60
	336	0.	15	60
	323	0	3	60
	327	0	1	50
	324	0	9	60
	326	0	9	60
	325	0	12	00
	311	0	16	80
	310	0	15	60
	273	0	18	00
	272	0	14	40
	271	0	16	80

[स. ओ.-11027/137/89—ओ. एन. जी.-डी. III/IV]

एम मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2252.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3037 dated 20-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol G.C.S. to Reliance Industries

State : Gujarat *Taluka : Dascroi* *District : Ahmedabad*

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vastral	542	0	1	50
	539	0	6	00
	538	0	6	00
	540	0	9	60
	536	0	3	60
	535	0	0	60
	529	0	6	00
	530	0	12	00
	Cart track	0	1	50
	345	0	6	60
	346	0	14	40
	347	0	0	60
	348	0	8	55
	349	0	6	00
	340	0	6	00
	341	0	6	60
	339	0	0	60
	338	0	15	60
	334	0	6	75
	335	0	0	60
	336	0	15	60
	323	0	3	60
	327	0	1	50
	324	0	9	60
	326	0	9	60
	325	0	12	00
	311	0	16	80
	310	0	15	60
	273	0	18	00
	272	0	14	40
	271	0	16	80

[No. O-11027/137/89-ONG-D-III/IV]

M.MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2253—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3034 तारीख 20-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य:—गुजरात जिला:—अहमदाबाद तालुका: दसक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
भुवालडी	516	0	24	00
	517	0	09	60
	—	—	—	—
	526	0	36	00
	525	0	10	50
	537	0	09	60
	538	0	04	80
	539	0	00	30
	540	0	06	00
	541	0	04	50
	573	0	19	20
	556	0	12	00
	572	0	01	80
	557	0	09	60
	565	0	12	00
		0	03	00
	713	0	34	80

[सं. ओ-11027/147/89-ओ. एन. जी. डी-III (iv)]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2253.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3034. dated 20-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM RAMOL GCS TO RELIANCE INDUSTRIES

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Shuvaldi	516	0	24	00
	517	0	09	60
	—	—	—	—
	526	0	36	00
	525	0	10	50
	537	0	09	60
	538	0	04	80
	539	0	00	30
	540	0	06	00
	541	0	04	50
	573	0	19	20
	556	0	12	00
	572	0	01	80
	557	0	09	60
	565	0	12	00
	Cart track	0	03	00
	713	0	34	80

[No. O-11027/147/89-ONG D-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2254.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3042 तारीख 20-1-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी. सी. एस. से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य:—गुजरात जिला:—अहमदाबाद तालुका:—दस क्रोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कनभा	437	0	00	90
	438	0	24	00
	439	0	15	15
	441	0	00	60
	442	0	18	30
	444	0	10	50
	459	0	05	25
	460	0	06	00
	461	0	04	20
	463	0	13	50
	466	0	07	50

[सं. ओ.—11027/140/89—ओ. एन. जी. डी.-III(IV)]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2254.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3042 dated 20-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat Dist.: Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kanbha	437	0	00	90
	438	0	24	00
	439	0	15	15
	441	0	00	60
	442	0	18	30
	444	0	10	50
	459	0	05	25
	460	0	06	00
	461	0	04	20
	463	0	13	50
	466	0	07	50

[No.O-11027/140/89—ONG.D-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2255.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 422 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. ए. आई. से पानी इंजेक्शन हेडर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—वागरा

गांव	ब्लाक नं.	है.	आर	सेन्टी
मुलेर	2/पी	0	09	10
	1	0	10	14
	119	0	04	16
	118	0	04	25
	116	0	41	21
	115	0	02	08
	113	0	00	80
	91	0	05	20

90/ए/बी	0	12	52
92/ए/बी	0	01	52
87	0	22	30
85	0	03	17
86	0	10	35
81	0	17	68
82	0	00	32
66	0	00	85
65	0	19	76
64	0	20	80
63	0	03	04

[सं. ओ.-11027/188/90—ओ. एन. जी. डी.-III/(IV)]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2255.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 422 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government :

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration of Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From GNAI to Water Injection Header

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Muller	2/P	0	09	10
	1	0	10	14
	119	0	04	16
	118	0	04	25
	116	0	41	21
	115	0	02	08
	113	0	00	80
	91	0	05	20
	90/A/B	0	12	52
	92/ /B	0	01	52
	87	0	22	30
	85	0	03	17
	86	0	10	35
	81	0	17	68
	82	0	00	32
	66	0	00	85
	65	0	19	76
	64	0	20	80
	63	0	03	04

[No. O-11027/188/90-ONG.D-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2256 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3039 तारीख 20-12-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी. सी. ऐस से रिलायन्स उद्योग तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका दस कोई

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	से.
रामोल	141/3	0	18	00
	140	0	00	30

[सं. ओ.-11027/142/89 ओ. एन. जी. डी. III/IV]

एन. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2256.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 3039 dated 20-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user ernment declared its intention to acquire the right of user in

lands specified in the Schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right or user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Ramol GCS to Reliance Industries

State : Gujarat Distt : Ahmedabad Taluka : Descroi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ramol	141/3	0	18	00
	140	0	00	30

[No. O-11027/142/89-ONG. D-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2257.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 967 तारीख 15-3-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के. एन. के. फेस -II के लिए लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : बड़ोदरा

गांव	सर्वे नं.	हे	आर.	से
पदमला	736/2बी	0	54	80

[सं. ओ-11027/151/90/ओ एन जी-डी III/IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2257.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 967 dated 15-3-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the Act the Central Government hereby declares that the right or user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line for K. N. K. Phase-II

State : Gujarat Distt. & Taluka : Vodadara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centare
Padamala	736/2B	0	54	80

[No. O-11027/151/90-ONG D-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2258.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 836 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (III) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

और अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों म उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी-11 से जंक्शन बिन्दु तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : जम्बुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर	से.
कहानवा	45	0	19	24
	46	0	06	99
	47	0	00	15
	39	0	10	40

[स. आ.-12016/155/91/ओ. एन. जी. डी. -IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2258.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 836 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the omCompetent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From D-11 to Junction Point

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kahanwa	45	0	19	24
	46	0	06	99
	47	0	00	15
	39	0	10	40

[No. O-12016/155/91/ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2259.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 839 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों का उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा का उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने का बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन का इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. सी. पी. से जी. एन. ए. क्यू तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : जंबुसर

गांव	ब्लाक	हे.	आर.	सें
जांसेरा	85/ए/बी.	0	20	80
	35	0	20	54
	22	0	00	49
	21	0	06	50
	20	0	00	52
	15	0	13	62
	14	0	00	14
	13	0	07	28
	12	0	07	28
	कार्टट्रेक	0	01	95
	7	0	13	52
	8	0	15	60
	1	0	15	06
	296	0	11	44

[सं. 12016/158/91/ओ. एन. जी. डी -IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2259.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 839 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right

of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right or user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNCP to GNAQ

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Vanseta	85/A/B	0	20	80
	33	0	20	54
	22	0	00	48
	21	0	06	50
	20	0	00	52
	15	0	13	52
	14	0	00	14
	13	0	07	28
	12	0	07	28
	Cart track	0	01	95
	7	0	13	52
	8	0	15	60
	1	0	15	08
	296	0	11	44

[No. O-12016/155/91-ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2260.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 841 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी सी टी से जंक्शन बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : जंबूसर

गांव	ब्लाक नं.	है.	आर	से
काहानवा	67	0	04	94
	59	0	17	55
	58 ए	0	07	02
	50	0	01	96
	49	0	06	88
	48	0	08	58
	47	0	08	06
	34	0	08	81

[सं. O-12016/160/91/ओ.एन.जी.डी.-IV]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2260.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 841 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right or user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline From DBT to Junction Point

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kahanwa	67	0	04	94
	59	0	17	55
	58/A	0	07	02
	50	0	01	96
	49	0	06	88
	48	0	08	58
	47	0	08	06
	34	0	08	81

[No. O-12016/160/91-ONGD-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2261—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.स. 842 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.एन.जी.जे. से जी एन.जी के./जी.एन जी.ए. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	है.	आर.	मे
मुलेर	82	0	43	00
	81	0	33	60
	73	0	48	00
	76	0	06	00
	75	0	34	00

[सं. ओ-12016/161/91/ओएन.जी डी -IV]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2261.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 842 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notificaion for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From GNGJ to GNGK/GNGA

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Muller	82	0	42	00
	81	0	33	60
	73	0	48	00
	76	0	06	00
	75	0	34	00

[No. O—12016/161/91 ONC D-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2262—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.स. 843 तारीख 14-3-1992 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी जे ए जे से डब्ल्यू एच आई देहेज तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक न.	हे.	आर.	स.
रहीयाद	199	0	03	12
	200	0	03	25

[सं. ओ-12016/162/91/ओ.एन.जी.डी.-(4)]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2262.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 843 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the Act the Central Government hereby declares that the right or user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DJAJ to WHI DAHEJ

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Rahiyad	199	0	03	12
	200	0	03	25

[No. 0—12016/162/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2263.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 844 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन जी एच से जी एन ए ए तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर.	सें.
मुलेर	57	0	00	70
	56	0	19	80
	55	0	14	88
	54	0	15	84
	53	0	20	28
	61	0	26	60
	63	0	42	00

[सं. ओ-12016/163/91/ओ.एन.जी.डी-(4)]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2263.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 844 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appnded to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of

user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGH to GNAA

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Muller	57	0	00	70
	56	0	19	80
	55	0	14	98
	54	0	15	84
	53	0	20	28
	61	0	26	60
	63	0	42	00

[No. O-12016/163/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2264.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 845 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ओ.एन.जी.एस. से जी.एन.जी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सें.
गंधार	412	0	18	40
	411	0	29	20
	406	0	37	20
	404	0	26	20
	403	0	14	00
	401	0	07	20
	399	0	09	98
	397	0	24	00
	398	0	00	25

[सं. O-12016/164/91-ओ.एन.जी.डी.-4]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2264.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 845 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGS to GNGF

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Gandhar	412	0	18	40
	411	0	29	20
	406	0	37	20
	404	0	26	20
	403	0	14	00
	401	0	07	20
	399	0	09	98
	397	0	24	00
	398	0	00	25

[No. O-12016/164/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का आ 2265—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं 846 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन एफ यू से जी एन एफ वाई तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात	जिला भरूच		तालुका वागरा	
गांव	ब्लाक नं	हे	आर	से
मुल्लेर	63	1	02	00

[सं ओ-12016/165/91-ओ एन.जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2265.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 846 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From GNFU to GNFY

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No	Hectare	Are	Centiare
Muller	63	1	02	00

[No. O-12016/165/9-ONG D-IV]

M MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का आ 2266—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं 847 तारीख 14-3-1992 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी जी ए जे. से दहेज जी जी एस तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात	जिला भरूच		तालुका वागरा	
गांव	ब्लाक नं	हे	आर.	सेंटीयर
कोलीयाद	66	0	12	48
	113	0	35	56
	112	0	09	36

	2	3	4	
कोलियाद—पगरी	111	0	14	56
	116	0	12	48
	114	0	20	80
	108/बी	0	21	84
	कार्ट ट्रेक	0	07	28
	136/बी	0	26	00
	197	0	02	08
	196	0	11	44
	201	0	07	28
	195	0	26	00
	185	0	12	48
	193	0	10	40
	186	0	15	60
	187	0	07	28
	183/ए	0	07	90
	183/बी	0	22	88
	182	0	07	60

[सं. ओ-12016/166/91/ओ.एन.जी.डी.-(iV)]

एम० मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2266.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 847 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM DJAJ TO DAHEJ GGS

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Koliad	66	0	12	48
	113	0	35	56
	112	0	09	36
	111	0	14	56
	116	0	12	48
	114	0	20	80
	108/B	0	21	84
Koli d (Cont .)	Cart track	0	07	28
	136/B	0	26	00
	197	0	02	08
	196	0	11	44
	201	0	07	28
	195	0	26	00
	185	0	12	48
	193	0	10	40
	186	0	15	60
	187	0	07	28
	183/A	0	07	90
	183/B	0	22	88
	182	0	07	60

[No O-12016/163/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का० आ० सं० 2267—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम) 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 848 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचियों विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जी एन ई बाय से जी एन एच डी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला – भरूच तालुका – वागरा

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आर	से०
गंधार	321	0	80	00

[सं ओ-12016/162/91/ओ० एन० जी० डी० -4)]

एम० मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2267.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 848 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of seciton, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULF

PIPELINE FROM GNEY TO GNHD

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectar	Are	Centiare
Gandhar	321	0	80	00

[No. O-12016/167/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का० आ० 2268.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ० सं 849 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ओ. एन. जी. यू. से ई. पी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरूच तालुका—वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर	से.
मुलेर	63	0	34	45

[सं. O-12016/168/91-ओ. एन. जी. डी.-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2268.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 849 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GNFU TO EPS.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Muller	63	0	34	45

[No. O-12016/168/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का० आ० 2269.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं. 855 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न

अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल डब्ल्यू ई यू से लनवा ई पी एस-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—महेसाणा तालुका—चनास्मा

गांव	सर्वे नं.	हे०	आर०	से
दानोदरडा	554	0	03	48
	555 1	0	08	04
	593	0	04	44
	592पी	0	06	84
	592पी	0	02	88

[सं. ओ-12016/174/91/ओ. एन० जी० डी०-IV]

एम० मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2269.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 855 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM LWEU TO LANWA EPS-I

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Danodarda	554	0	03	48
	555/1	0	08	04
	593	0	04	44
	592/P	0	06	84
	592/P	0	02	88

[No. O-12016/174/91-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2270.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 854 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

इलाव -2 से एल डब्ल्यू एम बी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला : भरूच तालुका—हांसोट

गांव	सर्वे न	हेक्टर	आर	सेन्टी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मालणपुर	225	0	04	03
	224	0	07	82
	219/बी	0	11	96
	218	0	02	50
	207/ए-बी	0	09	65
	204	0	07	61
	201	0	07	41
	206	0	13	86

[संख्या O-12016/173/91/ओ एन जी डी-IV]

एम मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2270.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 854 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPLLINE FROM ELLAV-2 TO SWMR

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Malanpor	225	0	04	03
	224	0	07	82
	219/B	0	11	96
	218	0	02	56
	207/A-B	0	09	65
	204	0	07	61
	201	0	07	41
	206	0	13	61

[No. O-12016/173/91-ONC.D-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का. आ. 2271.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्या 858 तारीख 14-3-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एल. डब्ल्यू ज पी (32) से मनसा ई. पी एस 1 तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : महेसाना तालुका : कालोल

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणवरा	595	0	00	48
	596	0	10	84
	397	0	05	70
	592/पी	0	04	80
	591	0	06	30
	590	0	06	48
	589	0	01	32
	588	0	12	96
	565	0	02	52
	568	0	06	00
	584	0	04	56
	568	0	05	04
	569	0	11	28
	570	0	05	0
	571	0	03	50
	534/पी	0	02	76
	534/पी	0	1[illegible]	52
	516/पी	0	01	0[illegible]
	528	0	08	40
	52[illegible]	0	02	88
	526	0	07	80
	526	0	04	08
	590	0	10	20
	591	0	00	60

[संख्या ओ-12016/173/91-ओ. एन. जी. डी.-IV]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2271.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 858 dated 14-3-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHLDULE
PIPELINE FROM LWEV (32) TO LANWA EPS-I
State : Gujarat Distri t : Meh-ana T. luk : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Danodarda	595	0	06	48
	596	0	10	84
	59'	0	05	76
	59? P	0	04	80
	591	0	06	36
	590	0	06	49
	589	0	01	3?
	588	0	12	96
	565	0	02	52
	566	0	06	00
	584	0	04	56
	568	0	05	64
	569	0	11	28
	570	0	05	04
	571	0	01	56
	534 P	0	02	76
	534/P	0	14	52
	516 P	0	01	68
	528	0	08	40
	527	0	02	88
	5.6	0	07	80
	525	0	04	68
	599	0	10	20
	591	0	00	60

[No. O-12016/177/91-ONG.D-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2272:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ सं. 3040 तारीख 20-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों म उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी सी एस से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य . —गुजरात जिला अहमदाबाद तालुका . —दसक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
सिंगरवा	133/2	0	06	00
	127	0	42	30
	124/3	0	14	40
	124/2	0	10	50
	124/1	0	06	60
	123	0	06	15
	101/1	0	06	00
	102	0	30	60
	98	0	12	00
	97	0	12	60

[सं. ओ.-11027/144/89-ओ एन जी डी-III/IV]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2272.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3040 dated 20-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE
PIPELINE FROM RAMOL GCS TO TELIANCEX INDUSTRIES
State : Gujarat Dist : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Singarva	133/2	0	06	00
	127	0	42	30
	124/3	0	14	40
	124/?	0	10	50
	124/1	0	06	60
	123	0	06	15
	101/1	0	06	00
	102	0	30	60
	98	0	12	00
	97	0	12	60

[No. O-11027/144/89-ONGD .III/IV]
.MARMTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ.सं. 2273.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3854 तारीख 5-12-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कानजीसन-1 से कलोल-126 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : —गुजरात तालुका :—कड़ी जिला : —मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
घुमासन	670		18	30
	669	0	03	00
	671	0	18	90
	666	0	12	00
	733	0	04	50
	720	0	15	00
	721	0	38	00
	722	0	07	80
	114	0	14	80
	113/2	0	04	50
	104/1	0	12	00
	106	0	06	40
	97	0	04	50
	96	0	05	40
	कार्ट ट्रेक	0	95	90
	95/5	0	06	00
	134	0	12	15
	175	0	12	30

[सं. ओ.—11027/160/89—ओ एन जी डी-III/IV]
एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

2066 GI/92—4

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2273.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3854 dated 5-12-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Kanjisan 1 to Kalol - 126

State : Gujarat Taluka : Kadi Distt : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ghumasan	670	0	18	30
	660	0	03	00
	671	0	18	90
	666	0	12	00
	733	0	04	50
	720	0	15	00
	727	0	81	00
	722	0	07	80
	114	0	14	80
	113/2	0	04	50
	104/1	0	12	00
	106	0	05	40
	97	0	04	50
	96	0	05	40
	Cart track	0	00	90
	95/5	0	06	00
	134	0	12	15
	175	0	12	30

[No. O-11027/160/89-ONGD-III/IV]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2274 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 587 तारीख 2-2-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं. 15 से एस.आईपी-34 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : —गुजरात जिला : — मेहसाना तालुका : —कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
हाजीपुर	615/P / 1/ए	0	07	50

[सं. ओ.-11027/22/90/ओ एन जी डी-[II/IV]
एम. मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2274.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 587 dated 2-2-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL No. 15 TO SIP 34

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Hajipur	615/1 / 1/A	0	07	50

[No. O-11027/22/90/ONGD.II(I)V]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2275.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 973 तारीख 15-3-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

टी.पी. रणासण से रामोल जी.जी.एस. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : —गुजरात जिला : —अहमदाबाद ता. : —दसक्रोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
लुवलडी	739	0	13	40
	740	0	11	60
	741	0	11	20
	742	0	02	60
	743	0	08	40
	744	0	12	00
	745	0	33	00
	रोड़	0	04	20
	684	0	10	00
	687	0	14	40
	664	0	14	40
	688	0	16	00
	689	0	02	00
	690/1	0	15	00
	690/2	0	06	00
	690/3	0	15	00
	कार्ट ट्रेक	0	04	00
	620	0	18	00
	589/1	0	10	80
	589/2	0	06	00
	589/3	0	18	00
	592	0	04	60

1	2	3	4	5
	591	0	06	20
	593	0	01	00
	586	0	19	00
	577	0	19	00
	585	0	08	00
	578	0	08	00
	532	0	08	40
	531	0	03	10
	535	0	17	00
	530	0	01	00
	529	0	16	00
	526	0	28	00
	525	0	08	00

[सं. ओ.-11027/157/90-ओ एन जीडी-III/IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2275.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 973 dated 15-3-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government directed its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM T.P. RANASAN TO RAMOL GGS

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bhuwaldi	739	0	13	40
	740	0	11	60
	741	0	11	20
	742	0	02	60
	743	0	08	40
	744	0	12	00
	745	0	33	00
	Road	0	04	20
	684	0	10	00
	687	0	14	40
	664	0	14	40
	688	0	16	00
	689	0	02	00
	690/1	0	15	00
	690/2	0	06	00
	690/3	0	15	00
	Cart track	0	04	00
	620	0	18	00
	589/1	0	10	80
	589/2	0	06	00
	589/3	0	18	00
	592	0	04	60
	591	0	06	20
	593	0	01	00
	586	0	19	00
	577	0	19	00
	585	0	08	00
	578	0	08	00
	532	0	08	40
	531	0	03	02
	535	0	17	10
	530	0	01	00
	529	0	16	00
	526	0	28	00
	525	0	08	00

[No. O-11027/157/90-ONGD-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2276.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3033 तारीख 20-11-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रामोल जी.सी.एस से रिलायन्स उद्योग तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
गतराड	173	0	01	50
	174	0	27	15
	175	0	15	00

[सं. ओ.-11027/145/89/ओ एन जी डी-III/IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2276.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3033 dated 20-11-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM AMOL GGS TO RELIANCE INDUSTRIES

State : Gujarat Distt : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Aentriare
Gat ad	173	0	01	50
	174	0	27	15
	175	0	05	00

[No. O-11027/145/89-ONGD-III-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 2277.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3133 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी पी से धाधर नदी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
गंधार	322/ए/बी	0	91	65

[सं. ओ-11027/114/90/ओ एन जी डी-III/IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1992

S.O. 2277.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3733 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WWTP TO DHADHAR RIVER

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Gandhar	322/A/B	0	91	65

[No. O-11027/114/90-ONGD-III/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1992

का.आ. 2278.—केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्यांक 4709 से 4711 एवं 4713 से 4718 में प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) की अधिसूचनाएं का.आ. 2810 एवं 2811, तारीख 3 नवम्बर, 1990 द्वारा इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने के उनके आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में टंकण और मुद्रण प्रकृति की कतिपय गलतियां हुई हैं;

अत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :

पृष्ठ संख्या 4709 — अकलिया गांव के किला संख्या 74/2 के सामने स्तम्भ 6 के नीचे "रिक्त" के स्थान पर "39" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4710. — अकलिया गाव के किला संख्या 100/7/1 के सामने स्तम्भ 5 नीचे "9" के स्थान पर "6" पढ़ें ।

किला संख्या 130/21 के सामने स्तम्भ 5 के नीचे "12" के स्थान पर "53" पढ़े ।

स्तम्भ 2 के नीचे किला संख्या "285" के स्थान पर "385" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4713 — सहूल गांव के स्तम्भ 2 के नीचे किला संख्या "22/16" के स्थान पर "22/15" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4714: — मतीवाला गांव के स्तम्भ 2 के नीचे किला संख्या "9/1" के स्थान पर "9/19" पढ़ें ।

यथा संशोधित किला संख्या 9/19 के सामने स्तम्भ 4 के नीचे "12" के स्थान पर "–" पढ़ें ।

समूशन गाव के स्तम्भ 2 के नीचे किला संख्या "16/1" के स्थान पर "16/4" पढ़ें ।

स्तम्भ 2 के नीचे किला संख्या "11/12" के स्थान पर "11/2" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4715: — कमलपुर गाव के स्तम्भ 2 के नीचे किला संख्या 120/3 के स्थान पर "120/2" पढ़ें ।

स्तम्भ 1 के नीचे गांव के नाम "खनालकन" के स्थान पर "खनालकला" पढ़ें ।

यथा संशोधित गांव "खनालकला" के किला संख्या 50/5 के सामने स्तम्भ 6 के नीचे "70" के स्थान पर "78" पढ़ें ।

किला संख्या 51/18/2 के सामने स्तम्भ 5 एवं 6 के नीचे "4" एवं "67" के स्थान पर क्रमश: "5" एवं "57" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4717 — गोबिन्दपुर नगरी गांव के स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "14/16/1" के स्थान पर "41/16/1" पढ़ें ।

स्तम्भ 1 के नीचे गांव के नाम "मेहृता" के स्थान पर "मेहूना" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4718 — यथा संशोधित मेहूना गाव के किला संख्या "58/24" के सामने स्तम्भ 6 के नीचे "771" के स्थान पर "77" पढ़ें ।

ऐसी भूमि में जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के इक्कीस दिन के भीतर उक्त भूमि के संपूर्ण या किसी भाग के, या उक्त ऐसी भूमि में या इस पर किसी अधिकार के अर्जित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के निर्बन्धनों के अनुसार आक्षेप कर सकेगा;

स्पष्टीकरण : केवल इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित गांव के नाम, किला संख्या व क्षेत्रफल की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के निबन्धनों के अनुसार, इक्कीस दिन की उक्त अवधि अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से प्रारम्भ होगी ।

[संख्या : आर-31015/1/90-ओ आर.-1 भाग ए-]
कुलदीप सिंह, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th July, 1992

S.O. 2278.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum and Natural Gas) No. S.O. 2810 and 2811 dated the 3rd November, 1990, published in the Gazette of India, Part II, Sect on 3, Sub-section (ii), at page 4711 to 4713 and 4718 to 4723, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisit on of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that not fication;

Andwhereas, it has been brought to the notice of the Central Government that cer'a'n errors of printing nature have occured in the publication of the said notifications in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sect'on (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows :

at page 4711, in the Schedule, in column 6, for "Centi Area" read "Centi Are";

at page 4712, in village Aklia, against killa no. (72)|10, in column 6, insert "63", against kill no. (98)|25|2, in column 6, for "33" read "63";

at page 4718, in the Schedule, in column 6, for Centi Area' read Canti Are';

at page 4719, in village Manshiwala, against killa no. 10|25, in column 6, for "58" read "53";

at page 4721, in v llage Khanal Kalan, against killa no. 118|19, in column 6, for '70" read "90", against killa no. 118|24, in column 6, for "00" read "90", in column 3, for killa no. "130|7" read "130|9", against killa no. 130|14, in column 6, for "27" read "29" aga nst killa no. 144|24, in column 5, for "4" read "9".

Any person interested in any land in respect of which the above amendment has been issued, may within twenty one days of the issue of this notification, object to the acquisit on of the whole or any part of the said land or any right in or over such land in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act.

EXPLANATION :

In respect of the lands, killa numbers and area amended through this notification only, the said period of twenty one days n terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act starts running from the date the copies of this notification are made available to the public after its publication in the official Gazette.

[No. R-31015/1/90-OR. I (Pt. A)]
KULDIP SINGH, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1992

का.आ. 2279 —केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा 1 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्यांक 1395 से 1400, 1424 से 1434, एवं 1444 से 1451 में प्रकाशित भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) की अधिसूचनाएं का.आ. 833, 835 एवं 846, तारीख 23 मार्च, 1991 द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में टंकण और मुद्रण प्रकृति की कतिपय गलतियां हुई हैं

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :

पृष्ठ संख्या 1385	अरायन कला गांव के स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "108/34)" के स्थान पर "108 34" पढ़े ।
	स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "109/25/3" के स्थान पर "109/25/2" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1396	अनपान कला गांव के किला संख्या 123/14/2 के सामने स्तम्भ 6 नीचे "7" के स्थान पर '57" पढ़े ।
	स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या '13/43" के स्थान 13/1, 3 पढ़े ।
	स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या 43/35" स्थान पर '43/25" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1399 :	फग्गो कला गांव के स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "335/1" के स्थान पर "355/1' पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1400 :	फग्गो कला गांव के किला संख्या "360/2' के सामने स्तम्भ 5 एवं 6 के नीचे "03' एवं "0" के स्थान पर क्रमशः "01" एवं "01" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1425 :	चाऊ के गांव के किला संख्या "212/25/1" के सामने स्तम्भ "5" के नीचे "1" के स्थान पर "4" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1428 :	खोखर गांव के स्तम्भ "3' के नीचे किला संख्या "767/2" के स्थान पर "767/1" पढ़े ।
	ढड्डे गांव के स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "159/6" के स्थान पर "159/1" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1439 :	ढड्डे गांव के स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "898/1" के स्थान पर "898/1/1" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1449 :	भुंगवानी गांव के स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या "207/29/1" के स्थान पर "207/19/1" पढ़ें ।
पृष्ठ संख्या 1450 :	भुंगवानी गांव के किला संख्या 230/5 के सामने स्तम्भ 6 के नीचे "31" के स्थान पर '39" पढ़े ।
	किला संख्या 231/4 के सामने स्तम्भ 6 के नीचे "32" के स्थान पर "51" पढ़े ।
	गुलाब गढ़ गांव के किला संख्या "26/10" के सामने स्तम्भ "5" एवं "6" के नीचे "15" एवं "62" के स्थान पर क्रमशः "12" एवं "65" पढ़े ।
पृष्ठ संख्या 1451	कुम मण्डी गांव के किला संख्या 212 के सामने स्तम्भ "5" के नीचे "25" के स्थान पर "22" पढ़े ।

ऐसा भूमि में जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के इक्कीस दिन के भीतर उस भूमि के संपूर्ण या किसी भाग के, या उसमें ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकार के अर्जित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के निबंधनों के अनुसार आक्षेप कर सकेगा :

स्पष्टीकरण :—केवल इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित गांव के नाम, किला संख्या व क्षेत्रफल की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के निबन्धनों के अनुसार, इक्कीस दिन की उक्त अवधि अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से प्रारम्भ होगी ।

[संख्या आर-31015/1/90-ओ आर-1 (भाग ए)]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th July, 1992

S.O. 2279.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and No. S.O. 832, 833, 834, 835 and 836, dated the 23rd No. S. O. 832, 833, 834, 835 and 836, dated the 23rd March, 1991, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), at pages 1378 to 1395, 1400 to 1406, 1415 to 1424, 1434 to 1444 and 1451 to 1459 issued under sub-section (1) of section 3 of the Patroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occured in the publication of the said notifications in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the schedule appended to the said notifications as follows:

- at page 1378, in Schedule, in column 6, for Centi Area' read "Centi Are";
- at page 1383, in village Upli, against Survey No. 2086, in column 5, for '05' read '07', in column 6, for '06' read '33', in column 3, for survey no. '2140' read '2143';
- at page 1384, in village Ubewal, against survey no. 126|23, in column 6, for '41' read '51';
- at page 1389, in village Longowal, in column 3, for survey no. 260|1|8 read 260|18|1;
- at page 1390, in village Longowal, in column 3, for survey no. '257|11|2' read '267|11|2', against so amended survey no. 267|14, in column 5, for '02' read '05', against survey no. 267|15 in column 5, for '05' read '02' against survey no. 289|1, in column 5, for the sign '—' read '12';
- at page 1391, in village Longowal, in column 3, for survey no. 308|9 read '308|5';
- at page 1401, in village Aspal Kalan, against survey no. 123|13, in column 6, for '98' read '89';
- at page 1402, in village Aspal Kalan, in column 3, for survey no. 124|17|1' read '124|19|1';
- at page 1403, in village Kot Duna, in column 3, for survey no. 52|4|2' read '52|13|2';
- at page 1404, in village Bhani Fatcha, in column 3, for survey no. '678' read '768', against survey no. 2399, in column 6, for '65' read '56';
- at page 1415, in the Schedule, in column 6, for Canti Area' read 'Centi Are';
- at page 1434, in the Schedule, in column 6 for 'Centi Area' read 'Centi Are';
- at page 1436, in village Chauke, against survey no. 230|4, in column 6, for '12' read '11';
- at page 1438, in village Khokhar, against survey no. 855|2, in column 5, for '25' read '05', in village Dhadde, against survey no. 166|1|1, in column 6, for '53' read '52';

at page 1439, in village Dhadde, for survey no. '604|3' read '604|2';

at page 1440, in line 1, in column 1, the figure and the words "2. Khokhar' and in column 2, the figure "1" shall be omitted;

at page 1443, in village Jhanduke, against survey no. 89|2|1, in column 6, for '43' read '53';

at page 1451, in the Schedule, in column 1, for 'Chak Wala, read 'Chak Ram Singh Wala', n column 2, the words 'Ram Singh' shall be omitted;

at page 1452, in village Chak Ram Singh Wala, for survey no. '66|13|2' read '66|13'1', for survey no. '67/1/6' read '67,6', for survey no. '66/11' appearing after survey no. 67|15, read '68|11';

at page 1453, in village Chak Fatha Singh Wala, for survey no. '144|116' read '144|16';

at page 1454, in village Chak Fatha Singh Wala, for Survey no. '144|20|12' read '144 20|2';

at page 1455, in village Tungwali, for survey no. '139/21 2/1' read '199/21/2/1';

Any person interested in any land in respect of which the above amendement has been issued, may within twenty one days of the issue of this notification, object to the acquisit on of the whole or any part of the said land or any right in or over such land in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act.

EXPLANATION :

In respect of the lands, killa numbers and area amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act starts running from the date the copies of this notification are made available to the public after its publication in the Official Gazette.

[No. R-31015/1/90-ORI (Pt. A)]
KULDIP SINGH, Under Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1992

का.आ. 2280.—राष्ट्रपति, पवनहंस लिमिटेड के आपस एवं संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद 38(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बृजेश कुमार, संयुक्त सचिव, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय को, श्री ए.एम. भारद्वाज, संयुक्त सचिव नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के स्थान पर, जिनकी नियुक्ति इस मंत्रालय के दिनांक 15-3-91 की अधिसूचना संख्या ए वी-13015/81/88-ए सी. (बी एल) के द्वारा अधिसूचित की गई थी, तत्काल से और 16 जनवरी, 1994 तक, पवनहंस लिमिटेड के बोर्ड में पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त करते है।

[संख्या एवी-13015/81/88-ए सी बी एल]
एम भट्टाचार्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

New Delhi, the 4th August, 1992

S.O. 2280.—In exercise of the powers conferred by Article Article 38(a) of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Limited, the President is pleased to appoint Shri Brijesh Kumar, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation and Tourism as Ex-Officio Director on the Board of Pawan Hans Limited with immediate effect and until 16th January, 1994, vice Shri A. M. Bhardwaj, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation and Tourism whose appointment was earlier notified vide this Ministry's Notification No. Av. 13015|81|88-ACVL, dated the 15th March, 1991.

[No. Av. 13015/81/88-ACVL]
M. BHATTACHARJEE, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का.आ. 2281.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टी.वी. मन्टोनेन्स सेन्टर, श्रीगंगानगर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-42011/36/87-डी-II (बी) (भाग/)]
के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st July, 1992

S.O. 2281.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of T.V. Maintenance Centre, Sriganganagar and their workmen, which was received by the Central Government on 16-7-92.

[No. L-42011/36/87-D.II(B)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 55/1988

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-42011/36/87—डी-II (बी) दिनांक 22-7-88

श्री शिव कुमार पुत्र श्री फतेह चन्द व श्री राम अवतार पुत्र श्री चान्द राम, मार्फत महामंत्री भारतीय मजदूर संघ कार्यालय जे. सी. टी. मिल्स के सामने, श्रीगंगानगर।

—प्रार्थीगण

बनाम

अभियन्ता, टी. वी. मन्टोनेन्स सैन्टर, वाटर वर्क्स कालोनी, श्रीगंगानगर। अप्रार्थी

उपस्थित

संघ की ओर से : श्री जयवीर सिंह यादव

अप्रार्थी की ओर से

दिनांक अवार्ड 9-4-1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय, अन्तर्गत धारा 10(1)(घ), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रेषित किया है :

"क्या टी. वी. अनुरक्षण विभाग के प्रबन्धतंत्र की श्री शिवकुमार तथा श्री राम अवतार की 3-11-86 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है। यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का तथा किस तारीख से पाने का हकदार है।"

2. महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, श्रीगंगानगर, जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम

प्रकट किया कि सर्वश्री शिव कुमार व राम अवतार श्रमिकगण जनवरी 1984 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में अप्रार्थी द्वारा नियोजित किये गये थे। श्रमिकों द्वारा लगातार व बिना किसी व्यवधान के कार्य करने के कारण तथा उनकी लगन मेहनत व ईमानदारी को देखते हुए अप्रार्थी ने विभागीय कार्यवाही जैसे मैडीकल व शिक्षा आदि की औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत 8-9-84 से उन्हें वर्कचार्ज गार्ड बनाने के आदेश प्रसारित कर दिये। उक्त श्रमिकों ने 31-1-86 तक बिना किसी व्यवधान के प्रतिवादी के पास कार्य किया है। तत्पश्चात् 1-2-86 को जबानी आदेश देकर इन श्रमिकों की सेवा मुक्त कर दिया। प्रार्थी संघ का कथन है कि 1 जनवरी, 1984 से 31-1-86 तक इन श्रमिकों ने पूर्ण लगन, मेहनत व ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम दी थी। इनके कार्य व ड्यूटी बाबत कोई शिकायत नहीं थी फिर भी बिना कारण बताये गैर कानूनी तरीके से उनकी सेवाएं निरस्त कर दी। यह भी कहा है कि प्रत्येक श्रमिक ने सेवा मुक्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक लगातार सेवा कर ली थी फिर भी उन्हें धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया और न ही किसी दुराचरण के आधार पर उनकी सेवा मुक्ति की गई है इसलिए 1-2-86 के जुबानी आदेश द्वारा की गई सेवा मुक्ति निरस्त की जाये और श्रमिकगण को सवेतन पुनः सेवा में लिया जाये।

3. अप्रार्थी ने जरिये प्रत्युत्तर प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की है कि दूरदर्शन का संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनता में ज्ञान वितरित करने के उद्देश्य से किया जाता है जिसका बजट भी संचित निधि से आबंटित होता है। दूरदर्शन के कर्मचारियों पर संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये नियम लागू होते हैं इसलिए अप्रार्थी संस्थान उद्योग नहीं है और न ही इस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रार्थी संघ के लिए भी कहा गया है कि यह मान्यता प्राप्त नहीं है और इसके द्वारा स्पोंसर्ड किया हुआ विवाद चलने योग्य नहीं है। गुणावगुण पर अप्रार्थी का कथन है कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री ओ.पी. जैन ने वादीगण को अपने आदेश दिनांक 8-9-84 के द्वारा दो माह की अवधि के लिए 3-9-84 से तदर्थ आधार पर 196-3-222 के वेतनमान में सुरक्षापाल के पद पर नियुक्त किया था। उक्त अधिकारी ने इस विषय में जारी सरकारी आदेशों व नियमों की प्रक्रिया नहीं अपनाई और न ही सुरक्षापाल का कोई पद था इसलिए उक्त नियुक्तियां अवैध थी। यह भी कहा है कि उक्त नियुक्तिया अस्थाई अवधि के लिए थी जो 2-11-84 को अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही समाप्त हो गई। तत्पश्चात् जुबानी आदेश देकर इन श्रमिकों को उक्त श्री ओ.पी. जैन ने ही 3-11-84 से 15-11-84 तक काम पर लगाये रखा फिर हटा दिया। 15-11-84 के बाद एक भी दिन श्रमिकों को नहीं रखा गया। 15-11-84 से 31-1-86 तक नियोजित रखना सरासर गलत व झूठ है। इन श्रमिकों ने लिखित आदेश द्वारा 61 दिन और मौखिक आदेश द्वारा 13 दिन कुल 74 दिवस ही सेवा की है। इसलिए नोटिस या छंटनी या मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

4. अप्रार्थी का यह भी कथन है कि 3-11-84 से 15-11-84 तक 13 दिवस की अवधि का वेतन श्रमिकों को नहीं दिया गया था क्योंकि नियोजित करने का कोई लिखित आदेश नहीं था इसलिए उक्त अवधि का वेतन प्राप्त करने हेतु राम अवतार श्रमिक ने एक दावा पी. डब्ल्यू. ए-526/85 दिनांक 23-12-85 को प्रस्तुत किया और शिव कुमार श्रमिक ने भी एक दावा पी. डब्ल्यू. ए. 575/85 23-12-85 को प्रस्तुत किया। उक्त दोनों दावों में भी 15-11-84 तक की अवधि के वेतन तक की ही मांग की गई थी और 15-11-84 तक का ही उन्हें वेतन दिलाया गया था। अगर 15-11-84 के बाद श्रमिकों को नियोजित रखा गया होता तो उस विषय का उल्लेख उपरोक्त दावों में भी होता। नियोजक के अनुसार श्रमिकगण किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं हैं।

5. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिकगण सर्वश्री राम अवतार व शिव कुमार ने अपने-अपने शपथ पत्र पेश किये हैं और अन्हें सत्यापित कराया है जिनमें नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की है। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री जे. पी. जैन ने शपथ पत्र पेश किया है जिससे संघ के प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रालेखिक साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत पी-6 फोटो प्रतियां पेश हुई है। नियोजक की तरफ से एम-1 लगायत एम-3 प्रलेखों की फोटो प्रतिया पेश की गई हैं। तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

6. सर्वप्रथम मैं नियोजक द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों का निपटारा करूंगा। क्लेम के प्रत्युत्तर के अनुसार ही श्री जे. पी. जैन नियोजक साक्षी ने भी अपने शपथ पत्र में कहा है कि जनता के स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु जनहित में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अप्रार्थी संस्थान कायम किया है। इसके स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों पर संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये सेवा नियम लागू होते हैं और इस प्रकार अप्रार्थी संस्थान उद्योग की परिभाषा में नहीं आता। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि अप्रार्थी संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है और इसके कर्मचारी पर अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये सेवा नियम लागू होते हैं तो भी इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अप्रार्थी संस्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(जे) के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेंगलोर वाटर सप्लाई एवं सीवेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा 1978 (2) एस.सी.सी. 213 तथा एस. के. शर्मा बनाम महेश चन्द 1983 (4) एस. सी. सी. 1914 आदि न्याय दृष्टान्तों में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां पर सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो नियोजक अथवा नियोजित के सहयोग से कोई उत्पादन हो रहा हो अथवा किसी प्रकार की सेवा की जा रही हो तो उक्त संस्थान उद्योग की परिभाषा में ही आयेगा चाहे उसमें लाभ की बजाय हानि ही होती हो। उक्त न्याय दृष्टान्त में यह भी उल्लेख कर दिया था कि चाहे कोई विभाग सोवरिन फंक्शन

ही क्यो न करता हो उसमे भी अगर कोई यूनिट उपरोक्त तीनों आवश्यकताएं पूरी करती है तो उद्योग को परिभाषा में आ जायेगी । अतः उपरोक्त समस्त कारणों से नियोजक द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है ।

7. जहां तक प्रार्थी संस्थान द्वारा श्रमिकों का विवाद खड़ा करने का प्रश्न है चाहे अप्रार्थी संस्थान ने प्रार्थी संघ को मान्यता नहीं दी हो तो भी उक्त संघ श्रमिकों को विवाद उठाने मे सक्षम है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वश्री शिव कुमार व राम अवतार को सेवा मुक्ति का विवाद है जो उक्त श्रमिकगण धारा 2-ए के अन्तर्गत स्वयं भी उठा सकते हैं। इस पत्रावली में जो क्लेम प्रस्तुत किया गया है इस पर दोनों श्रमिकों ने भी हस्ताक्षर किए हैं इसलिए अप्रार्थी का यह तर्क भी चलने योग्य नहीं है और खारिज किया जाता है।

8. गुणावगुण पर श्रमिकों का कथन यह है कि उन्होंने जनवरी 1984 से 31-1-86 से बिना व्यवधान के निरंतर सेवा की है। उक्त तथ्यों को अप्रार्थी ने अस्वीकार किया है और कहा है कि 3-9-84 से 15-11-84 तक ही श्रमिकों ने कार्य किया है और प्रत्येक श्रमिक ने 74 दिवस से अधिक कार्य नहीं किया । किस पक्षकार के कथनों में सत्यता है, इस बाबत अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रालेखिक साक्ष्य का निरीक्षण आवश्यक है। श्रमिकगण सर्वश्री शिव कुमार व राम अवतार ने अपने शपथ पत्रों में भी दर्ज किया है कि उन्होंने टी. वी. मेन्टीनैंस सैन्टर श्रीगंगानगर में 1-1-84 को दैनिक वेतनभोगी श्रमिक नियुक्त किया गया था। 1-1-84 से 31-1-85 तक निरंतर व लगातार बिना किसी ब्रेक के उन्होंने ड्यूटी अंजाम दी है । प्रति परीक्षा करने पर शिव कुमार कहता है उसे 31-1-85 को हटाया था 31-1-86 को नहीं हटाया । 31-1-85 तक का वेतन हमें मिल गया । 15-11-84 तक हमने मस्टररौल पर काम किया था। 1-1-84 को भी मस्टररौल पर लगाया गया था । इसी प्रकार राम अवतार श्रमिक भी प्रति परीक्षा में कहता है 3-9-84 से 15-11-84 तक वर्कचार्ज में रखा था, उसके बाद से दैनिक वेतन पर रखा था, 15-11-84 के बाद से सत्य प्रकाश जी ने काम लिया । 31-1-85 के बाद काम नहीं लिया । इन श्रमिकों के उपरोक्त अपुष्ट मौखिक कथनों पर निभर नहीं किया जा सकता क्योंकि क्लेम में तो 31-1-86 तक काम करना बताते है और शपथ पत्र में 31-1-96 तक ही टाईप किया हुआ है जिसे तत्पश्चात हाथ से 31-1-85 किया गया है । अगर वास्तव में इन श्रमिकों से 3-9- 4 से 15-11-84 के पहले या बाद में काम लिया गया था तो उन्होंने उक्त अवधि बाबत अप्रार्थी से संबंधित रिकार्ड क्यों नहीं मंगवाया । किसी भी श्रमिक ने न तो अपने शपथ पत्र में यह दर्ज किया कि 3-9-84 से 15-11-84 के पहले या बाद में किस व्यक्ति ने उनसे कहां पर क्या काम कराया था और न ही नियोजक साक्षी से उक्त विषय में प्रति परीक्षा की गई है । अगर वास्तव में 15-11-84 के उपरांत श्रमिकों ने काम किया था तो 23-12-85 को जो श्रमिकों ने प्राधिकारा वेतन भुगतान श्रीगंगानगर के समक्ष वाद सं. 575/85 व 576/85 प्रस्तुत किए थे उनमें इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रतियां नियोजक पक्ष की ओर से अभिलेख पर पेश की गई हैं जो प्रदर्श एम-1 व एम-2 है । श्रमिक राम अवतार की तरफ से प्रदर्श पी-2 प्रमाण पत्र पेश किया गया है जो ओ. पी. जैन का हस्ताक्षरयुक्त है उसमें 1-11-84 से 15-11-84 तक सेवा करने का उल्लेख श्रमिक राम अवतार अपने शपथ पत्र में दर्ज करता है । उक्त ओ. पी. जैन का तो परीक्षण नहीं कराया गया तथा पी-2 प्रमाण पत्र में भी 1-4-84 में संख्या 4 पर ओवर राईटिंग हो रही है संभवतः यह 1-11-84 था जिसे 1.4 बनाया गया है, मेरी उक्त धारणा की पुष्टि इसलिए भी होती है क्योंकि नियोजक साक्षी श्री जे. पी. जैन ने अपने शपथ पत्र में ही यह दर्ज कर दिया है कि 1-11-84 से 15-11-84 तक सर्वश्री शिव कुमार व राम अवतार को नियोजित रखा गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रदर्श पी-2 पर निभर नहीं किया जा सकता ।

9. हालांकि क्लेम के प्रत्युत्तर में तो नियोजक ने यह कहा है कि उसके यहां इन श्रमिकों ने 74 दिवस से अधिक सेवा नहीं की। परन्तु नियोजक साक्षी श्री जैन अपने शपथ पत्र की चरण सं. 12 में यह स्वीकार करते है कि 16-11-84 से 30-11-84 तक शिव कुमार ने 13 दिन व राम अवतार ने 14 दिन सेवा की है। 1-12-84 से 15-12-84 तक राम अवतार ने 13 दिवस सेवा की है । 16-12-84 से 31-12-84 तक राम अवतार ने 14 दिन सेवा की है । 24-12 84 से 31-12-84 तक शिव कुमार ने 6 दिन सेवा की है । 1-1-85 से 9-1-85 तक राम अवतार ने 8 दिन सेवा की है। इसी प्रकार शिव कुमार ने 3-9-84 से 15-9-84 तक जो 74 दिन सेवा की थी उसके अलावा 19 दिवस और सेवा की है तथा उसकी कुल सेवा 93 दिवस ही बनती है और राम अवतार ने भी 3-9-84 से 15-11-84 तक 74 दिन सेवा के उपरांत 49 दिवस और सेवा की है और उसने भी कुल सेवा 123 दिवस ही की है । नियोजक साक्षी यह भी कहता है कि शिव कुमार ने संस्थापन अधिकारी के पास 26-3-84 से 31-7-84 तक 34 दिवस काम किया । उक्त अर्से का भी अगर शिव कुमार को लाभ दिया जावे तो कुल 127 दिवस ही सेवा बनती है । हालांकि नियोजक के अनुसार दूरदर्शन केन्द्र पर तो 74 दिवस ही सेवा की गई है । दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र पर शिव कुमार ने 19 दिन तथा राम अवतार ने 49 दिवस सेवा की है तथा दूरदर्शन के संस्थापन अधिकारी के पास शिव कुमार ने 34 दिन सेवा की है। तीनों सेवाओं का मिलान करने पर भी राम अवतार की 123 और शिव कुमार की 127 दिवस ही बनते हैं। अभिप्राय यह है कि 240 दिवस की सेवा नहीं बनती अतः धारा 25-एफ के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते । प्रार्थी संघ की तरफ से धारा 25-एफ के प्रावधानों का ही उल्लेख किया गया है धारा 25-जी और 25-एच बाबत न तो रैफरेंस ही प्राप्त हुआ है और न ही क्लेम में उक्त तथ्यों का उल्लेख है इसलिए धारा 25-जी

और 25-एच बाबत पक्षकारों की साक्ष्य भी नहीं आई है। धारा 25-एफ साबित नहीं होने से ये श्रमिकगण किसी अनुतोष के अधिकारी नही है और इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"श्रमिकगण सर्वश्री राम अवतार व शिव कुमार की सेवा मुक्ति करना उचित एवं वैध है और ये कर्मकार किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं है।"

10. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के पढ़ाई जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 21 जुलाई 1992

का. आ. 2282.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिवीजनल इंजीनियर (टेलीग्राम) सवाईमाधोपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/76/89-आई-आर (डीयू) (पार्ट)]

के. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1992

S.O. 2282.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Eng. (Telegraphs) Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on 16-7-92.

[No. L-40012/76/89-IR(DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रिय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी० आई० टी० 6/90

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या :

एल 40011/76/89 आईआर (डीयू) दि. 15-1-90

जगराम पुत्र श्री रामफूल माली, गांव कुनकाटा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

बनाम

डिवीजनल इंजीनियर (टेलीग्राफ) सवाईमाधोपुर।

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर.एच.जे.एस.

श्रमिक पक्ष की ओर से : श्री कानसिंह राठौड

नियोजक पक्ष की ओर से : श्री एन. सी. चौधरी

दिनांक अवार्ड : 25-5-92

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय अपनी अधिसूचना सं.एल. 40012/76/89 आईआर (डीयू) दि. 15-1-90 के धारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है—

"Whether the action of the Divisional Engineer (Telegraph) Swai Modhopur in terminating the services of Shri Jagram Mali S/o Shri Ramphool Mali w.e.f. 1-8-87 is justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. प्रार्थी जगराम जिसे तत्पश्चात् श्रमिक संघ संबोधित किया गया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति विपक्षी संस्थान में हैल्पर के पद पर दिनांक 1-12-86 को 13रु. प्रतिदिन की दर से मस्ट्रोल पर केजुअल लेबर के रूप में की गई थी। तभी से वह निरंतर मेहनत व ईमानदारी से कार्य करता आ रहा था फिर भी विपक्षी संस्थान ने मौखिक आदेश द्वारा दिनांक 1-8-87 से सेवा से पृथक् कर दिया। श्रमिक कहता है उसने अलग करने के बाद से विपक्षी संस्थान से कई बार संपर्क करके कार्य पर लेने बाबत निवेदन किया लेकिन सुनवाई नहीं की गई फलस्वरूप समझौता अधिकारी के यहां विवाद खड़ा किया गया जहां पर भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए यह निर्देश अधिनिर्णय हेतु यहां पठाया है।

3. श्रमिक का कहना है कि उसने 1-8-87 को समाप्त हुए एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया फिर भी उसे धारा 25एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया अर्थात् न तो नोटिस दिया और न ही छटनी भत्ता यहां तक कि छंटनी से पूर्व वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की गई तथा कथित सेवा मुक्ति अगर दुराचरण के आधार पर की गई होती तो उसे आरोप पत्र देकर नियमानुसार घरेलू जांच करवाई होती। सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्यरत थे। तथा सेवा मुक्ति के उपरांत भी नये व्यक्तियों को नियोजित किया गया और इस प्रकार धारा 25जी और 25एच का भी उल्लंघन किया है। श्रमिक का कहना है कि वह सेवा मुक्ति के उपरांत से बेरोजगार बैठा है इसलिए उसे सवेतन सेवा में बहाल किया जाये।

4. अप्रार्थी ने जरिये प्रतिउत्तर यह तो स्वीकार किया कि श्रमिक को 1-12-86 को केजुअल लेबर के रूप में टेम्प्रेरी कार्य के लिए रखा गया था और उसे दिनांक 31-7-87 तक कार्य किया है तत्पश्चात् कार्य पर उपस्थित नही हुआ और अपनी इच्छा से ही कार्य छोड़कर चला गया। तत्पश्चात् उसने कभी भी विभाग में न तो व्यक्तिगत संपर्क किया और न ही कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया। नियोजक के अनुसार श्रमिक ने केवल 211 दिवस ही कार्य किया है उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्य नही कर रहा है और न ही इसके पश्चात् किसी व्यक्ति को नियोजित किया गया है। नियोजक के अनुसार श्रमिक धारा 25एफ के लाभ का अधिकारी नहीं है इसलिए उसे न तो नोटिस दिया गया और

न ही छंटनी भत्ता। नियोजक यह भी कहता है कि 31-7-87 के बाद सर्वप्रथम 13-2-89 को ही उसका वकील का रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हुआ है कि उसे अवैध तरीके से सेवा मुक्त किया है। नियोजक के अनुसार अप्रार्थी का क्षेत्राधिकार सहायक श्रम आयुक्त कोटा है न कि अजमेर इसलिए रेफरैंस कानूनी गलत है।

5. अपने कथनों के समर्थन मे श्रमिक जगराम ने स्वयं का शपथ पेश कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री केशरसिंह ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की। प्रलेखिक साक्ष्य मे डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-6 फोटो प्रति पेश की तत्पश्चात् मैने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों को विस्तारपूर्वक सुना।

6. जहां तक नियोजक की प्राथमिक आपत्ति का प्रश्न है कि उनकी सस्थान सहायक श्रम आयुक्त कोटा के क्षेत्राधिकार में आता है न कि अजमेर के। इस विषय में नियोजक साक्षी केशरसिंह ने अपने शपथपत्र में नाममात्र का भी कथन नही किया और न ही श्रमिक जगराम से उक्त विषय की प्रतिपरीक्षा की गई है। श्रमिक की तरफ से जो असफल वार्ता प्रतिवेदन डब्ल्यू-6 पेश हुआ है उसके अनुसार सहायक श्रम आयुक्त कोटा द्वारा ही समझौता वार्ता प्रारम्भ की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने इसी न्यायालय में यह निर्देश न्याय निर्णयन हेतु पाया है और यह न्यायालय केन्द्रीय औद्योगिक विवाद हेतु पूरे राजस्थान राज्य का क्षेत्राधिकार रखता है इसलिए अप्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति निराधार मानते हुए अपास्त की जाती है।

7. गुणावगुण पर क्लेम के अनुसार ही श्रमिक जगराम ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उसने 1-12-86 से 31-7-87 तक अप्रार्थी की लगातार सेवा की है और 240 दिवस से अधिक कार्य किया है प्रतिपरीक्षा में भी उक्त कथनों को ही दोहराया है। क्लेम के प्रतिउत्तर मे भी नियोजक ने स्वीकार किया है कि श्रमिक ने 1-12-86 से 31-7-87 तक कार्य किया है और 211 दिवस ही कार्य किया है। नियोजक के अनुसार इस श्रमिक ने दिसम्बर 86 में 27 दिन, जनवरी 87 में 27 दिवस, फरवरी 87 में 24 दिन, मार्च में 27 दिन, अप्रैल में 26 दिन, मई में 29 जिन, जून मे 26 और जुलाई में 27 दिन कार्य किया है जो कुल 211 दिवस बनते है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियोजक ने श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं दिया जो जोड़ने से 243 दिन बनते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्कमैन आफ अमेरिकन एक्सप्रेस के न्याय दृष्टान्त मे 1985(2)एल.एल.एन 817 में यह व्यवस्था दी है कि —

"The expression actually worked under the employer" must necessarily comprehend all those days during which the workman was in the employment of the employer and for which he had been paid wages either under express or implied contract of service or by computation of days etc. sundays and other paid holidays to be treated as days "actually worked under the employer".

उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के अनुसार साप्ताहिक अवकाश का लाभ देने पर इस श्रमिक ने 1-12-86 से 31-12-87 तक 243 दिवस कार्य कर लिया था और इसकी छंटनी धारा 25एफ प्रावधानों के विपरीत करने से उक्त सेवा मुक्ति स्वतः ही अनुचित एवं अवैध तथा शून्य हो गई है।

8. श्रमिक ने क्लेम में यह दर्ज किया है कि सेवा मुक्ति के समय वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्यरत थे और सेवा मुक्ति के उपरांत नये व्यक्तियों को नियोजित किया गया तथा उसे सूचना तक नहीं दी गई। उक्त तथ्यों को भी नियोजक ने क्लेम के जबाब में अस्वीकार किया है। श्रमिक से अपेक्षा थी कि वह उन कनिष्ठ व्यक्तियों के नाम क्लेम में दर्ज करता जो उस समय कार्यरत थे और यथा सम्भव उन व्यक्तियों के भी नाम दर्ज करता जो उसकी सेवा मुक्ति के उपरांत नियोजित किये गये थे। अपने शपथ पत्र में भी श्रमिक उक्त व्यक्तियों के नाम प्रकट नहीं करता है। प्रतिपरीक्षा में कहता है कि दिनांक 31-7-87 को बुधराम, श्री किशन और प्रभु उससे कनिष्ठ थे और निकालने के बाद सतपाल, अख्तर वगैराह को रखा है। नियोजक साक्षी केशर सिंह प्रतिपरीक्षा में कहता है कि अख्तर, कालूराम, संतपाल, शिवप्रकाश, जवाहरलाल आदि जगराम से कनिष्ठ नहीं थे इस प्रकार श्रमिक की अपुष्ट साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्यरत हों। स्वीकृत रूप से सेवा मुक्ति के समय श्रमिक जैसे ही मस्ट्रोल पर दैनिक वेतन पर नियोजित कैजुअल आकस्मिक श्रमिकों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई। जिस तथ्य को नियोजक साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनरल मैनेजर, नोर्दन रेलवे बनाम सी.आई.टी., 1991(2) एल.एल.एन 224 तथा पटना उच्च न्यायालय ने गिरधर गोपाल तिवाडी बनाम भारत सरकार 1992(1)एल एल.एन. पेज 654 के न्याय दृष्टान्तो में भी स्पष्ट कर दिया है कि छंटनी से पूर्व वरिष्ठता सूची बनाना आज्ञापक है चाहे श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस की सेवा अवधि पूरी नहीं की हो। विवेचनाधीन विवाद में तो श्रमिक ने 240 दिवस की सेवा अवधि भी पूरी करली थी इसलिए नियोजक ने धारा 25जी तथा नियम–77 की भी अवहेलना की है।

9. क्लेम के प्रतिउत्तर में नियोजक का कथन यह था कि दिनांक 31–7–87 से श्रमिक स्वेच्छा से काम पर आना बंद कर दिया। हालांकि श्रमिक ने उक्त कथनों को अस्वीकार किया है। और अपनी प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि उससे श्री लक्ष्मण सिंह एस.डी.ओ.टी. ने कहा है कि काम नहीं है बाद में बुला लगे फिर भी नियोजक की तरफ से ही लक्ष्मण सिंह एस डी ओ टी का परीक्षण नहीं कराया और न ही नियोजक साक्षी केशर सिंह ने उक्त तथ्यों का अपने

शपथ पत्र में प्रतिवाद किया। इन परिस्थितियों में नियोजक का यह कथन भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं है कि श्रमिक स्वेच्छा से काम छोड़कर चला गया हो। तर्क के लिए यह मान भी ले कि श्रमिक ने स्वयं से 31-7-87 के बाद से आना बंद कर दिया था और स्वेच्छा से अपना काम त्याग दिया था तो भी यह एक दुराचरण था जिस बाबत नियोजक से अपेक्षायी कि वह श्रमिक पर आरोप लगाकर नियमानुसार घरेलू जॉब कराकर अपने प्रमाणित स्थाई आदेशों के अनुसार दण्ड देता । इस विषय में रोबर्ट डिसूजा का केस 1982(1) एल.एल.एन. 257 का उल्लेख किया जा सकता है । जिसके तथ्य भी विवेचनाधीन विवाद के तथ्यों से मिलते जुलते थे क्योंकि वहां पर भी आकस्मिक श्रमिक गैर हाजिर हो गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि—

> "Absence without leave constitutes Misconduct and it is not open to an employer to terminate services without notice and enquiry or at any rate without complying with the minimum Principles of Natural Justice."

इस विषय में बम्बई उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त 1988 (1) एल.एल.एन. पेज 259, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का 1986 (1)एल.एल.एन. पेज–912 उड़ीसा उच्च न्यायालय 1990(1) एल.एल.एन. 924 के न्याय दृष्टान्तों का भी उल्लेख किया जा सकता है । अतः नियोजक द्वारा उठाई गई आपत्ति प्रत्येक दृष्टिकोण से परखने पर भी आधारहीन पाई जाती है और अपास्त की जाती है ।

10. नियोजक प्रतिनिधि का एक तर्क यह भी था कि यह श्रमिक मस्ट्रोल पर केजुअल लेबर के रूप में टेम्प्रेरी कार्य के लिए रखा गया था। हालांकि क्लेम के प्रतिउत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया कि उपरोक्त टेम्प्रेरी कार्य क्या था और कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था । नियोजक साक्षी केशरसिंह ने भी अपने शपथ पत्र में उपरोक्त कार्य के सीजनल कार्य की व्याख्या नहीं की है कि उक्त कार्य क्या था किस तरीके का शुरू हुआ था और किस तारीख को समाप्त हुआ था और न ही श्रमिक जगराम से इस विषय में प्रति-परीक्षा की गई है तर्क के लिए यह भी मान ले कि श्रमिक को दैनिक वेतन पर मस्ट्रोल पर आकस्मिक सीजनल कार्य के लिए रखा गया था तो भी इससे श्रमिक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के लाभकारी प्रावधानों से वंचित नहीं किया जा सकता । इस विषय में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त 1990 (1) एल.एल.एन. 131 तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त 1990 (2) एल.एल.एन. 714 का उल्लेख किया जा सकता है । अंतिम प्रयास के रूप में नियोजक प्रतिनिधि का तर्क यह था कि 1-8-87 के उपरांत श्रमिक ने सर्वप्रथम 13-2-89 को ही रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा सेवा मुक्ति की आपत्ति की है और विवाद विलम्ब से उठाया गया है । हालांकि श्रमिक ने अपने क्लेम की चरण सं. 3 में ही दर्ज कर दिया था कि उसने सेवा मुक्ति के उपरांत से कई बार व्यक्तिगत सम्पर्क कार्य पर लेने बाबत नियोजक से किया था परन्तु उसकी सुनवाई नहीं की । अपने शपथ पत्र की चरण सं. 4 में भी श्रमिक ने उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है । परन्तु श्रमिक के अपुष्ट कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रमिक ने यह प्रकट नहीं किया कि उसने मौखिक रूप से कब कब और नियोजक के किस अधिकारी को निवेदन किया था । नियोजक साक्षी केशर सिंह से भी इस विषय में प्रतिपरीक्षा में सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये गये हैं । इसलिए श्रमिक द्वारा विवाद विलम्ब से उठाया गया है। हालांकि औद्योगिक विवाद उठाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु अगर विवाद उठाने में श्रमिक की तरफ से कोई विलम्ब हुआ होता है तो उक्त अवधि का वेतन श्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता । श्रमिक से अपेक्षा थी कि 31-7-87 के उपरांत शीघ्रताशीघ्र अथवा छः माह में ही अपना विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष खड़ा करता । इसलिए यह श्रमिक 1 फरवरी 88 से 13 फरवरी 89 तक की अवधि का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

11. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अभिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है कि—

श्रमिक जगराम केजुअल लेबर की 1-8-87 से सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है और इसे इसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है । इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है और इसे 1 फरवरी 88 से 13 फरवरी 89 अवधि तक के वेतन के अलावा शेष अवधि का वेतन दिलाया जाता है । नियोजक से अपेक्षा है कि यह अधिनिर्णय के प्रकाशन के तीन माह के अन्दर श्रमिक को सेवा में लेते हुए उक्त राशि अदा करेगा अन्यथा इस राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा । 100रु. हर्जा खर्चा भी दिलाया जाता है । उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जिसे वास्ते प्रकाशन केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जाये ।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का. आ. 2283—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. (टी) सवाई माधोपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16–7–92 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल–40012/25/88–डी-2(बी) (पार्ट)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1992

S.O. 2283.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO (T) Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on 16-7-92.

[No. I-40012|25|88-D-II(B)(Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर ।

केस नं. सी. आई. टी./124/89

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एल. 40012/25/83-डी-21(बी) दिनांक 2-11-89

अब्दुल सामद खान मार्फत श्री प्रेम कृष्ण शर्मा एडवोकेट, 49, विवेक नगर स्टेशन रोड, जयपुर।

बनाम

एस. डी. ओ. (टी) संचार विभाग, हिण्डोन सिटी सवाईमाधोपुर।

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर. एच. जे. एम.

श्रमिक पक्ष की ओर से : श्री एम. एफ. बेग
नियोजक पक्ष की ओर से श्री एल. सी. चौधरी
दिनांक अवार्ड : 29-5-92

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद उस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय अपनी अधिसूचना सं. एल. 40012/25/88-डी-2(बी) दि. 2-11-89 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 101(10) के अंतर्गत प्रेषित किया है—

"Whether the action of the management of SDO(T), Deptt. of Tele-communiation, Hindaun City, Distt. Sawaimadhopur is justified in terminating the services of Shri Abdul Samad Khan w.e.f. 9-4-85? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. प्रार्थी अब्दुल समद जिसे तत्पश्चात् श्रमिक सम्बोधित किया जायेगा, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसने उपमंडल अधिकारी तार हिण्डोन के यहां वाहन चालक के पद पर दिनांक 3-5-84 से 8-4-85 तक काम किया है और इस प्रकार 327 दिवस तक काम किया था फिर भी उसे अप्रार्थी ने बिना कारण बताये काम से अलग कर दिया। श्रमिक यह भी कहता है कि जिस पद पर वह काम करता था वह स्थाई था और नियोजक के पास उस काम की कमी नही थी। सेवामुक्त करते समय उसे न तो नोटिस दिया अथवा नोटिस की एवज में एक माह का वेतन भी नहीं दिया और न ही छंटनी भत्ता दिया गया है इस प्राकार धारा 25एफ की भी अवहेलना की गई है। सेवा मुक्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची नही बनाई गई तथा सेवामुक्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी कार्यरत थे इसलिए धारा 25जी और नियम-77 का भी उल्लंघन किया है। सेवामुक्ति के उपरांत नई नियुक्तियां काफी तादाद मे की गई थी और उसे सूचना तक भी नहीं दी गई इसलिए धारा 25(एच) का भी उल्लंघन किया है। श्रमिक का कहना है कि सेवामुक्ति की दिनांक से यह बेरोजगार बैठा है इसलिए उसे सवेतन नियोजित किया जाये।

3. अप्रार्थी ने जरिये प्रतिउत्तर यह तो स्वीकार किया कि अब्दुल सामद ने जीप सं. आर. एस. डी. 1727 पर दि. 3-5-84 से 8-4-85 तक दैनिक वेतनभोगी चालक के रूप में 327 दिस काम किया है। पर जीप खराब हो गई तथा कार्य के योग्य नहीं रही इसलिए श्रमिक का दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए कहा गया परन्तु श्रमिक ने दैनिक मजदूरी के पद पर कार्य करने से मना कर दिया और स्वयं कार्य छोड़कर चला गया। नियोजक के अनुसार श्रमिक स्वयं कार्य छोड़कर गया था इसलिए उसे एक माह का नोटिस अथवा उसकी एवज मे एक माह का वेतन देने का औचित्य नहीं था इससे कनिष्ठ व्यक्ति चालक के पद पर कार्यरत नहीं थे और न ही इसकी सेवा मुक्ति के उपरांत किसी चालक को नियुक्त किया गया। सेवामुक्ति के उपरांत सन् 1988 में हिण्डोन उप मंडल में वाहन आर. जे. यू. 8190 उपलब्ध हुई थी उस पर दैनिक मजदूरी चालक के पद पर कार्य लिया है। श्रमिक ने सेवामुक्ति के उपरांत 4-1-87 से 29-1-87 तक वाहन चालक के पद पर दैनिक वेतन पर कार्य किया है। श्रमिक की असावधानी से वाहन सं. आर. एस. डी. 4241 का इंजन गर्म हो गया और काम करना बंद कर दिया। अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिसे सत्यापित किया गया। श्रमिक से नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की तथा प्रलेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-6 प्रलेख की फोटो प्रति पेश की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री हाकिम सिंह ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की। तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

4. क्लेम के प्रति उत्तर में ही नियोजक यह स्वीकार करते है कि 3-5-84 से 8-4-85 तक इस श्रमिक ने 327 दिवस कार्य किया है। इसलिए उच्च स्वीकारोक्ति के आधार पर ही यह तो साबित है कि 9-4-85 को समाप्त हुए एक कलैंडर वर्ष में इस श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक कार्य कर लिया था और यह धारा 25एफ के लाभकारी प्रावधानों का अधिकारी था। निर्विवाद रूप से नियोजक ने न तो श्रमिक को एक माह का नोटिस दिया और न ही नोटिस वेतन दिया यहा तक कि छंटनी भत्ता भी नहीं दिया गया इसलिए धारा 25एफ की अवहेलना हुई है, जिससे सेवामुक्ति स्वतः ही अनुचित एवं अवैध तथा शून्य हो जाती है।

5. श्रमिक का क्लेम में यह भी कथन है कि सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्यरत थे परन्तु उसने

किसी व्यक्ति का नाम न तो क्लेम मे दर्ज किया और न ही अपने शपथ पत्र मे बताया यहा तक कि नियोजक साक्षी श्री हाकिम सिह से भी इस विषय मे प्रतिपरीक्षा नही की गई इसलिए यह साबित नही है कि दिनाक 9–4–85 को श्रमिक से कनिष्ठ कोई वाहन चालक अप्रार्थी की सेवा मे कार्यरत हो । और धारा 25 जी की अवहेलना करना साबित नही होता है ।

6 क्लेम मे श्रमिक का यह भी कथन है कि सेवामुक्ति के उपरात काफी तादाद मे नई नियुक्ति की गई है । शपथ पत्र की चरण स. 5 मे श्रमिक ने दर्ज किया है कि उसे अलग करने के बाद सर्वश्री उमराव सिह, महेश व अशोक को रखा गया था, प्रतिपरीक्षा मे भी श्रमिक कहता है आर एल डी 1727 नम्बर की जीप पर हटाने के बाद अशोक को लगाया है । नियोजक साक्षी श्री हाकिम सिह की अपने शपथ पत्र की चरण स 9 मे स्वीकार करता है कि अगस्त 88 मे नये वाहक की उपलब्धि पर अशोक, महेश व उमराव सिह को चालक के कार्य पर रखा गया था इन परिस्थितियो मे यह भी साबित है कि सेवामुक्ति के बाद से अन्य उक्त व्यक्तियो को चालक के पद पर रखा गया जिसकी सूचना इस श्रमिक को नही दी गई इस प्रकार धारा 25एच के लाभकारी प्रावधानो की अवहेलना हुई है ।

7 क्लेम में श्रमिक यह भी दर्ज करता है कि सेवामुक्ति के पूर्व वरिष्ठता सूची नही बनाई गई जिस तथ्य को क्लेम के प्रतिउत्तर मे अस्वीकार नही किया गया है नियोजक साक्षी हाकिम सिह प्रतिपरीक्षा मे स्वीकार करता है कि केजुअल वर्कस की वरिष्ठता सूची नही होती इन परिस्थितियो मे नियोजक की तरफ से राजस्थान औद्योगिक विवाद नियमावली, 1958 के नियम–77 का भी उल्लघन किया गया है ।

8 क्लेम के प्रतिउत्तर मे नियोजक का कथन यह था कि जीप स.आर एस डी 1727 खराब हो गई थी और दैनिक मजदूरी के पद पर श्रमिक ने कार्य करने से मना कर दिया था और यह स्वय कार्य छोडकर चला गया। उक्त विषय मे प्रतिपरीक्षा करने पर श्रमिक कहता है कि वाहन स 1727 जीप खराब नही हुई थी चालू हालत मे थी । यह गलत है कि जीप खराब होने पर वह काम पर नही आता था, यह भी गलत है कि दि 9–4–85 से वह खुद काम छोडकर चला गया था बल्कि सन् 85 से 87 तक मैने कई बार एस.डी ओ.टी पुष्कर साहब से कहा था कि मुझे काम पर लगालो जो मुझे तसल्ली देते रहे । नियोजक साक्षी हाकिम सिह ने अपने शपथ पत्र मे तो यह दर्ज किया है कि दि 28–3–85 से वाहन स. आर.एस.डी. 1727 कार्य के योग्य नही रहा और उसके बाद दुबारा ठीक नही हुआ परन्तु इसकी अपुष्ट साक्ष्य पर निर्भर नही किया जा सकता विशेषकर उस रूप मे जबकि श्रमिक ने उक्त तथ्य को अस्वीकार किया है । नियोजक से अपेक्षा थी कि वे वाहन स आर० एस० डी० 1727 की अयोग्यता बाबत कोई प्रतेखिक अथवा अन्य विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य पेश करत । उक्त वाहन की लागबुक तक प्रस्तुत नहीं की गई है । अत नियोजक का यह कथन साक्ष्य के अभाव मे साबित नही पाया गया है ।

9 नियोजक का दूसरा कथन यह है कि श्रमिक स्वय कार्य छोडकर चला गया। मेरी राय मे उक्त कथन को भी हाकिम सिह के अपुष्ट कथनो पर साबित नही माना जा सकता क्योकि श्रमिक का स्वय द्वारा काम छोडकर जाने का कोई औचित्य नही था । नियोजक ही यह स्वीकार करते है कि जनवरी 87 मे श्रमिक ने जीप स० आर०एस०डी० 4241 चलाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खडपीठ ने डी बी सिविल रिट पिटी. स 129/87 मदन सिह बनाम श्रम न्यायलय जयपुर निर्णय दिनाक 22–4–87 द्वारा भी यह व्यवस्था दी है कि कोई भी व्यक्ति सामान्यत अपनी सेवाओ का त्याग नही करता जब तक कि उसे कोई लाभप्रद नियोजक नही मिल जाये तथा पद त्यागने का मामला तो तथ्यो से सबधित है तो साक्ष्य द्वारा ही साबित करना अपेक्षित है । यह भी व्यवस्था दी है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–2 (ओओ) मे पद त्यागना छटनी की छूट (एक्जेम्पशन) मे नही आता है। विवेचनाधीन विवाद में भी नियोजक की तरफ से ऐसी साक्ष्य नही आई है जिससे श्रमिक का पद त्यागना साबित हो । तर्क के लिए यह मान भी ले कि श्रमिक ने स्वय ने अपना पद त्याग दिया था तो भी यह एक दुराचरण था जिसके लिए नियोजक से अपेक्षा थी कि वह नियमानुसार आरोप समाकर जाच कर श्रमिक को दण्डित करता। इस विषय मे बम्बई उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टान्त 1988(2) एल.एल.एन. पेज–259 के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के रोबर्ट डिसूजा के न्याय दृष्टान्त 1982(1) एल.एस एन 257 का उल्लेख किया जा सकता है । जिसमे भी आकस्मिक श्रमिक द्वारा अनुपस्थित होने पर सेवामुक्ति की गई थी। इस विषय मे उडीसा उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त माधवानन्दा बनाम उडीसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1990 (1) एल.एच एन 924 न्याय दृष्टान्त का भी उल्लेख किया है । उपरोक्त न्याय दृष्टान्तो मे मेरी राय मे नियोजक का यह तर्क भी चलने योग्य नही है और यह अपास्त किया जाता है ।

10 नियोजक प्रतिनिधि का एक तर्क यह था कि 9-4-85 के उपरात श्रमिक ने सन् 1988 मे यह विवाद खडा किया है और इसलिए उक्त अवधि के वेतन बाबत नियोजक को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता । श्रमिक ने अपने क्लेम मे विलब के कोई कारण का उल्लेख नही किया । अपने शपथ पत्र की चरण स 10 मे यही दर्ज किया है कि उसने प्रबन्धको से कई बार काम पर लेने हेतु निवेदन किया परन्तु कोई ध्यान नही दिया गया । दिनाक 4-1-87 से 29-1-87 तक कुल 24 दिन उसे वाहन स आर एस डी 4241 पर लगाया गया था । श्रमिक के अपुष्ट कथनों पर विश्वास नही किया जा सकता कि उसने सेवामुक्ति के उपरात अनेको बार काम पर लेने के लिए प्रबंधको को कहा हो विशेषकर उस परिस्थिति मे जबकि नियोजक साक्षी हाकिम सिह से प्रतिपरीक्षा मे ऐसे सुझावात्मक प्रश्न नही पूछे गये । श्रमिक की तरफ से

असफल वार्ता प्रतिवेदन की भी फोटोप्रति पेश की गई है जिसमें भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि इस श्रमिक ने सेवा मुक्ति के उपरांत काम पर लेने बाबत प्रबंधकों को मौखिक एवं प्रलेखिक निवेदन किया हो । इसके द्वारा यही निष्कर्ष निकलता है कि सन् 88 में सर्वप्रथम श्रमिक ने समझौता अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था । जो मेरी राय में काफी विलम्बित था । श्रमिक से अपेक्षा थी कि वह 9-4-85 के शीघ्र उपरांत अथवा एक छ माह के समय में ही समझौता अधिकारी के यहां आवेदन करता । अत: इन परिस्थितियों में 1 जनवरी 86 से 31 जनवरी 88 तक की अवधि का वेतन प्राप्त करने का श्रमिक अधिकारी नहीं है ।

11. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस रेफरेंस का अधिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है कि—

श्रमिक अब्दुल समद को दिनांक 9-4-85 से वाहन चालक के पद से सेवा मुक्त करना उचित एवं वैध नहीं है और इसे वाहन चालक के पद पर नियोजित घोषित किया जाता है इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है तथा इस श्रमिक को 1-1-86 से 31-1-88 तक की अवधि का वेतन नहीं दिलाया जाता है तथा शेष अवधि का वेतन दिलाया जाता है तथा इसे 100 रु. खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है । उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जाये ।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का.आ. 2284.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिवीजनल इंजीनियर जोधपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-92 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-40012/121/90-आई. आर. (डी-यू.) (पार्ट)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1992

S.O. 2284.—In pursuance of Sectjon 17 of the Industiral Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Eng. Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on 16-7-92.

[No. L-40012/121/90-IR(DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई. टी. 9/1991

रेफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/121/90 आई. आर. (डी. यू.) दिनांक 31-1-91

श्री शमसुदीन सुपुत्र श्री उम्मेद खां निवासी सिन्धियों की धाणी गांव मलार, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ।

---- प्रार्थी

बनाम

डिवीजनल इंजीनियर, जोधपुर ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर . श्री एम.एफ. बेग

अप्रार्थी की ओर से : श्री प्रवीण बलवदा

दिनांक अवार्ड : 30 मई, 1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of Deptt. of Telecommunication in terminating the services of Shri Samsuddin S/o Shri Umed Khan, daily rated workman w/e.f. 6-5-86 is justified? If not what relief is the workman concerned entitled to ?"

2. प्रार्थी शमसुदीन जिसे तत्पश्चात श्रमिक संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसने फरवरी 1982 में कैज्युअल लेबर के पद पर उप-मण्डल अधिकारी फोन्स द्वितीय जोधपुर के अधीन नियुक्त किया गया था जहां पर उसने जनवरी 1984 तक निरंतर कार्य किया था । तत्पश्चात उसे सेवा पृथक कर दिया और पुन. कार्य पर लगाने हेतु निरंतर आश्वासन दिया जाता रहा। श्रमिक का कहना है कि 7 जुलाई 1985 को उसे उप मण्डल अधिकारी तार प्रताप नगर जोधपुर ने कैज्युअल लेबर के रूप में पुन. नियुक्त किया जहां पर उससे 6 मई 1986 तक निरंतर कार्य लिया गया । 7-5-86 को मौखिक आदेश द्वारा सेवा मुक्त कर दिया । श्रमिक के अनुसार 6-5-86 को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में उसने 240 दिवस से अधिक कार्य कर लिया था फिर भी उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया, अर्थात् एक माह का नोटिस या उसे एवज में एक माह का वेतन भी नहीं दिया और न ही छंटनी भत्ता दिया । यहां तक कि छंटनी का कोई कारण नहीं बताया और न ही छंटनी की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी गई । श्रमिक यह भी कहता है कि छंटनी से पूर्व नियमानुसार वरीयता सूची प्रकाशित नहीं की गई और सेवा मुक्ति के समय कनिष्ठ लोगों को नियोजित रखा गया । इस प्रकार धारा 25-जी व नियम 77 का भी उल्लंघन किया है । सर्वश्री जालाराम, पपाराम, माधोसिंह, लालसिंह, राम लाल व गोरधन राम श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति सेवा मुक्ति के समय नियोजन में थे । सेवा मुक्ति के उपरांत भी नई नियुक्तियां की गई थीं जिस बाबत श्रमिक को सूचना नहीं दी गई और धारा 25-एच का भी उल्लघंन किया है । श्रमिक की प्रार्थना है कि उसे संवेतन सेवा में बहाल किया जाये और ब्याज सहित समस्त राशि दिलवाई जाये ।

3. अप्रार्थी ने जरिये प्रत्युत्तर प्रकट किया कि जुलाई 1985 में इस मण्डल में श्रमिक को रखा गया था और 7-5-86 से श्रमिक अपनी मर्जी से अनुपस्थित रह रहा है। नियोजक के अनुसार श्रमिक ने एक वर्ष में 240 दिवस अवश्य कार्य किया है परंतु वह स्वयं ही कार्य छोड़कर चला गया इसलिए नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही वह एक माह के वेतन का अधिकारी है। उसकी छंटनी नहीं की गई है इसलिए छंटनी भत्ते का भी अधिकारी नहीं है। उसे मौखिक आदेश द्वारा काम पर आने से मना नहीं किया बल्कि 7-5-86 से कई दिन उसकी अनुपस्थिति भी मस्टररोल पर लगाई गई थी। नियोजक का कहना है कि 7-5-86 के उपरांत कभी भी उसने अप्रार्थी से यह मालूम नहीं किया कि उसके साथी काम कर रहे हैं और लगभग 5 वर्ष अनुपस्थित रहा है। इसलिए उसे नौकरी देने का आधार नहीं बनता और धारा 25-एच का भी उल्लंघन नहीं होता है।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक शमसुदीन ने अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 व 2 प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां पेश की गई हैं। इसके विपरीत नियोजक की ओर से श्री विजय राज कर्नावट ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की। तत्पश्चात मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5. क्लेम के प्रत्युत्तर में ही नियोजक ने स्वीकार किया है कि इस श्रमिक ने जुलाई 1985 से 6-5-86 तक उनके यहां कार्य किया है और एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य पूरा कर लिया था। नियोजक का कहना था कि उन्होंने श्रमिक की छंटनी नहीं की बल्कि उसने स्वयं ही 7 मई 1986 से काम पर आना बंद कर दिया। नियोजक के उक्त कथनों में सत्यता का आभास नहीं होता है क्योंकि सामान्यतः तब तक कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जाता तब तक कि उसे अन्यत्र कोई लाभप्रद नियोजन नहीं मिल जाता हो। नियोजक का यह कथन नहीं है कि श्रमिक को अन्यत्र कोई नौकरी मिल गई हो न क्लेम के अनुसार ही अपने शपथ पत्र में भी श्रमिक ने दर्ज किया है कि उप मण्डल अधिकारी तार जोधपुर ने 6 मई 1986 को उसे मौखिक रूप से यह कहा कि तुम्हारे कार्य की आवश्यकता नहीं है और सेवा मुक्त कर दिया। प्रतिपरीक्षा में भी श्रमिक कहता है 6 मई 1986 को उसे मौखिक आदेश से नौकरी से हटा दिया वह स्वयं गैर हाजिर नहीं रहा। 6 मई 1986 के बाद भी वह कार्यालय में नौकरी पर गया था लेकिन उसे नौकरी में नहीं रखा। परंतु फिर भी नियोजक के प्रतिनिधि ने प्रतिपरीक्षा में श्रमिक से यह नहीं पूछा कि किस अधिकारी ने उसे मौखिक रूप से सेवा मुक्त किया था। 6 मई 1986 को श्री विजय कर्नावट उप मण्डल अधिकारी जोधपुर में नहीं थे। नियोजक साक्षी को यह भी पता नहीं है कि 6-5-86 को उप मण्डल अधिकारी जोधपुर कौन थे। इसलिए श्री विजय राज कर्नावट के उपरोक्त अपुष्ट मौखिक कथनों के आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 7-5-86 को श्रमिक ने स्वयं ने काम पर आना बंद कर दिया हो। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि 7-5-86 से श्रमिक ने स्वयं ने काम पर आना बंद कर दिया था तो भी राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के न्याय दृष्टान्त डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न. 129/87 बदन सिंह बनाम श्रम न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 22-4-87 के अनुसार पद त्यागना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (100) में दी गई छंटनी की छूट में नहीं आता इसलिए चाहे श्रमिक ने पद त्यागा हो वह छंटनी की ही परिभाषा में आयेगा। राबर्ट डिसूजा के न्याय दृष्टान्त 1982 (1) एल.एल.एन. 257 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आकस्मिक श्रमिक द्वारा ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर यह व्यवस्था दी थी कि उक्त पद त्याग दुराचरण था जिसके लिए नियोजक से अपेक्षा थी कि वह अपने सेवा नियमों के अनुसार आरोप अधिरोपित कर नियमानुसार जांच कराकर श्रमिक को दण्डित करते। इस विषय में 1988 (1) एल.एल.एन. 259, 1986 (1) एल.एल. एन. 912 तथा 1990 (1) एल.एल.एन. 924 के न्याय दृष्टान्तों का भी उल्लेख किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से प्रत्येक दृष्टिकोण से परखने पर भी मेरी राय में 7-5-86 से श्रमिक की छंटनी ही की गई थी जो धारा 25-एफ के प्रावधानों के विपरीत होने से अनुचित, अवैध एवं शून्य हो जाती है।

6. श्रमिक का यह भी कथन है कि 7-5-86 को सेवा मुक्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई और नियम 77 का उल्लंघन किया है तथा सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी कार्य कर रहे थे तथा सेवा मुक्ति के उपरांत नये व्यक्तियों को भी नियोजित किया गया है। उक्त तथ्यों को क्लेम के प्रत्युत्तर में भी नियोजक ने स्पष्ट अस्वीकार नहीं किया और जब श्रमिक ने क्लेम के अनुसार ही अपने शपथ पत्र में भी यह दर्ज किया कि सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति कार्य कर रहे थे और सेवा समाप्ति के उपरांत नई नियुक्तियां की गई हैं और वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई तो इस विषय में श्रमिक के प्रति परीक्षा भी नहीं की गई और न ही नियोजक साक्षी श्री कर्नावट ने अपने शपथ पत्र में इस विषय में उक्त तथ्यों का प्रतिवाद किया। इन परिस्थितियों में धारा 25-जी व 25 एच तथा नियम 77 का भी उल्लंघन हुआ है।

7. अप्रार्थी नियोजक के प्रतिनिधि का तर्क यह था कि 6 मई, 1986 के उपरांत करीब 5 साल बाद यह विवाद उठाया गया है इसलिए उक्त अवधि के वेतन का भार नियोजक पर नहीं डाला जा सकता। अपने क्लेम व शपथपत्र में श्रमिक ने उक्त विलंब बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न ही नियोजक साक्षी श्री करनावट से उक्त विषय में प्रति परीक्षा की है। श्रमिक से अपेक्षा थी कि वह 7-5-86 के तुरंत उपरांत यथासंभव समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद खड़ा करता जिस त्रुटि के लिए श्रमिक को 7 मई, 1986 से 7 मई 1990 तक की अवधि का वेतन नहीं दिलाया जा सकता।

8. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है

"श्रमिक शमसुद्दीन की 6-5-86 से सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है और इसे इसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है। इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है। 7-5-86 से 7-5-90 तक की अवधि का वेतन श्रमिक को नहीं दिलाया जाता है। इसके उपरांत का वेतन व अन्य सभी लाभ श्रमिक को दिलाये जाते हैं। 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर इस पंचाट के प्रकाशन के तीन माह के भीतर नियोजक उक्त राशि अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।"

9. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (1) के भेजी जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का. आ. 2285.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस डी ओ (टेलीग्राफ) सूरतगढ़ के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल – 40012/27/90 – आई आर (डी यू) (पी टी)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st July, 1992

S.O. 2285.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO (Telegraph) Suratgarh and their workmen, which was received by the Central Government on 16-7-92.

[No. L-40012|27|90-IR(DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 1/1991

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल – 40012/27/90 आई. आर. (डी यू) 18-12-90

श्री राम रतन सिंह, पुत्र श्री लालमन जाति सक्सैना जरिये महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, जे. सी. टी. मिल के सामने श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम

उप मण्डल अधिकारी (तार) एस. डी. ओ. (टी) सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर. एच. जे. एस

प्रार्थी की ओर से :	श्री जयवीर सिंह यादव
अप्रार्थी की ओर से :	श्री प्रवीण बलवदा
दिनांक अवार्ड :	30 मई, 1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है :

"Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer (Telegraphs) Suratgarh in terminating the services of Shri Ram Ratan Singh w.e.f. 22-6-88 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. प्रार्थी राम रतन सिंह, जिसे तत्पश्चात श्रमिक संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसे अप्रार्थी मण्डल अधिकारी (तार), सूरतगढ़ जिला गंगानगर द्वारा 24-6-81 को दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में स्थाई व स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के दिनांक से ही श्रमिक ने पूर्ण लगन व मेहनत से ड्यूटी अंजाम दी थी परन्तु नियोजक प्रार्थी को बीच-बीच में हटा देता था पूछने पर यही जवाब दिया जाता कि कुछ समय ठहर कर आ जाना फिर काम पर ले लिया जायेगा, श्रमिक चक्कर पर चक्कर लगाता रहता था जिस पर कभी काम पर रख लिया जाता तो कभी हटा दिया जाता था। यही क्रम 24-6-81 से 20-6-88 तक चलता रहा। श्रमिक का कहना है कि 24-6-81 से मार्च, 1982 तक उससे लगातार कार्य लिया है फिर दिसम्बर 1982 में 14 दिन के लिए पुनः काम पर लगाया। इसके बाद फरवरी, 1983 से अप्रैल 1983 तक व दिसम्बर 1984 से दिसम्बर, 1985 तक, जनवरी 1986 से दिसम्बर, 1986 तक, जनवरी 1987 से 21-6-88 तक कार्य लिया गया है। 22-6-88 को जब वह कार्य पर गया तो उसे अप्रार्थी ने कार्य पर नहीं लिया और पूछने पर बताया कि हमेशा के लिए काम से हटा दिया गया है अब कभी काम के लिए मही आना। श्रमिक कहता है इस पर उसने अपनी यूनियन को शिकायत की कि पुनः कार्य पर उसे लगवाया जाये क्योंकि धारा 25–एफ की पालना किये बिना हटाया है परन्तु फिर भी पुनः सेवा में नहीं लिया गया। श्रमिक का कहना है कि वह 21-5-87 से 15-3-88 तक बीमार रहा था और मेडिकल प्रमाण पत्र भी उसने अप्रार्थी को प्रस्तुत कर दिया था जिसके आधार पर मार्च, 1988 में उसे पुनः कार्य पर ले लिया गया परन्तु जून, 1988 में पुनः हटा दिया। श्रमिक कहता है अप्रार्थी के प्रधान कार्यालय के आदेश के अनुसार 31-3-85 के उपरांत 240 दिन पूरे करने वाले श्रमिकों को सेवा मुक्त करना अवैध व गैर कानूनी है जिस बाबत भी उसने अप्रार्थी को निवेदन किया था परन्तु फिर भी कोई सुनवाई नहीं की। श्रमिक के अनुसार सेवा मुक्ति की दिनांक से ही वह बेरोजगार है तथा उसका शोषण करने की नियत से ही उसे सेवा मुक्त किया गया है। अप्रार्थी के पास काफी काम है। सेवा मुक्ति के समय भी काफी कनिष्ठ श्रमिक कार्यरत थे और हटाने के बाद भी नये श्रमिकों को नियोजित किया है जबकि श्रमिक को सूचना तक नहीं दी गई। इसलिए उसे सवेतन सेवा में बहाल किया जाये।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर कहा है कि श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष में लगातार 240 दिवस तक कार्य नहीं किया, वह स्वयं कई बार नौकरी छोड़कर चला गया था जिससे अप्रार्थी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अगस्त 1981 से दैनिक वेतन के आधार पर अस्थाई व कैज्यूअल मजदूर के रूप में श्रमिक ने कार्य करना शुरू किया था। वह 1-4-82 से 31-11-82 तक, 15-12-82 से 31-1-83 तक, 1-5-83 से 30-11-84 तक, 21-5-85 से 31-3-87 तक, 21-5-87 से 15-3-88 तक कार्य पर नहीं आया और स्वयं अनुपस्थित रहा इसलिए किसी भी वर्ष में 240 दिवस लगातार कार्य नहीं किया। अगस्त, 1981 से मार्च, 1982 तक श्रमिक ने 192 दिन कार्य किया है। तत्पश्चात 1-4-82 से 30-11-82 तक गैर हाजिर रहा। दिसम्बर, 1982 में केवल 14 दिन कार्य किया। अप्रैल व मई, 1987 में केवल 38 दिन कार्य किया। 16-3-88 से जून 1988 तक केवल 78 दिन कार्य किया। इसलिए एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस पूरे करने पर ही 25–एफ के प्रावधान लागू होते हैं और धारा 25–जी व 25–एच की भी अवहेलना

नहीं होती । नियोजक का कहना है कि प्रार्थी को उसी की प्रार्थना पर एक निश्चित परियोजना व लक्षित कार्य हेतु अस्थाई तौर पर रखा गया था ताकि पुरानी सेवा के आधार पर मैडीकल प्रमाण-पत्र पत्र प्राप्त किया स्वीकार किया ।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक राम रतन सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की । प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू – 1 लगायत डब्ल्यू – 10 फोटो प्रतियां पेश की हैं । इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की । तत्पश्चात मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना ।

5 अपने शपथ पत्र में भी क्लेम के अनुसार ही श्रमिक राम रतन सिंह कहता है कि उसने 24-6-81 से 22-6-88 तक नियोजक की सेवा की है, बीच-बीच में उसे अप्रार्थी ने ड्यूटी पर नहीं लगाया और पूर्व की भांति सेवा से हटाने का जुबानी आदेश देते रहे । सेवा पृथक करने का कारण या वजह पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया । श्रमिक कहता है अगस्त 1981 से मार्च 1982 तक प्रदर्श डब्ल्यू-1 के अनुसार उसने 220 दिन काम किया है जिसमें साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं है जिन्हें जोड़ने पर 254 दिन बनते हैं । श्रमिक यह भी कहता है कि वर्ष 1986 में 285 दिवस कार्य किया है जिस बाबत प्रदर्श डब्ल्यू–4 लगायत डब्ल्यू-7 पेश किये हैं । श्रमिक के अनुसार डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-8 तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा ही जारी किये गये हैं प्रति परीक्षा में भी श्रमिक ने कहा है कि उसे लिखित नियुक्ति आदेश नहीं दिये, 24-6-81 से उसे नौकरी में लगाया गया था, 22-6-88 को उसे काम पर नहीं लिया गया । श्रमिक स्वीकार करता है कि वह 21-5-87 से 15-3-88 तक बीमार रहा था जिसके मेडीकल प्रमाण-पत्र उसने पेश किये थे और 16-3-88 को उसे काम पर ले लिया था । 22-6-88 को एस.डी.ओ. श्री राम प्रताप खटटर ने कहा कि नहीं रखूंगा आप चले जाओ । फिर भी उक्त श्री राम प्रताप का परीक्षण नहीं करवाया गया है और नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार शर्मा जो जून 1990 से ही अप्रार्थी संस्थान में कार्यरत है इसके पहले की अवधि का उसे निजी ज्ञान नहीं है । रिकार्ड के आधार पर शपथ पत्र पेश किया है । नरेन्द्र कुमार शर्मा ने भी क्लेम के प्रत्युत्तर के अनुसार ही कहा है कि किसी भी वर्ष में श्रमिक ने 240 दिन लगातार काम नहीं किया । प्रति परीक्षा करने पर नियोजक साक्षी स्वीकार करता है कि 21-5-87 से 15-3-88 तक का उसने मेडीकल दिया था । नियोजक साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-6 पर तत्कालीन एस. डी.ओ. के ही हस्ताक्षर हैं । डब्ल्यू-7 भी हमारे कार्यालय का ही है परंतु इस पर दस्तखत किसके हैं नहीं पहचानता । इन परिस्थितियों में श्रमिक राम रतन सिंह के मौखिक बयानों की पुष्टि प्रदर्शन डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-6 से होती है । डब्ल्यू-1 में अगस्त 1981 से मार्च 1983 तक की अवधि में इस श्रमिक द्वारा की गई सेवा का उल्लेख है । इसमें मस्टर रोल सं. तथा पार्टी इंचार्ज का नाम भी दर्ज है । अगस्त 1981 से मार्च 1993 तक 254 दिवस कार्य किया गया है जिसमें साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश एवं फैस्टीवल अवकाश शामिल नहीं हैं । डब्ल्यू-2 अप्रैल 1983 से मई 1988 तक का है । इसके अनुसार 264 दिवस कार्य करना बताया गया है, इसमें भी पार्टी इंचार्ज का नाम व मस्टररोल सं. दर्ज है । डब्ल्यू-3 जुलाई 1985 से दिसम्बर 1985 तक का है । 119 दिवस कार्य करना दिखाया गया है तथा मस्टर रोल सं. व पार्टी इंचार्ज का नाम दर्ज है । डब्ल्यू-4 जनवरी 1985 का है और 25 दिवस काम करना बताया गया है । डब्ल्यू-5 फरवरी 1986 से सितम्बर 1986 तक की अवधि का है और 210 दिवस कार्य करना दिखाया गया है । इस पर भी मस्टररोल नं. व पार्टी इंचार्ज का नाम दर्ज है । डब्ल्यू-6 अक्तूबर 1986 का और 22 दिवस कार्य दिखाया गया है । डब्ल्यू-7 अक्तूबर 1986 से मार्च 1987 तक की अवधि का है जिस पर 138 दिवस कार्य करना दिखाया गया है, इसमें भी पार्टी इंचार्ज व मस्टररोल सं. दर्ज है । डब्ल्यू-8 द्वारा अप्रैल 1987 से मई 1987 व जून 1988 में 54 दिवस कार्य करने का उल्लेख है इसमें भी मस्टर-रोल व पार्टी इंचार्ज का नाम दर्ज है । उपरोक्त सभी प्रलेख नियोजक द्वारा जारी किये गए हैं इन पर तत्कालीन उप मण्डल अधिकारी (तार), सूरतगढ़ के हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा अंकित है फिर भी नियोजक की तरफ से इन प्रलेखों में दर्ज मस्टररोल पेश नहीं किये गये हैं न ही किसी पार्टी इंचार्ज का बयान कराया गया । बहस के दौरान श्री प्रवीण बवलवा नियोजक प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया कि डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-8 अप्रार्थी द्वारा जारी किये गये हैं । इन परिस्थितियों में श्रमिक की मौखिक साक्ष्य के अलावा अगर उपरोक्त प्रालेखिक साक्ष्य का भी प्रयोग किया जावे तो डब्ल्यू-2 के अनुसार श्रमिक ने जनवरी 1985 में 27 दिवस, फरवरी में 24 दिवस, मार्च में 23 दिवस, अप्रैल में 25 दिवस, मई में 27 दिवस, जून में 28 दिवस, जुलाई में 20 दिवस काम किया है । डब्ल्यू-3 के अनुसार जुलाई 1985 में 6 दिवस, अगस्त में 27 दिवस, सितम्बर में 26 दिवस, अक्तूबर में 27 दिवस, नवम्बर में 6 दिवस और दिसम्बर 1985 में 27 दिवस कार्य किया है । उक्त अवधि के मस्टररोल सं. भी दर्ज है और जिस पार्टी इंचार्ज के अधीन काम किया था उसका नाम भी दर्ज है । इस प्रकार डब्ल्यू-2 व डब्ल्यू-3 से जनवरी 1985 से दिसम्बर 1985 तक इस श्रमिक ने 291 दिवस कार्य कर लिया था जिसमे साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं है । इसी प्रकार प्रदर्श डब्ल्यू-5 के अनुसार जनवरी 1986 से सितम्बर 1986 तथा डब्ल्यू 6 द्वारा अक्तूबर 1986 में डब्ल्यू-7 द्वारा दिसम्बर 1986 तक इस श्रमिक ने कुल 316 दिवस काम किया है जिसमें भी साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं है । तत्पश्चात् श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष मे 240 दिन से अधिक काम नहीं किया है । परंतु मेरी राय में, नियोजक प्रतिनिधि का यह तर्क चलने योग्य नहीं है कि सेवा मुक्ति हुए एक कलैण्डर वर्ष में श्रमिक को 240 दिवस की सेवा पूरी करनी आवश्यक थी । इस विषय में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त बी.आर. आयल मिल्स भरतपुर बनाम बी.आर. आयल मिल्स मजदूर यूनियन, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 889/81 निर्णय दिनांक 10-11-81 का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें धारा 25-बी की व्याख्या की गई है । इस विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम सी.आई.टी. 1980 (2) एल. एल.एन. 456 तथा अमेरिकन एक्सप्रेस के न्याय दृष्टान्त 1985 (2) एल.एल.एनसे 817 तथा 1970 (एस.सी.) ॥ एल.एल.एन. 306 का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसके द्वारा भी धारा 25-बी की व्याख्या की गई है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ने 1988 लैब. आई.सी. 425 के न्याय दृष्टान्त में निम्न मत व्यक्त किया गया है ।

> Even sickness, authorised leave, accident or strike which is not illegal or session of work which is not due to any fault on the part of the workman is to be counted in holding continuation of service for 140 days."

6. विवेचनाधीन विवाद में नियोजक साक्षी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करते कि 21-5-87 से 15-3-88 तक का उसने मेडीकल दिया था इसलिए चाहे उक्त अवधि का वेतन श्रमिक को नहीं दिया गया हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के अनुसार 21-5-87 से 15-3-88 तक की यह अवधि भी धारा 25-बी के अन्तर्गत 240 दिवस की गणना करने में प्रयोग की जायेगी । अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से परखने पर भी मेरी राय में यह श्रमिक धारा 25-ए के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी बन जाता है । निर्विवाद रूप से श्रमिक को धारा 25-एफ के अनुसार एक माह का नोटिस या उसके बदले में एक माह का नोटिस वेतन अथवा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया और छंटनी का कोई कारण न तो श्रमिक को बताया गया और न ही केन्द्रीय सरकार को इस विषय में सूचना भेजी इसलिए श्रमिक की सेवा मुक्ति धारा 25-एफ के विपरीत होने से स्वतः ही अनुचित, अवैध व शून्य हो जाती है ।

6. श्रमिक का कहना है कि 22-6-88 से पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई। नियोजक साक्षी भी प्रति परीक्षा में इस विषय में स्वीकार करता है कि वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई। स्वीकृत रूप में 22-6-88 को श्रमिक जैसे अस्थाई केज्युअल दैनिक वेतन भोगी मजदूर मस्टरोल पर कार्यरत थे इसलिए नियम 77 का उल्लंघन किया गया है।

7. श्रमिक ने न तो क्लेम में और न ही अपने शपथ पत्र में उन व्यक्तियों के नाम दर्ज किये जो उससे कनिष्ठ थे तथा 22-6-88 का भी सेवा में थे। सेवा मुक्ति के उपरान्त श्रमिक जैसे ही कार्य पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख भी न तो क्लेम में और न ही श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में किया है। नियोजक साक्षी से प्रति परीक्षा में तुलनात्मक प्रश्न किया है कि राम विलायन व राम किशन श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति नौकरी में थे जिस बाबत उसने अनभिज्ञता व्यक्त की है। मेरी राय में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि 22-6-88 को श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति कार्यरत थे या उसके उपरोक्त श्रमिक जैसा कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। श्रमिक से अपेक्षा थी कि वह इस विषय में विश्वसनीय मौखिक व प्रालेखिक साक्ष्य पेश करता। अतः धारा 25-जी एवं एच की अवहेलना साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।

8. दिनांक 22-6-88 को श्रमिक की सेवा मुक्ति की गई थी और 5-12-88 को ही इसने समझौता अधिकारी के यहां विवाद खड़ा कर दिया था ऐसा उल्लेख असफल प्रतिवेदन प्रपत्र डब्ल्यू-12 में मिलता है इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रमिक ने स्वयं सेवा नहीं त्यागी है बल्कि नियोजक ने ही उसे काम पर लेने से मना कर दिया था।

9. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"श्रमिक राम रतन सिंह को 22-6-88 से सेवा मुक्ति करना उचित एवं वैध नहीं है, इसे इसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है। इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है और इसे पिछला समस्त वेतन व अन्य सभी लाभ भी दिलाये जाते हैं। 100 रु. व खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर नियोजक इस अधिनिर्णय के प्रकाशन के अन्दर तीन माह उक्त राशि अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।

10. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के भेजी जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1992

का.आ. 2286.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/14/89-आई आर (बैंक-1)]
सुभाष चन्द शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th August, 1992

S.O. 2286.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mithila-Kshetriya Gramin Bank and their workmen, which was received by the Cenrtal Government on 3-8-1992.

[No. L-12011/14/89-IR (Bank-I)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 90 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga,

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri D. Mishra, Advocate.

For the Workmen—Smt D. Mukherjee, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Banking

Dated, the 17th July, 1992

AWARD

By Order No. L-12011/14/89-I.R. Bank-I, dated, the 9th August, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the Chairman, Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga in terminating the services of Shri Kishore Jha, Ex-Casual workman (IV Grade employees') vide their Order No. HO/PRS/5/85 dated 16-9-85 is fair and justified? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The case of the management of M/s. Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga, as disclosed in the written statement submitted by it, detailed apart, is as follows :

In conformance to the guidelines issued by the Government India, M/s. Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga (hereinafter referred to as Bank) was engaging persons to work as casual workers on daily wages purely on temporary basis to attend the work at Branches, such as, cleaning the premises, arranging for drinking water, etc. Kishori Jha was one of such person and he was appointed on 3-2-81 by the Chairman of the Bank to work at Bouram Branch of the Bank as casual worker on daily wages of Rs. 6.00 per diem. He was not a regular employee of the Bank nor was he an employee placed on 4th grade as claimed by him. The management received a letter from Branch Officer, Bouram on 7-3-83 regarding misconduct of Kishori Jha and some complaint from the public were also received by the management in which allegation regarding taking illegal gratification by him were made. A preliminary enquiry against the concerned workman was conducted by the Officer-in-Charge Audit and Inspection Department of the Head Office on 8-3-83 as per order of the Chairman; the Officer-in-Charge submitted his report on 21-3-83 in which prima-facie case of misconduct committed by the concerned workman was found to have been proved. In the circumstances, the concerned workman was directed to submit explanation by letter 25-3-83, but he refused to receive the letter after opening the envelop and reading the contents thereof. Since he refused to receive the memo calling for explanation, the Chairman had no option but to terminate the casual service of the concerned workman. Accordingly, the service of the concerned workman was terminated on 2-4-83 by letter dated 1-4-83. Thereafter the concerned workman filed writ petition in Patna High Court which was registered as C.W.J.C. No. 1559/83. While disposing of the said writ petition, the Court quashed the order of termination on technical ground and observed that it would be open to the authorities if they were so advised to proceed further in the matter in accordance with the law and directed the concerned workman to show cause within ten days. As per order of the Court the concrned workman was re-appointed as casual worker. He filed his show cause which was considered to be unsatisfactory and the management decided to hold proper domestic enquiry

and the allegation and a chargesheet dated 11-10-83 was served on him. Shri D. N. Thakur, Officer-in-charge, Statistics Department and Shri Shiva Shankar Jha, Officer-in-Charge, Planning and Development Department were appointed as Enquiry Officer and presenting Officer respectively by the management by letter dated 27-10-83 and the concerned workman was informed accordingly. The domestic enquiry started on 25-11-83 and completed on 15-5-85. The Enquiry Officer submitted his report to the Disciplinary Authority on 6-9-85. The domestic enquiry was conducted without any prejudice and in a proper and legal way. It was conducted in presence of the concerned workman and sufficient opportunities were given to him to cross-examine the management's witnesses and to place his defence and evidence and in the process the principles of natural justice and fair play were strictly observed. After careful study of the enquiry report the Disciplinary Authority agreed with the finding of the Enquiry Officer and found the concerned workman guilty of the charges nos. 1, 3, 4 and 5 which were major misconduct warranting termination of casual service of the concerned workman. The Disciplinary Authority rightly and properly passed the order of termination of service of the concerned workman by letter dated 16-9-85. Although there is specific provision in the Staff Service Regulation 1980 for appeal within 30 days against the order passed by an authority which injuriously affects his interest. The concerned workman did not prefer any appeal before the Appellate Authority. He again filed a writ petition which was registered as C.W.J.C. No. 4776/85 in the Patna High Court challenging termination order of the management and for quashing the same. The writ petition was dismissed by the Court. Thereafter he again filed a case in the Court of 1st Additional Munsiff at Darbhanga which was registered as T.S. No. 23 of 1986 assailing his termination of service. The suit was dismissed by the Court with the observation that the Civil Court has got no jurisdiction to try that suit. Thereafter the present industrial dispute was raised by the concerned workman before Asstt. Labour Commissioner (C), Patna. The conciliation proceeding ended in a failure as the management had not agreed to take him into service. The appropriate Government has referred the dispute for adjudication by this Tribunal.

3. The case of the concerned workman, as appearing in the written statement submitted by him, is as follows :

He was working as permanent workman since long with unblemished record of service. The management arbitrarily and whimsically terminated his service in violation of the mandatory provision of the Industrial Disputes Act. He challenged the illegal and arbitrary order of termination of service by the management before Patna High Court. The Hon'ble Court passed an order quashing termination order and directed the management to reinstate him in service with full back wages. The direction of the Court was not palatable to the management. With an ulterior motive and in order to victimise him, the management issued a false and frivolous chargesheet against him on 11-10-83. He submitted his reply on 17-10-83 denying the false and frivolous charges. Although his reply to the chargesheet was sufficient, the biased management appointed biased and prejudiced Enquiry Officer to conduct enquiry by office order dated 17-10-83. Appointment of the Enquiry Officer itself was illegal and void ab-initio. The concerned workman was not aware of the procedure of enquiry and prayed before the management for being represented by a lawyer in domestic enquiry by petition dated 31-10-83. The management refused to give him permission to be represented by a lawyer. The Enquiry Officer was biased and prejudiced against him and the enquiry was conducted in violation of the principles of natural justice. By petition dated 23-11-83 he submitted a list of 26 persons before the Enquiry Officer with a prayer to examine them. None of the independent witness was allowed to be cross-examined by him. He was not aware of the procedure relating to enquiry and the Enquiry Officer did not ask him to cross-examine any of the witnesses.. The Enquiry Officer also rejected arbitrarily and whimsically many of the questions put to some of the witnesses for the management. The matter was brought to the notice of the Enquiry Officer with a copy to the Chairman, but the anti-labour management did not pay any heed to it. He was not also informed of the date of enquiry which is evident from the enquiry proceeding. He repeatedly requested to close the enquiry due to non-appearance of the management witnesss, but the biased Enquiry Officer did not pay any heed to it He requested the Enquiry Officer by letter dated 8-8-85 to allow him to adduce evidence instead of submitting written argument, but the Enquiry Officer rejected his prayer. The Enquiry Officer did not also take into consideration the documents produced by him during the course of domestic enquiry. Again, the Enquiry Officer did not give any reason for believing the documents of the management and disbelieving the documents produced by him. Even in the invalid and irregular enquiry, the management miserably failed to establish the charge against him. He was dismissed illegally and arbitrarily by an unauthorised person.

4. In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has asserted that the domestic enquiry was held fairly and properly and in conformance to the principles of natural justice and the concerned workman was given full opportunity to defend himself in domestic enquiry.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the concerned workman has reiterated his case as made out in his written statement.

6. The issue as to whether the domestic enquiry was held fairly and properly was considered as preliminary issue. In the course of hearing the management examined the Enquiry Officer, Shri D. N. Thakur and laid in evidence a mass of documents which were marked Exts. M-1 to M-15.

On the other hand, the concerned workman examined himself and laid in evidence some documents which were marked Exts. W-1 to W-6.

It was held, by order dated 15-1-1992, that the domestic enquiry was held fairly and properly and in conformance to the principles of natural justice. Thereafter the case was heard on merit.

7. Shri Kishori Jha, the concerned workman, was appointed by the Chairman of the bank as casual worker on a daily wages of Rs. 6 per diem on 3-2-81. He was working in Bouram Branch of the Bank since the date of his appointment.

Rajendra Prasad, Branch Manager of Bouram Branch, by letter dated 5-3-83 (Ext. M-9) reported certain acts of misconduct committed by the concerned workman to the Chairman of the Bank. The Chairman, thereupon directed Sri S. N. Jha, Officer-in-Charge, Audit and Inspection Department of Head Office to conduct a preliminary enquiry in the matter and submit his report. Shri Jha submitted his report holding that the case of misconduct of the concerned workman was, prima-facie, proved. Thererafter the Chairman by memo dated 25-3-83 directed the concerned workman to submit his explanation. It is alleged that consequent upon refusal of the concerned workman to receive the memo after opening the envelope and reading the contents thereof, the Chairman had to terminate the service of the concerned workman. Admittedly, the concerned workman filed writ petition which was registered as C.W.J. C. No. 1559/83 in Patna High Court assailing the order of his termination of service. The Hon'ble Court quashed the order of termination of service of the concerned workman and observed that it would be open to the authorities if they were so advised to proceed with the matter further in accordance with the law and directed the concerned workman to submit his show-cause within ten days. The management re-appointed him as casual worker and issued chargesheet dated 11-10-83 against him consisting of five counts of charges (Ext. M-1). The chargesheet is re-produced hereinbelow :

"Sri Kishoree Jha,
Casual Worker,
Branch - More

Subject—Charges levelled against you.

With reference to above we have to inform you that explanation dated 6-9-83 furnished by Shri Jha in context of the direction of Hon'ble High Court Patna has been found unsatisfactory and non believable. Hence following charges are levelled against Sri Jha.

Charge No. 1—That Sri Jha refused to acknowledge Head Office memo No. HO/PRS/4/83|354 dated 25-3-83 which is indicative of major indiscipline in itself.

Charge No. 2—Sri Jha has taken illegally Rupees thirty each from the beneficiaries of IRDP while giving them blank application form while the provision is that the application should be given free of cost. This has been clearly established from the report of branch officer Bauram, Permukh Panchayat Samitee Ghanshyampur Block Sri Raghu Nandan Paswan as well as from the local inspection report of officer Audit and Inspection Head Office.

Therefore, the charge of taking illegal money from the poor rural people for loan application misguiding public, tarnishing the image of the Bank and corruption is clearly established.

Charge No. 3—When branch officer Bauram enquired from Sri Jha about taking illegal money for loan application them he misbehaved with branch officer Bauram and also threatened the Branch Officer "being a scheduled cast person if you initiate any action against me then I will make stay your here troublesome" This is indicative of major misconduct and indiscipline.

Charge No. 4.—Not only this but Sri Jha was neither coming to office in time nor was cleaning the branch premises and performing daily duties despite repeated instruction of branch officer, Bauram. This thing has been confirmed in report received from officer in charge, Audit and Inspection and which is clear case of negligence of duty, indiscipline and carelessness towards duties.

Charge No. 5—In spite of all these things the then Branch Officer Sri Rup Kumar Mahto while getting relieved for branch on transfer was requested by Sri Jha for issue of one character certificate so that it can be useful for him in future for permanent job. Accordingly the branch officer issued one character certificate to Sri Jha on 11-12-82 in which Sri Jha added in the office copy in his own handwriting that "YE LIPIK KA KAM BHI PURN RUP SE SAMHAL LETA HAIN."

So there is serious case of fabrication and interpolation in the official document.

Undersigned has taken a decision to get all the above charges finally inquired for which the appointment of Enquiry Officer and the date of enquiry will be decided very soon. You will be informed about it in due time. Hence you should keep yourself prepared for final enquiry as well as if you have some explanation to offer about above mentioned charges then you can furnish the reply to the undersigned within seven days of the receipt of the chargesheet.

Let it be known that if some other type of charge of irregularity is received against Sri Jha in the meantime the management will be free to get such charges enquired during the final enquiry.

Sd/-

B. RAMESH, Chairman."

In conformance to the order of Hon'ble Court the concerned workman submitted his explanation dated 17-10-83 to the chargesheet denying all the charges (Ext. M-2).

The explanation of the concerned not being found satisfactory the management decided to hold domestic enquiry into the charges levelled against him. In the domestic enquiry the concerned workman was found guilty of alleged misconduct in respect of five counts of charges, namely Nos. 1, 3, 4 and 5. Charge No. 2 contains allegation against him of receiving illegal gratification. This was a serious charge. But the management could not prove it in domestic enquiry. Even then the Enquiry Officer has not spared to commit that although it was not proved that the concerned workman took illegal gratification, 'the possibility also cannot be denied that with his efforts Kishori Jha might have mobilised the management's witnesses in his favour'. This demonstrates that the Enquiry Officer has given free flight of his imagination in drawing such inference and in the process leaned on the case of the management against the concerned workman.

8. I have already re-produced the chargesheet containing five counts of charges brought against the concerned workman of which Charge No. 2 alleging taking of illegal gratification by the concerned workman was not proved in the domestic enquiry. But remaining four charges, according to Enquiry Officer, were proved against the concerned workman.

Shri D. Mukherjee, learned Advocate for the concerned workman, has submitted before me that all the four counts of charges are vague and indefinite inasmuch as they do not disclose the date and time when alleged acts of misconduct was committed by the concerned workman.

Shri D. Mishra, learned Advocate for the management, has contended that the concerned workman cannot assail the charges levelled against him as he has not questioned the infirmity of charges in his pleading.

Adverting to the pleading of the concerned workman, it appears that he has alleged therein that the charges were false and frivolous. Frivolous means of little value or importance; trifling; trivial; not properly serious or sensible, silly and light minded, giddy.' Thus, it appears that the concerned workman in his pleading has stignatised the charge as not serious or sensible and of little value or importance.

Consideration of charge is always a mixed question of law and facts. Charge must contains some essential ingradients. It shall contain such particulars as to the time and place of alleged charge and the persons against whom or the thing in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the person proceeded against the notice of the matter with which he is charged. When the nature of the case is such that the particulars aforesaid do not give the person proceeded against sufficient notice of the manner with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence/misconduct was committed as will be sufficient for that purpose.

9. Charge No. 1 simply discloses that the concerned workman refused to acknowledge Head Office letter dated 25-3-83 which is indicative of major indiscipline itself. Here the date on which such refusal was made and the person who presented him the letter have not been spelt out. In my view this is a serious infirmity which cannot be glossed over. The concerned workman replied that the affidavit of the Bank in the Hon'ble Court shows that the said letter was despatched on 25-3-83 and was handed over to him by the Branch Manager on 26-3-83 and that he read he letter after opening the envelope and returned the same to the Branch Manager That apart, the letter dated 25-3-83 is a letter directing him to submit explanation to the alleged misconduct. The concerned workman was within his right to accept or refuse the letter and consequence that will ensue on his refusal to accept the letter is that it would be considered that he has got the letter.

Shri Mishra has contended that the concerned workman refused to accept the lawful order of the management as contained in that letter and this must be considered to be a misconduct. In support of his contention he cited the decision of Supreme Court, reported in 1959 (II) LLJ, 224 [Tractor (India Ltd. Vs. Mohammed Sayeed and another]. But the fact of the case is fairly distinguishable from the facts of the present case. In that case the Darwan of the management refused to accept the Office Order underlining the duties. In the context of such fact the Hon'ble Supreme Court held that refused to accept lawful order of the management is a misconduct. In the present case, even if it is assumed that the concerned workman refused to accept the letter in question, directing him to submit his explanation to the allegations of misconducts against him, his refusal to accept the same will mean that he has received the letter and has no explanation to offer and necessary consequence will ensue. The management cannot compel the workman to submit his explanation. If the workman does not submit any explanation

natural consequence will follow. So, in my view, the concerned workman, even if refused to accept the letter, did not commit any misconduct.

10. The third charge relates to mis-behaviour of the concerned workman with the Branch Manager. The concerned workman has denied this charge. He has stated in his explanation that his duty is to obey the instruction of higher officer and he will always obey the officers and obey them in future.

I have already pointed out that Rajendra Prasad, Branch Manager, reported to the management complaining that he (concerned workman) was taking illegal gratification from outsiders. The same Rajendra Prasad complained that the concerned workman mis-behaved with him. Here also the charge is vague for it has not disclosed the date, time and place when the concerned workman mis-behaved with him. So it remains, ipsi dixit of Shri Prasad that the concerned workman mis-behaved with him. In my view, the allegation of Shri Prasad against the concerned workman for mis-behaviour is not worthy of cridence as he was not disposed favourably towards the concerned workman. That being so, the charge both substantively and technically is incompetent.

The fourth count of charge relates to negligence of duty and carelessness. Here also, the charge does not discloses the date and place when such delinquency was committed by the concerned workman. In reply to this charge the concerned workman has stated that the charge is baseless. He had always reported for duty on time and performed his duty of cleaning the office efficiently. When even the cleaning was delayed it was not due to his irresponsibility but due to assignment of other work by the Branch official from time to time during the cleaning hour. Knowingly he has never delayed the cleaning operation. As a matter of fact S. N. Jha, Officer of Audit and Inspection Department of Head Office, while he made preliminary enquiry, found the concerned workman removing mud from the office by pouring water. The management has not produced the Attendance Register to show that the concerned workman did not report for duty in time. This being the evidence, I am constrained to hold that the charge is technically incompetent and substantively not sustainable.

The charge No. 5 relates to tempering with the character certificate issued by Sri Rup Kumar Mahato, Branch Officer, inform of the concerned workman while he was being relieved of his duty from the branch. It has been alleged that the concerned workman has tampered with this certificate by writing "YE LIPIK KA KAM BHI PURN RUP SE SAMBHAL LETA HAIN". In his explanation (Ext. M-2) the concerned workman has stated that Sri Rup Kumar Mahato, Branch Officer, Bouram, issued a character certificate in his favour after being impressed by his efficient and behaviour, a copy of which was, kept in branch file. Office Order remains in the branch file and without Branch Manager's order it cannot be removed. He has specifically stated that if something is added in the character certificate that was not done by him because he could not touch the file without the permission of the Branch Officer.

Admittedly, the documents including character certificate remained in the custody of the Branch Officer. The management has not laid any evidence to prove that the concerned workman had occasion and opportunity to get at the characer certificate and tamper with the same. Besides, the management has not proved the handwriting of the concerned workman in the character certificate. The Enquiry Officer has held that since direct or in-direct benefit of addition of this sentence will go only to the concerned workman, he on getting some opportunity has added the sentence in the contracter certficate. Here again, the Enquiry Officer has given flight his imagination because there is nothing on evidence to indicate that the concerned workman got such opportunity. The Enquiry Officer has not even spared the pain of making comparision between admitted handwriting of the concerned workman and impugned writing. This being so, I hold that this charge also has not been proved.

11. Shri D. Mukherjee has submitted that in the Service Regulations of the Bank none of the acts as borne out in the chargesheet is prescribed as misconduct.

Shri D. Mishra has contended that the Service Regulations of the Bank envisage such acts as misconduct.

Chapter 4 of Regulations 16 to 30 enumerate acts of misconduct. But acts of misconducts as allegedly committed by the concerned workman do not fall within the four corners of the Service Regulations. The Hon'ble Supreme Court has held in the case reported in 1985 Lab I.C. 729 (Rasiklal Vaghajibhai Patel Vs. Ahmedabad Municipal Corporation and another) that it is well settled that unless either in the Certified Standing Orders or in the Service Regulations an act or omission is prescribed as misconduct, it is not open to the employer to fish some conduct as misconduct and punish the workman even though the alleged misconduct would not be comprehended in any of the enumerated misconduct. These being the legal position, the entire exercise of the management in finding the concerned workman guilty of some fished out misconduct and to punish him for such misconduct is futile.

12. Considering the facts and circumstances of the case and evidence on record and legal position, I hold that the Enquiry Officer was not justified in holding the concerned workman guilty of the alleged misconduct and the management also was not justified in terminating his service with ecect from 16-9-85 by letter of termination.

13. When the Tribunal finds that the termination of service is not justified, the question of awarding back wages is the discretion of the Tribunal. That discretion has to be exercised judiciously. Where the employee was gainfully employed during the enforced idleness that has to be taken into account, where there is delay in raising industrial dispute, that has to be taken into consideration in awarding back wages [1989 (II) LLJ. 86 (Andhra Pradesh] (Indian Airlines Vs. A. Philips).

In the present case there is no evidence that the concerned workman was gainfully employed during the period of inforced idleness. On the other hand, the concerned workman has described himself as unemployed person (sitting idle). There is no evidence on record that the concerned workman has made delay in raising the present industrial dispute. So, he, in my view, is entitled to full back wages from the date of termination of his service till he is reinstated.

14. Accordingly, the following award is rendered—

> the action of the Chairman, Mithila Kshetriya Gramin Bank, Darbhanga, in terminating the service of Kishore Jha, casual worker, by letter dated 16-9-85 is unfair and unjustified. The order of termination of service of Jha is hereby set aside and the management is directed to reinstate him in service with full back wages and other consequential benefits within one month from the date of publication of the award. The concerned workman is directed to report for duty within the time stipulated as aforesaid.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का.आ. 2287.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सिक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 21 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस-11017/10/81-डी-1 (ए)]

एस.एस पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2287.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Security Paper Mill, Hoshangabad, which is covered item 21 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/10/81-D.I (A)]
S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का.आ. 2288.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट, बम्बई को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/3/85-डी-1 (ए)]
एस.एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2288.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the India Government Mint, Bombay which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/3/85-D.I (A)]
S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का.आ. 2289—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जमूरिया ए एण्ड बी पिट्स कोलयरी आफ मैसर्स ई सी लि. के प्रबंधतंत्रके संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/99/90-आई आर (सी-II)]
राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2289.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamuria A & B Pits Colliery of M|s. E. C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-8-92.

[No. L-22012/99/90-IR(C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 37|90

PRESENT :

Shri N. K. Saha,
Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Jamuria A & B Pits Colliery of M|s. E.C. Ltd.
AND
Their Workman

APPEARANCES :

For the Employers.—Sri. P. Banerjee Advocate.
For the Workman.—Sri. B. Kumar, Joint Secretary of the Union

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

New Delhi, the 24th July, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(99)|90-IR(C.II) dated the 26th August, '90.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jamuria A & B Pit unit of Sripur Colliery under Sripur Area of M|s. ECL in not regularising Shri Abdul Rahaman, Fitter (M) as Asstt. Foreman (M) from the year 1981 basing on the jobs performed by him, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from what date ?"

2. To-day (24-7-92) Sri Bijoy Kumar the learned representative of the union submits that he has no instruction from the union to proceed with this case and makes endorsement to that effect in the order-sheet.

3 In such circumstances it appears to me that no dispute exists and as such a no dispute award is passed in this case.

Sd/-
N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का० आ० 2290—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजोर कोलयरी वानी एरिया डब्ल्यू टी एल के प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/43/91 आई आर (सी-II)]
राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2990.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajur Colliery Wani Area, WCL and their workmen, which was received by the Central Government on 27-7-92.

[No. L-22012/43/91-IR(C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

SHRI P. D APSHANKAR

PRESIDING OFFICER

Reference No. CGIT-2|40 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Rajur Colliery, Wani Area, WCL.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management—(1) Shri G. S Kapur, (2) Shri B. N. Prasad Advocates.

For the Workmen—No appearance.

INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 26th June, 1992

AWARD

The Central Government by their order No. L-22012|43| 91-IR(C-II) dated 29-7-1991 have referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947.

"Whether the termination of service of Shri Soma Kisan Dhawas, Casual Loader by the Sub Area Manager, Rajur Colliery WCL, Wani area Dist. Yaotmal from 6-7-1988, is justified and legal If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The notices of this reference were duly served upon both the parties. Accordingly the advocate for the management appeared before this tribunal since the beginning i.e. 12-9-1991. The workman remained present only on 10-4-1992 He had remained absent on all the dates from 12-9-1991 to 21-12-1992. He also remained absent on 23-4-1992, 23-6-1992, and on 25-6-1992.

3. The said workman had challenged the justification of the action in question by the management. Therefore it was for the workman to file the necessary statement of claim challenging the action in question, and also then to lead the necessary evidence in support of his case. However, the workman remained absent, and as such failed to file the necessary statement of Claim, and also failed to lead the necessary evidence in support of his case challenging the action of the management in dismissing him from services.

4. Therefore, the present Reference stands disposed of.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का० आ० 2291—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/81/एफ/91 आई आर (सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2291.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 27-7-92.

[No. L-22012/81/F/91-IR(C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 101|1991

In the matter of dispute between :

Sri Kripa Shanker,
C|o. Sri T. B. Singh,
41|417 Jail Bhawan,
Narhi Lucknow.

AND

The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
6 Habibullah Estate,
Hazaratganj Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. 22012|82|91 I.R. (D.U.) dated 3-7-91, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow, is justified in imposing the penalty of dismissal from service to Sri Kripa Shanker Ahirwar AG. III with effect from 7-3-88 in violation of principle of natural justice ? If not, to what relief the workman is entitled ?

2. The workman's case is that he joined the service of Food Corporation of India as a messenger on 17-7-71, and was promoted as A. G. III (D) by Zonal Manager (North), in 1976 and joined as A. G. III (D) on 2-4-76. On the other hand the case of the management is that the workman was appointed as a Watchman in Food Corporation of India at Jhansi, on 13-7-71 and was promoted as A. G. III (D) vide order dt. 5-4-78.

3. The admitted facts are that the workman was suspended on 25-11-85, and was served with chargesheet dt. 28-2-87 issued by the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow. Ext. W.5 is the copy of chargesheet. The charges are as follows :—

ARTICLE I :

Kripashanker A. G. III (D) while posted and functioning as Ic Sector 'D' at Airstrip Lalitpur during the year 1984 and 85 failed to maintain absolute integrity and devotion to duty and to serve the corporation honestly and faithfully in as much as he failed :—

(a) to maintain proper and uptodate stock accounts in the prescribed manner and to render periodical accounts|returns.

(b) to attend airstrip Lalitpur regularly.

(c) to protect of the stock of wheat stored at CAP from losses|damages during storage; &

(d) to maintain and preserve the stocks and to carry out regular inspections and to provide treatments to the socks.

Due to above acts and criminal negligency and failure on the part of said Sri Kripashanker, the corporation had suffered huge financial losses on account of storage loss|shortages and damages to the stocks, besides damaging the image of the corporation in public and loss to the national property,

Thus Sri Kripashanker A G. III (D) has contravened Regulations 31 and 32 of the FCI Staff Regulations, 1971

Sri B. P. Goel Deputy Manager was appointed Enquiry Officer. He held the charges as proved. The Senior Regional Manager, F.C.I. accepted the finding given by the E.O. and vide his order dt. 7-3-88, copy Ext. W-14, dismissed the workman with immediate effect. An appeal preferred by the workman was also dismissed by the Zonal Manager.

4. The workman has assailed the order of punishment on a number of grounds. He has alleged that the charge-sheet was vague, he has also alleged that the inquiry was not conducted fairly and properly by the E.O. He has further alleged that the finding given by the E. O were perverse. The other pleas raised by the workman are that prior to the awarding of punishment the copy of the inquiry report was not furnished to him and that Senior Regional Manager was not his disciplinary authority but his Disciplinary authority was the Zonal Manager (North). The workman has, therefore prayed for quashing of order of punishment for his reinstatement with back wages together interest at the rate of 24% per annum on the amount of back wages.

5. The management in their written statement have denied all the grounds on which the order of punishment has been assailed by the workman. According to the management the disciplinary authority for category III employees to which the workman belonged is the Senior Regional Manager. On 2-4-1992, Shri T. B Singh, the authorised representative for the workman, alongwith the workman, submitted that the workman would simply be challenging the order of his dismissal from service on the ground that the Sr. Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow was not competent to pass the said order as he was not the disciplinary authority of the workman. After the making of the said statement it was submitted by the authorised representatives for the parties that they had not to lead any oral evidence I may state here that the only the workman has filed documents most of which have been admitted by the authorised representative for the management.

6. Thus the only point to be determined in this case is whether or not Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow, was the disciplinary authority of the workman. I may state here that it was submitted Shri T. B. Singh, authorised representative for the workman, that in the case of the workman, the Zonal Manager, was the disciplinary authority.

7. During the course of this arguments, Shri Singh, was invited my attention to a number of documents to which I shall refer now.

8. Ext. W-16, is the copy of notification dated 16-10-1987. From the notification it appears that Regulation 56 was substituted by FCI (Staff) (90th Amendment) Regulations 1987, with immediate effect. The substituted regulation 56 lays down that the authority specified in appendix (ii) would be the disciplinary authority. From the appendix it appears that in the case of category III Staff, Senior Regional Manager is the Disciplinary Authority. Explanation to Regulation 56 reads as :—

Appointing Authority in relation to an employee for the purpose of this Regulation shall be read as under :—

(i) the authority empowered to make appointments to the post/grade which the employee for the time being holds ; or

(ii) the authority which appointed the employee to such post/garde as the case may be whichever authority is the higher authority.

9. Ext. W-13 is the copy of office order dated 15-3-1978 issued on behalf of the Zonal Manager (North), regarding promotion of category IV officials to category III. At Serial No. 81, the name of the workman appears. Thus this office order shows that it was by the order of the Zonal Manager that he was promoted from category IV to Assistant Grade III (D).

10. Ext. W-15 is the copy of order dated 9-1-1992, of the Hon'ble Mr. Justice S. Saghir Ahmed, of the Hon'ble High Court of Judicature Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in Writ petition No. 665 of 1992, Dhanpati Singh Versus Food Corporation of India and others. It was observed by His Lordship that as the petitioner was promoted to the post of A. G. Gr. I (D) by the Zonal Manager, it would be the Zonal Manager who would be the appointing authority of the petitioner as provided by Regulation 56 of Food Corporation of India (Staff) Regulation, 1971.

11. It follows, therefore, that since in the instant case of the workman the order of promotion from category IV to A.G. II (D) was passed by the Zonal Manager (North) his appointing authority would be the Zonal Manager and not the Senior Regional Manager who ordinarily is the disciplinary authority/punishing authority of category III Staff. The proposition of law laid down by the Hon'ble Judge, has not been challenged before me by the authorised representative for the management.

12. We have seen above that amended Regulation 56 came into force on 16-10-1987 and the chargesheet issued to the workman is dated 26-2-1987. It follows, therefore, that the chargesheet was rightly issued by the Senior Regional Manager, Lucknow, who at that time happened to be both the appointing and disciplinary authority of the workman. However, the situation changed w.e.f. 16-10-1987, as from that date onwards the senior Regional Manager ceased to be the disciplinary authority/appointing authority of the workman in view of the amended Regulation 56.

13. Ext. W-9 is the copy of order dated 7-3-1988 of the Senior Regional Manager, by means of which the punishment of dismissal from service was awarded to the workman. Since as said by me above, the Senior Regional Manager ceased to be the disciplinary authority/appointing authority of the workman the order passed by him cannot be sustained. The order should have been passed by the Zonal Manager under whose order the workman was promoted from category IV to A. G. III (D).

14. Hence, the order of punishment dated 7-3-1988 passed by the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow, in his capacity as disciplinary authority is quashed and the workman is reinstated with full back wages. In the circumstances of the case, neither any interest on the amount of back wages nor any costs are awarded to the workman.

15. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का० आ० 2292.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/289/89-आई आर (कोल-II)]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2292.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 27-7-1992.

[No. L-22012/289/89-IR(C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR KANPUR.

Industrial Dispute No. 129 of 1990

The State Secretary,
Bhartiya Khadya Nigam Karamchari Sangh,
Regional Office,
Lucknow.

AND

The Sr. Regional Manager,
Food Corporation of India,
1 Abdul Aziz Road, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-22012|289|89-I.R. (Col. II) dt. 24-4-90| 2-5-90. has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

"Whether the action of the Senior Regional Manager Food Corporation of India in imposing penalty on Sri Chhotey Lal Assistant Grade III in violation of natural justice and denying him promotion and additional increment on acquiring qualifications while in service, was justified? If not, to what relief the workman concerned entitled ?"

2. The industrial dispute on behalf of the workman has been raised by Bhartiya Khadya Nigam Karamchari Sangh Lucknow (hereinafter referred to as Union), through its secretary. Admittedly the workman was appointed by Senior Regional Manager as A.G.III(M) vide his order dt 18-4-72. In persuance of the said order the workman joined the said post on 24 4-72. Subsequently vide order dt. 3-3-76 of the Zonal Manager (North) he was promoted as A.G.II(M) and vide order dt. 23-4-87, of the Zonal Manager (North) he was promoted as A.G.I(P). But the later promotion was not released.

3 It is further admitted case of the parties that the management of the Food Corporation of India introduced a scheme vide circular no. 40 of 1985 that such workman as had acquired LL.B degree during their service period, they will be entitled for two additional increments w.e.f 1-4-85. The workman acquired LL.B degree in 1972 from the Lucknow University. On the basis of acquisition of LL.B Degree he applied to the management for grant of two additional increments in the light of the said circular.

4. It is also admitted case of the parties that the Regional Manager, Food Corporation of India, served the workman with chargesheet dt. 19-5-87. The charges were—

While posted at Regional Office, Lucknow, in Fertilizer Branch Sri Chhote Lal Asstt Gr II (M) failed to serve the Corporation honestly faithfully sincerely and devotedly. Said Sri Chhote Lal AG-II(M) was deputed to maintain sale day book (BE-5) of fertilizer and he did not locate the short fall of Rs. 49858.11 against M|s. Chandu Lal Vijai Kumar, Muzaffarnagar. The said amount was timely realised from the said party against LC before its expiry and as such amount remained unrealised.
Sri Chhote Lal, AG-II(M) put the corporation to loss due to his gross negligence, slackness and undue favour to party ignoring the interest of FCI Thus Sri Chhote Lal AG-II(M) contravened regulation 31 and 32 of FCI (Staff) Regulation, 1971

Sri D. V. S Raju who was appointed E.O. held inquiry into the said charges and held the charges as proved Senior Regional Manager while acting as disciplinary authority accepted the finding given by the E.O. and by means of his order dt. 16-7-88 Ext W-40 awarded penalty of reduction in rank from AG-II(M) to AG.III(M) with immediate effect with the direction that the pay of the workman be fixed at the minimum of the scale of time scale of AG III(M).

5. The workman filed an appeal against the order of punishment passed by the Senior Regional Manager, and the same was rejected by the Zonal Manager (North) by means of his order dt. 10-6-89.

6. The Union alleges that the promotion of the workman from AG.II(M) to A.G. I(M) was withheld by the management arbitrarily and without any justifiable reason. The Union has, further alleged that two additional increments on the basis of acquisition of LL.B Degree by the workman were not released by the management. The Union has challenged the order of punishment on a number of grounds but on 9 6-92 which was a date fixed for hearing arguments it was submitted by Sri T. B. Singh, the authorised representation for the Union that the Union assails the order of punishment dt. 16-7-88 passed by the Senior Regional Manager only on the ground that he was not competent to pass it as he was not the disciplinary authority of the workman within the meaning of explanation to the proviso of the amended Regulation 56. In view of this statement I need nor refer to other grounds on which the order of punishment has been assailed by the Union.

7. The Union has, therefore, prayable for quashing the order dt. 16-7-88 passed by the Senior Regional Maanger and the order dt. 10-9-89 passed by the Zonal Manager (North). The Union has also prayed for grant of relief of promotion to the workman from A.G.II(M) to A.G.I(M) w.e.f. 23-4-87 alongwith consequential benefits. Lastly, the Union has proved that the two additional increments be also ordered to be released on the basis of the workman having acquired the degree of LL.B.

8. With regards to the orders dt. 16-7-88 and 10-6-89 passed by the Senior Regional Manager and the Zonal Manager (North), are concerned, the management plead that they are perfectly in order and that they were passed by the competent authority. As regards withholding of promotion of the workman from AG. II(M) to AG.I(M) the management plead that since the workman was involved in a serious vigilence case, his promotion order was not considered for release by the Regional Head Lucknow Region. Moreover, the workman could not claim promotion as a matter of right. As regards non release of two additional increments on the basis of acquisition of LL.B qualification by the workman, the management plead that the circular in question is not applicable to his case as he had competed his study of LL.B course prior to joining the services of the Food Corporation of India. Moreover the workman did not fulfil the required mandatory preconditions. He was also involved in a serious vigilence case which was pending against him at that time A legal plea has been raised by the management that the dispute referred to by the Central Government to this Tribunal is not an industrial dispute within the meaning of section 2(k) I.D. Act, 1947.

9 In support of their respective cases both sides have led oral as well as documentary evidence. Whereas the workman| Union has examined the workman the management have examined Sri Israr Hussain Deputy Manager (Vigilence) The following 3 points call for determination in this case—

1 Whether the order of punishment passed by Regional Manager is illegal ?

2. Whether the action of the management in withholding the promotion of the workman from AG.II(M) to AG.I(M) was justified ?

3 Whether the workman is entitled to the grant of two additional increments on account of his holding the degree of LL.B.

Let us consider the above three points seriatum

Point No. 1 —

10. Ext W-40 is the copy of order of punishment dt. 16-7-88 passed by Senior Regional Manager and Ext. W-42 is the copy of order dt. 10-6-89. of the Zonal Manager (North) rejecting the appeal of the workman filled by him against the order of punishment.

11. Annexure 3, to the affidavit of the workman is the copy of notification dt. 16-10-87 by means of which existing regulation 56 came to be substituted w.e.f. the date of notification. The proviso to the amended Regulation lays down that the penalties such as reduction in rank, compulsory retirement, removal from service or dismissal from service would not be imposed on any employee by an authority lower than the appointing authority. The explanation to the proviso says that appointing authority in relation to an employee for the purpose of this Regulation shall be as under :—

(1) The authority empowered to make appointments to the post/grade which an employee for the time being holds; or

(2) The authority which appointed an employee to such post grade as the case may be; whichever authority is the higher authority.

12. We have seen above that the order of promotion of the workman from AG.III(M) to AG. II(M) was passed by the Zonal Manager (North). Similarly the order of promotion dt. 23-4-87 from A.G. II(M) to A.G.I(M) was passed by the Zonal Manager. These two orders on behalf of the Zonal Manager (North) were issued by Deputy Manager (Admn.) and Assistant Manager (P.II) respectively. Copies of these orders are Ext. W-2 and Ext. W-3 respectively. Ext W-44 is the copy of order dt. 9-1-92 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad Lucknow Bench, Lucknow, in Writ Petition No. 665 of 1992, Dharpati Singh Versus Food Corporation of India. It was a case of an employee of Food Corporation of India who was appointed on the post AGIII(D) and was subsequently promoted to the post of A.G.II(D). He got another promotion of A.G.I-(D) under the orders of the Zonal Manager. It was held by the Hon'ble High Court that the Zonal Manager would be the appointing authority of the employee as directed by Regulation 56 of F.C.I. (Staff) Regulation 1971. In the said writ petition it was further held that the Senior Regional Manager had no jurisdiction to pass the impugned order of dismissal against the employee as his appointing authority was the Zonal Manager, who is higher in rank than the Senior Regional Manager. While expressing this view the Hon'ble High Court relied upon the decision given by it in writ petition nos 9043 of 1989 decided on 8-8-91 and writ petition no. 7240 of 1991 decided on 1-11-91.

13. The facts of the present case are similar to the facts of the writ petition no. 665 of 1992, hence it is held that the order of punishment dt. 16-7-88 passed by the Senior Regional Manager is illegal. It is liable to be quashed. Point no. 1 is decided accordingly.

Point No. 2.—

14. Ext. W-3 is the copy of orders dt. 23-4-87 of the Zonal Manager (North) promoting 8 persons including the workman who is named at serial no. 6 working as AGII(M) as A.G.I(M). In the order of promotion a direction has been given to the effect that before the persons named are promoted it should be got insured that no vigilence case is pending or contemplated against them. In para 43 of the written statement it has been pleaded by the management that since the workman was involved in a serious vigilence case, his promotion order was not considered for release by the Regional Head of Lucknow Region. So this was the main hitch in the matter of promotion of the workman as A.G.I(M).

15. It has been now found by me that the vigilence case which resulted in the passing of order of punishment against the workman has no legs to stand upon in view of my finding on point no. 1. Therefore, there no longer remains any obstruction in the matter of promotion of the workman from A.G.II(M) to A.G.I(M) in persuance of the order of promotion dt. 23-4-1987.

16. It is to be seen now as to from what date the promotion from A.G.II(M) to A.G.I(M) to the workman should be granted. In this regard Sri T. B. Singh, the authorised representative for the Union has placed reliance on the ruling in the case of C.O. Arumugam Versus State of Tamil Nadu 1990 (60) FIR 26 (SC). It was held in the said case that the promotion of a person against whom a charge has been framed in the disciplinary proceedings may be deferred till the proceedings are concluded. However he may be considered for promotion if he is exhonarated or acquitted of the charges. If he is found suitable he should be given promotion with retrospective from the date on which his juniors were promoted. No ruling to the contrary has been cited before me by the authorised representative for the management. Hence, it is held that although the action of the management in withholding the promotion of the workman was justified at that time in view of the contemplated departmental proceedings, but in view of my finding isue no. 1 the said justification has ceased to exist and in view of the ruling referred to above the workman is entitled to his promotion in persuance of the order of promotion dt. 23-4-87, from the date on which his junior was promoted in persuance of the said promotion order.

17. Point no. 2 is decided accordingly.

18. Point No. 3 :

In the claim statement it is stated by the Union that the workman initially joined the service of F.C.I. as A.G. III(M) on 24-4-72. In para 6 of the claim statement it is stated by the Union that he acquired LL.B Degree in 1972 from Lucknow University. The claim of the workman is resisted on the ground by the management that the circular No. 40 of 1985 dt. 29-7-85 which came into force w.e.f. 1-4-84 relied upon by the Union in support of the case of the workman has no application to the case of the workman as the workman acquired LL.B qualification prior to his employment in FCI.

19. Annexure A to the claim statement is the copy of circular no. 40 of 1985 dt. 24-7-85 issued by the Head Office of the FCI at New Delhi and Ext. W.44A is copy of Head Office Circular no. 64 of 1986 dt. 15-10-86 issued by the head office of the FCI at New Delhi giving clarifications on certain points raised in connection with the implementations of the previous circular no. 40 of 1985. One of the point raiesd is mentioned at serial no. 6 and it is to the effect whether employees passing additional qualification at the time of joining the Corporation should also be given incentive increments or not. The clarification which was given by the head office was that since in the case of such employees their professional qualification at the time of joining Corporation was taken into consideration for the purposes of appointment for a suitable post in the Corporation, they are not entitled for any incentive increments in the scheme.

20. It is not denied before me by Sri Singh, the authorised representative for the Union that the workman acquired LLB qualification before his joining the service of the FCI. Thus a classification has been mate by the management and those who had acquired additional qualification as mentioned in circular No 40 of 1985 before the joining the service of the Corporation shall not be entitled to two additional increments by way of incentive as such additional qualification had been considered at the time of joining the service by them and that only such employees as had acquired additional qualifications during their service period will only be entitled to such additional increments.

21. The classification does not seem to be arbitrary or unjust. It could be that if at the time of joining service they had not possessed any of the additional qualifications mentioned in circular no. 40 of 1985 they might not have been selected for the post to which they were selected. Hence to my mind the workman cannot be given the benefit of the circular in question.

22. Point no. 3 is decided against the Union.

23. In view of the findings recorded above it is held that the action of the Senior Regional Manager in awarding the workman punishment of reduction on rank was illegal and unjust. It is held that the workman is entitled to his promotion as A.G.I(M) from the date from which his junior was promoted as A.G.I.(M) in persuance of the order of promotion dt. 23-4-87. It is further held that the workman is not entitled to any additional increments under circular no. 40 of 1985 dt. 29-7-85, as the circular does not apply to his case, he having acquired LL.B qualification prior to his joining the service of the F.C.I.

24 Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का० आ० 2293:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कोलाम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27/7/92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/39/एल/89 आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2293.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 27-7-92.

[No. L-22012/39/F/89-IR(C.II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, KOLLAM

(Dated, this the 16th day of July, 1992)

PRESENT :

Shri C. N. Sasidharan, Industrial Tribunal

IN

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 107/89

BETWEEN

The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Regional Office City corporation Building, Trivandrum-691001.
(By Sri M. P. Kuttappan, Advocate, Trivandrum)

AND

The Secretary, Food Corporation of India Employees' Association, City House, Malloor Road, Vanchiyoor, Trivandrum-695035.

(By Sri R. Lakshmana Iyer, Advocate, Trivandrum)

AWARD

This industrial dispute has been referred for adjudication by the Government of India as per Order No. L-22012(39) F/89-IR (C-II) dated 26-9-1989.

The issue for adjudication is the following :

"Whether the present practice followed by the Management of M/s. Food Corporation of India in the matter of deploying workmen to man higher posts is fair and justifiable ? If not, to what relief the workmen thus deployed, including those listed in the Annexure-A are entitled ?"

The union espousing the cause of the workmen involved in this dispute has filed a detailed claim statement and the contentions briefly stated are as under : The Food Corporation of India (FCI for short), the management this case is engaged in the procurement, transportation, storage and distribution of food grains throughout India and the corporation has appointed large number of employees for this purpose. There are four categories of employees and this union represents the employees under categories II, III and IV, There are various grades for the employees under these categories. In the year 1974 the management introduced a new policy of deployment of employees from a lower post to higher post and from a lower category to higher category. There is no provision in the Staff Regulations enabling the management for such deployment. The management resorted to such deployment under the guise of avoiding delay in filling up the higher posts. The employees are virtually asked to man the higher posts without allowing them the emoluments attached to such posts. They are paid nominal deployment allowance i.e. Rs. 10/- for category IV, Rs. 20/- for deployment against post of Assistant Gr. II and Gr. I and Rs. 25/- for deployment against post of Assistant Manager. As per circular dated 9-11-1979 the rates of deployment allowance in some of the higher categories was slightly revised. It was stated in that circular that deployment allowance would be admissible for a maximum period of 180 days and during which period all efforts would be made to fill up the posts on regular basis. The deployment was contemplated as a purely interiem measure and every effort should be taken to fill up the higherposts on regular basis with all expedition. But the management failed to comply with such direction and the deployment of employees continued indefinitely. Artifical break of one or two days on paper used to be introduced. The period of deployment raised upto a period of six years. Majority of the 141 workmen mentioned in the Annexure to the order of reference had put in two to six years service in the higher posts as deployment. But they were being paid only a nominal allowance. The management has been taking the stand that the acceptance of such an arrangement is not compulsory. But the management had initiated disciplinary action and imposed punishment on several workmen for not accepting such deployment. The arrangement introduced by the management by deploying the workmen to higher posts on payment of nominal allowance is in gross violation of the principles of equal pay for equal work. It is arbitrary also. The management has been able to avoid timely promotions to higher posts and deprived the workmen of the benefit of higher emoluments attached to higher posts. The practice of deployment is unfair and unjustifiable. The workmen are entitled to get higher emoluments attached to such posts legally and to get them treated as having been regularly promoted to such higher posts. The management has shown discrimination also in denying higher emoluments to the workmen. The claim of the union is for getting higher emoluments attached to higher posts in which they are deploying and also for treating deployment as regular promotion in the higher posts with effect from date of deployment and also all consequential service benefits.

3. The management while opposing the claim of the union has advanced their contentions in the reply statement which briefly stated are as under : The recruitment to various categories of staff, their promotions, seniority etc. are governed by the FCI (staff) Regulations 1971 (the Regulation for short) and those provisions are strictly adhered to by the management. Interim arrangements are made from time to time with regard to exigencies of service which are not covered by the Regulations. This interim arrangements are never intended to circumvent the Regulations but are subject to it. As per staff Regulations mode of recruitment in Asstt. Gr. III (category III) is 70 per cent by direct recruitment of criteria and 30 per cent by promotion from lower grade with lesser educational qualifications. Absence of persons possessing the requisite experience was a contingency as per the circular of the FCI. The deployment scheme was envisaged as an interim measure to meet the contigency arising out of the absence of sufficiently experienced FCI employees in the lower grade/category eligible for promotion. Employees when deployed are given deployment allowance as prescribed in the special circular since they are not eligible to draw salary attached to the higher posts and to which they will be eligible only when regularly promoted. Deployment is on the basis of District/Regional seniority. Regular promotion on the other hand is on the basis of zonal seniority. Promotion to non-selection posts on the basis of seniority cum fitness is prepared by a promotion board. The promotion panel thus prepared is for the whole southern zone comprising the four regions on the basis of zonal seniority in the case of category IV. Such regular promotion necessarily involved transfers and consequently vacancies in the higher posts remain unfilled. Vacancies will also arise in various stations due to retirement, death, resignation etc. For the smooth running of the operations of FCI it is absolutely necessary to carry out the current duties of such vacant posts. The deployment scheme is introduced to meet such situations. Such deployment is made without detriment to the promotion scheme on regular basis of the more senior staff elsewhere in the zone and purely on an optional basis. As per circular dated 25-1-1974 the service rendered by persons on deploy-

ment will not be counted for promotion or for fixation of seniority in the higher grade or posts. The deployment is optional and hence it is not unfair. The total monetary benefits to the employees on deployment is substantial. The management has further revised and enhanced the rate in 1979. Persons on deployment are eligible for deployment allowance for a maximum period of 180 days only. The particulars of deployment stated in the Annexure are incorrect in most cases and full of mistakes. Deployment is never intended to be a substitute for promotion. The principle of equal pay to equal work is not applicable here. The pay attached to higher posts is admissible only when persons eligible for promotion on the basis of their seniority in the promotion panel are appointed as stipulated in the Staff Regulation. If the persons on deployment are treated as regularly promoted employees with effect from the date of deployment it will affect the claims of their seniors in the lower posts awaiting promotion on the basis of their seniority. They are necessary parties in a dispute of this nature. The dispute is therefore defective for non-joinder of necessary parties. The management denies all other allegations levelled by the union. According to the management the workers are not entitled to any relief.

4. The evidence consists of the depositions of four witnesses as WW1 and WW4. and Exs. W1 to W28 on the side of the union. The management has examined their Asst. Manager as MW1 and Exts. M1 to M3 have been marked on the side of the management.

5. The complaint of the union is mainly that the practice of deployment followed by the management in the matter of deploying workmen to man higher posts is unfair and unjustifiable. According to the union the management has followed this practice under the guize of avoiding delay in filling up the higher posts. Further, there were sufficient number of qualified hands for promoting to the higher posts but the management resorted to the practice of deployment for depriving the concerned workmen of the benefit of higher emoluments attached to higher posts and the management was able to save a very huge amount. But according to the management the practice of deployment was only a stop gap arrangement for a period of 180 days and the workmen were paid deployment allowance as per Ext. M1 circular dated 25-1-1974. It has come out in evidence that there were eligible hands for promotion to the higher posts, Exts. W4 and W5 seniority lists are of the year 1987. But the practice of deployment was followed by the management as per Ext. M1 circular which was accepted by the workman. The workmen accepted deployment, discharged the duties of the higher post to which they were depolyed and accepted deployment allowance as per the circular without raising any objection what so ever. The validity of the circular was also not challenged by the workmen or their union till this dispute. Even according to the union the workmen continued in the highers posts on deployment for several years without raising any kind of objection. They cannot therefore now turn round and contend that the practice of deployment followed by the management as per circular issued as early in 1974 is unjustified. Further, the workmen are bound to do the duties ordered by the management as per circulars issued by it. It is also the prerogative of the management to allot work to their workmen for the smooth functioning of the establishment. So long as validity of such a circular was not disputed for the last several years from 1974 and the workmen discharged the duties as per Ext. M1 circular and accepted the allowance it is not open for them to contend now that the practice of deployment is unjustified. Admittedly the practice of deployment is not in force now. The management has introduced this practice as per Ext. M1 circular which was accepted by the workmen without any demur and continued the practice since 1974. In the light of the above discussion I have no hesitation to hold that the practice of deployment followed by management is fully justified.

6. The next claim of the workmen involved in this case is for payment of remuneration attached to the higher posts on deployment and also for treating them as regular promotees in higher posts with effect from the date of deployment. The deployment of the workmen is not in dispute. It is also not disputed that the deployment is not in existence now. According to the management the deployment is only a temporary arrangement and the workers are paid deployment allowance as per circular of 1974 and that the workers are not entitled for any other benefit as per Ext. M1 circular. But the evidence tendered by WWs 1 to 4 provisions that the workers deployed to man the higher posts were discharging the entire duties attached to that posts. WW2 who was a watchman was deployed in 1983 in Gr. III. He has deposed that he had done all duties of clerk Gr. III while on deployment and he was not given washing allowance which was paid to him while working as watcher. The non payment of washing allowance itself prove that WW2 was not discharging the duties of watchman and fully discharging the duties of Gr. III clerk during the period of deployment. WW3 was a messanger in Gr. IV and he was deployed in 1984 in tapal section in Gr. III post. She has deposed that she had discharged all the duties of Gr. III while on deployment. Ext. W15 to W18 tapal registers and W19 to W21 inward registers prove the duties discharged by WW3 as Gr. III. According to this witness she had not done the duties of messenger but discharged all the duties of Gr. III in tapal section. She has stated in detail the duites done by her in tapal section on deployment. WW4 who was a watchman was deployed as Gr. III clerk. This witness has stated that he had prepared truck chit, daily statement of deposit and daily statement while on deployment as Gr. III clerk. Ext. W23 series truck chits, W24-series daily statements of deposit and W25 to W27 daily statements are written by WW4 according to him. WW4 has further deposed that while on deployment washing allowance was not given to him which was eligible for a watchman. The evidence of WW2 to WW4 and the documents mentioned above clearly establish that the workmen on deployment had discharged all the duties attached to the higher posts to which they were deployed. Further, it has come out in evidence through MW1, the witness examined on the side of the management, that a person who had written truck chit and gate pass can be said to have discharged the duties of Class-III employee. But these workmen were paid only deployment allowance and not paid the remuneration attached to the higher posts in which they were deployed and discharged the entire duties of such higher posts. The action of management is violative of the principles of equal pay for equal work as enshrined in Article 39 of the Constitution of India and against constitutional mandate. It is a clear case of exploitation also. The workers who were deployed have the legal right to get higher emoluments for discharging duties attached to such higher posts in which they were deployed. The non payment of the emoluments attached to such higher posts is a clear case of discriminat on also. It is true that the deployment allowance was increased slightly as per Ext. W2 circular in the year 1979. But even then the allowance was only a meagre amount of Rs. 30|-. It has come out in evidence through WW4 that he would have got Rs. 100|- if he had been promoted to the higher posts to which he was deployed. In this state of affairs the claim of the workmen for the emoluments attached to the higher posts in which they were deployed is legal and fully justified.

7. The next point to be considered is whether the workmen who have been deployed can be treated as regular promotees in the higher posts with effect from the date of deployment and whether they are entitled to get all consequential service benefits. It is not disputed that recruitment and promotion in FCI are governed by Ext. M2 staff Regulations. MW1 has deposed that for promotions there is zonal promotion committee in the Madras office of the management. This is not disputed by the union. Regular promotion is on the basis of zonal seniority which is maintained for all district|Regions of zone. The statement of management regarding the procedure of promotion that the panel of candidates for promotion is prepared by a promotion board is also not rebutted by the union. But the deployment is from the concerned unit and only unit seniority is considered according to MW1. This witness has further stated that no zonal seniority was being considered for deployment. So the workmen who have been deployed cannot be treated as regular promotees in the higher posts though they had discharged all the duties attached to such posts. Such workmen were deployed from a unit. On the other hand promotions are made on the basis of zonal seniority and as per clause No. 10 of Ext. M 2 Regulations on the basis of consideration by promotion board. In these circumstances the present claim of the workmen is not at all justified.

8. From the discussions made above it is clear that the practice followed by the management of FCI in the matter of deploying the workman to man higher post is fair and justifiable. However, the workmen are entitled to get higher

emoluments attached to the higher posts to which they have been deployed with effect from the date on which they have been so deployed. But such workmen cannot be treated as regular promotees in the higher posts as claimed by the union.

An award is passed in the above terms.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witnesses examined on the side of the Workmen :

WW1. Sri Pushpadharan K. R.

WW2. Sri P. V. Mohanan

WW3, Smt. C. Padmam

WW4. Sri M. N. Gopi

Witness examined on the side of the Management :
MW1. Sri T. Gopi

Documents marked on the side of the Workmen :

Ext. W1. Circular issued by the management dated 25-1-1974.

„ W2. Circular issued by the management dated 9-11-1979.

„ W3 Memo issued to Sri Pushpanagadhan, Asst. Gr. II from the management dated 4-4-1984.

„ W4. True copy of seniority list of Class-IV employees published by management as on 31-12-1987.

„ W5 True copy of seniority list of Watchman, Messengers etc. as on 30-10-1987.

„ W6. Covering letter attached to seniority list of Asst. Gr. II.

„ W6A. Seniority list of Asst. Gr. II as on 31-12-1988.

„ W7. List of employees deployed by the management.

„ W8. List of employees deployed from the Trivandrum Regional Office of the management and orders of deployment.

„ W9. List of employees deployed from the District Office Kollam of the management and orders of deployment.

„ W10. List of employees deployed from the District Office Cochin of the management and orders of deployment.

Ext. W11. List of employes deployed from the District office Trissur of the management and orders of deployment.

W12. List of employees deployed from the District Office Palghat of the management and orders of deployment.

„ W13. List of employees deployed from the District Office Kozhikode of the management and orders of deployment.

„ W14. List of employees deployed from the District Office Cannanore the management and orders of deployment.

„ W15. Tappal register of the Trivandrum Regional Office of management for the period from 25-9-1987 to 14-12-1987.

„ W15-A. Page No. 62 of Ext. W15.

„ W16. Tappal register of the Trivandrum Regional Office of management for the period from 5-12-1986 to 30-6-1987.

„ W16A. Page No. 269 to W16.

„ W17. Tappal register of the Trivandrum Regional Office of management for the period from 1-3-1988 to 4-1-1989.

„ W17-A. Page 66 of Ext. W17.

„ W17-B. Page 234 of Ext. W17.

„ W18. Tappal register of the Trivandrum Regional Office of the management for the period from 4-4-1988 to 4-1-1989.

„ W18-A. Pages 1 to 23 of Ext. W18.

Ext. W19. Inward register of the Trivandrum Regional Office of management for the period from 4-6-1984 to 19-11-1985.

„ W19-A. Page 231 of Ext. W19.

„ W20. Inward register of the Trivandrum Regional Office of management for the period from 11-12-1984 to 12-6-1985.

„ W20-A. Page 27 of Ext. W20.

„ W21. Inward register of the Trivandrum Regional Office of management for the period from 13-3-1985 to 19-11-1985.

„ W21-A. Page 29 of Ext. W21.

„ W22. Tappal register of the Trivandrum Office of management for the period from 2-1-1986 to 31-12-1986.

„ W22-A. Page 253 of Ext. W22.

„ W23. series (8 nos.) Truch chits.

„ W24. Series (3 nos.) Daily statements of issues from depots.

„ W25. Daily statement dated 14-4-1987.

„ W26. Daily statement of issues dated 11-10-1988.

„ W27. Daily statement of issues dated 10-10-1988.

„ W28. Circular issued from the Trivandrum Regional Office of management dated 17-12-1991.

Documents marked on the side of the Management :

Ext. M1. Photocopy of Ext. W1.

„ M2. Staff Regulations of management.

„ M3. Copy of promotion list of the management prepared in the zonal office.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का० आ० 2294.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रामनागोरे कोलयरी आफ मैसर्स आई–आई एस० सी० ओ० लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-7-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-19012/111/86-जी-II(बी)]
राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1992

S.O. 2294.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramnagore Colliery of M/s. IISCO Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 27-7-1992

[No. L-19012/111/86-D.IV (B)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 38 of 1988

Parties : Employers in relation to the management of Ramnagore Colliery of M/s. IISCD. Ltd.

AND

Their Workmen.

Present :

Mr. Justice Manash Nath Roy,
Presiding Officer.

Appearance :
On behalf of
Management—Mr. Niloy Ghosh, Advocate.
On behalf of
Workmen—Mr. S.K. Bose, Advocate.

State : West Bengal Industry : Coal.

AWARD

By-rder No. L-19012(111)/86-D.IV(B) dated 23rd April 1987, the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whereas the action of the management of Ramnagore Colliery of M/s. IISCO Ltd. in not regularising the workmen as mentioned in the Annexure on the post on which they are working and paying them the wages for the appropriate category admissible to the job done by them with protection of wages wherever necessary is justified ? If not, to what relief they are entitled ?"

Annexure

Sl. No.	Name	Designation	Post on which working
1.	Shri Jiten Gorh	Line Helper	Pump Khalasi
2.	,, Souri Pada Das	Gen. Mazdoor	Electric Helper
3.	,, Ramesh Chandra Dass	do	do
4.	,, Gopal Bouri	Timber Mistry	Timber Mistry (High Category)
5.	,, Naru Bouri	Timber Mazdoor	Timber Mistry
6.	,, Peru Turi	Line Helper	Line Mistry
7.	,, Parosuram Harijan	Mason Helper	Mason
8.	,, Babu Mallick	Gen. Mazdoor	Fan Helper
9.	,, Jagnnath Ghosh	Pump Helper	Pump Khalasi
10.	,, Hublal Rabidas	Explosive Carrier	Timber Mazdoor
11.	,, Pyrelal Rabidas	Spray Mazdoor	do
12.	,, Shankar Ghosh	Trammer	Tyndal
13.	,, SadhuBhandari	Explosive Carrier	Tub Mazdoor
14.	,, Some Majhee	Line Helper	Line Mistry
15.	,, Sadan Mandal	Gen. Mazdoor	Filter Helper
16.	,, Madhusudan Ghosh	do	do
17.	,, Monikanchan Bhandari	do	do
18.	,, Jagannath Paul	Machinist	Turner
19.	,, Babu Mia	Piece Rated Mazdoor	Onsetter
20.	,, Munilal Misra	Tuyndal	Foreman
21.	,, Anil Kumar Das	Clerk	Despatch Clerk
22.	,, Lalicha an Majhi	U.G. Loader	Turner
23.	,, Laljhi Bhar	do	Dresser
24.	,, Narayan Singh	do	Trammer
25.	,, Sadhu Bouri	do	Trammer
26.	,, Ramjas Rabidas	do	Haulage Khalasi
27.	,, Khelari Rabidas	do	Onsetter

2. After the dispute as mentioned, was referred to this Tribunal for adjudication, pleadings were completed on due service of the notice.

3. When the case is called out today, the Secretary of the Union has stated that the matter has been settled out of court to which the other side has also agreed. That being the position, the reference is disposed of without going into the merits on the basis of the statements as made at the Bar

Dated, Calcutta,
The 7th July, 1992.

MANASH NATH RAY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1992

का० आ० 2295.—औद्योगिक अविवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42018/5/88-डी-IV (बी)]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2295.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industiral Tribunal, Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 4-8-1992.

[No. L-42018/5/88-D.IV (B)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 29/89

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri Devendra Singh S/o Shri Jeewan Singh, Village Walipur, P.O. Ladpur, District Bulandshair (U.P.)

Versus

The District Manager, Food Corporation of India, 29-B.N. Road, Lucknow.

APPEARANCES :

Workman—in person.

Shri Manni Lal—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42018/5/88-D.IV (B) dated 15-2-87 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the Management of Food Corporaion of India in terminating services of Sri Devendra Singh, Watchman w.e.f. 20-11-1986 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The workman in his statement of claim alleged that he was appointed as Watchman in F.C.I. on regular basis vide office order dated 31-10-72 and confirmed vide order dated 19-9-73. Unfortunately he was involved in a domestic quarrel and convicted by the court in 1973. After few months imprisonment he was released from jail on mercy petition accepted by Governor of U.P. After being released from Jail he resumed his duties in 1974 and performed the same to the best satisfaction of his superiors. Again in 1976 his family circumstances became worse and he remained on leave for 1-1/2 year due to the murder of his elder brother. On having received a telegraphic order from D.M. F.C.I. Lucknow he again joined his duties on 26-6-78. On his joining he was placed under suspension by the District Manager F.C.I. He made representation repeatedly to the authorities but no action was taken. He remained under suspension for 8 years and finally he appealed to the Dy. Zonal Manager, FCI who recommended his revocation through a D.O. letter to Sr. R.M., FCI U.P. Region, Ignoring all the rules and regulation of the FCI District Manager FCI finally dismissed his services vide order dated 20-11-86 without assigning any reason and without giving any opportunity to explain his conduct. This termination was illegal against law and passed on 21-11-86 with retrospective effect from 26-6-78.

3. The Management in its written statement alleged that the workman was appointed because of misrepresentation and concealment of facts about his involvement and conviction in a case under section 148/452/307/323 and 324 I.P.C. He was not involved in any domestic enquiry. Remission of sentence under section 432 Cr. P.C. does not mean that the conviction has been set aside. It only empower the Appropriate Government to remit the sentence and release the convict. The workman had been absent during the period from April, 74 to June, 78 when he resumed duties on 26-6-78. This was unauthorised absence. The workman was put under suspension because he was convicted under verious sections of the I.P.C. Section 52 of the I.P.C. deals with the punishment of the person who commits house tress pass and such a person could not be retained in the service as Watchman. No opportunity of hearing is required by law in case where an employee has been convicted by competent Court of law. The disciplinary authorities have considered all relevant facts and passed the order of termination according to law.

4. The Management examined Shri C. P. Pandey MW-1 while the workman himself appeared as WW-1.

5. I have heard representative for the parties and have gone through the record.

6. The representative for the management has urged that the C.G.I.T. Delhi has no jurisdiction to hear this case because the workman was employed in the State of U.P. and the order was passed by the District Manager Lucknow and only CGIT Kanpur had jurisdiction to hear this case. It has further been argued on merits that according to the FCI Staff Regulation 1971 Clause IV(f) lays down that no person shall be eligible for appointment who has been convicted in any court of law under any offence involving moral turpitude. Clause 32-A (17) prohibits an employee from the commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude and Clause 49(11) provides that "Nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to the competent authority regarding such action". The workman, however, concealed his conviction and did never intimate the facts to the FCI. Due to his prolonged absence from duty a report was called from the District Authorities of Bulandshair, his home town when the management came to know about his conviction in various criminal offences. A notice was also published in the Newspaper on 16-6-78 whereafter applicant reported on 26-6-78 and was placed under suspension for misconduct. His convictions has been admitted by the workman himself and the mere fact that his sentence was remitted by the Governor does not mean that his conviction has been set aside. The Order passed by the Management was legal and unquestionable.

7. The representative for the workman on the other hand has urged that the workman never concealed the facts of his conviction and he was placed under suspension under Regulation 66(1)(a) of the FCI Regulation for prolonged leave and was not placed under suspension under Regulation 66(2)(b) which provides suspension for conviction in a criminal case. Since he was not suspended for his conviction but for absence from duty so his termination on that ground was also illegal. He has further urged that the effect of remittance of his sentence by the Governor amounted to acquittal. He has also referred to a case of one Mahabir Singh Watchman who was convicted in similar charges but taken back by the FCI even after dismissal due to conviction in the criminal case. The order of dismissal was, therefore, illegal and discriminatory.

8. The point that this court has get no jurisdiction has not been substantiated by any role by the representative for the management. No specific distribution of jurisdiction amongst the CGITs in India debarring the territorial jurisdiction of the other has been brought to my notice nor any such order has further been received in this office vide which the jurisdiction of this Tribunal could be carried only to the territorial jurisdiction of Delhi. There is thus no force in this preliminary objection of the management.

9. A careful perusal of the point urged before me by the representative for the parties leads me to the definite conclusion that the workman was undoubtedly and admittedly convicted by a Court of law for thh offence stated in the written statement which includes house tress pass. The provisions in the FCI Staff Regulation 1971 making any person eligible for appointment on conviction by a Court of law for an offence involving moral turpitude. All these offences for which he was convicted do amount to moral turpitude and the fact that the Hon'ble Governor of U.P. had remitted his sentence does not help the applicant except to the effect that he was not supposed to undergo further imprisonment. The Order of conviction, the proof of his guilt do not get set aside and the fact that he was convicted does not stand abolished from his record due to certain compassionate grounds or some other grounds put before the Hon'ble Governor for his sentence being remitted. The remission of sentence does not make him entitled to all the facilities of the job where he was working because his continuance in the service would further depend upon the rules and regulations of the department under which he is employed. It is the employer for to decide the future of the employee. If these rules do not permit him to continue in the job or call for any action, the mere fact that his sentence has been remitted cannot come to his help. That factor was to be examined by the Management which they have done in this case and keeping in view all the circumstances I am of the view that the order of termination passed by the management does not call for any interference by this Tribunal. I, therefore, hold that no illegality seems to have been committed and the order of termination of the services of the Watchman Devender Singh was justified and no relief could be granted by this Tribunal. Parties shall, however, bear their own costs.

July 1, 1992.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का०आ० 2296.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार परबेलिया कोलयरी आफ मैसर्स ई० सी लि० के प्रबंधतंत्र के संम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 4-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/123/90-आई आर (सी-II)]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2296.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industiral Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the dispute between the employers in relation to the management of Perbelia Colliery of M/s. E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-8-1992.

[No. L-22012/123/90-IR (C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 43/90

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employer in relation to the Management of Parbelia Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman—Sri Bijoy Kumar, Joint Secretary of the Union.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 28th July, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. 22012|123|90-IR (C-II) dated the 21st September, 1990.

SCHEDULE

"Whether the management of Parbelia Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd., Po. Neturia, Dist. Purulia was justified in not recording the year of birth as 1938 as per Identity Card issued by the erstwhile management in the newly constructed Form 'B' register ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. Today (28-7-92) Sri Bijoy Kumar the representative of the union submits that he has no instruction from the union to proceed with this case and makes endorsement to that effect in the order-sheet.

3. In such circumstances it appears to me that no dispute exists and as such a no dispute award is passed.

Dated : 28-7-1992.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का० आ० 2297.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सोडेपुर (आर) कोलयरी आफ मसर्स ई सी लि० के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/378/91-आई आर (सी-II]

राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2297.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sodepur (R) Colliery of M/s. E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-8-1992.

[No. L-22012/378/91-IR-(CII)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 21/92

PRESENT :

Shri N. K Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Sodepur (R) Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri B. N. Lala, Advocate.
For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 28th July, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/378/91-IR(C.II) dated the 12th/21st May, 1992.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Sodepur (R) Colliery, E.C. Ltd., P.O. Sunderchak, Dist. Burdwan, in terminating Shri Drupat Ahir, Mining Sirdar from the year 1987 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Today (28-7-92) Sri B. N. Lala, the learned Advocate for the management is present. None appears for the union. It appears to me from the conduct of the union that the union is not interested to proceed with the case. The union has not filed written statement though the notice was duly served upon the union on 4-6-92.

3. In view of the circumstances I have no other alternative but to pass a no-dispute award and accordingly a no-dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का. आ. 2298.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न कोलफील्डस लि., के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/176/89-आई आर (सी-II)]
राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2298.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-8-1992.

[No. L-22012/276/89-IR(C.II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE HON'BLE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(59)/1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Ltd., Patherkhera District Betul (M.P.) and their workman, Shri Mayaram, represented through the Organiser, Hind Mazdoor Kisan Panchayat, Pathakhera Office, Jagjivan Nagar, New Bus stand, Pathakhera, District Betul (M.P.)-460449.

APPEARANCES :

For workman—None.

For Management—Shri A. K Sashi, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mining. DISTRICT : Betul (M.P.).

AWARD

Dated, 31st January, 1992

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012(276)/89-IR(Coal-II) dated 19th February, 1990, for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of the Management of the General Manager, Western Coalfields Ltd., Pathakhera, in not providing light job to Sri Mayaram, T. No. 2398, is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The workman/union raised the present dispute and the reference was made vide Notification dated 19th February, 1990. But inspite of several opportunities given to the workman to file the statement of claim etc. neither the workman nor the Union took any interest in prosecuting the case by filing the statement of claim. Even none appears on any date of hearing on behalf of the workman. It appears that the workman has no interest in the case.

3. In the circumstances, I have no alternative but to pass a No dispute Award. I accordingly pass a No Dispute Award with no order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का.आ. 2299.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/215/एफ/91-आई आर (सी-II)]
राजालाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2299.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-92.

[No. L-22012/215/F/91-IR (C.II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PENDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 7 of 1992

In the matter of dispute between :

Vice President,

Food Corporation of India,

Workers Union C-1783 Rajajipuram,

Lucknow.

AND

District Manager,

Food Corporation of India,

29 V. N. Road, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification number L-22012|215|F|91 IR(C-II) dated 23-1-1992 has referred the following dispute for adjudication :—

Whether the District Manager, Food Corporation of India, Lucknow, was justified in not regularising the services of following workmen in their Talkatora Depot ? If not to what relief these workmen were entitled to ?

1. Sri Raman s|o Ram Lal
2. Sri Uma Shanker s|o Mahavir
3. Sri Tilak s|o Sri Jawahar
4. Sri Santu s|o Rupan
5. Smt. Lakhpata Devi w|o Mangal Ram
6. Sri Mano ram s|o Babu Lal
7. Sri Maikulal s|o Bhagwan Din
8. Sri Sant Ram s|o Bansraj
9. Sri Girjanandan s|o Ram Pal.

2. In this case first date for filing of the claim statement was 30-3-1992 but none appeared on behalf of the Union Sri P. C. Nigam appeared on behalf of the management. However, 6-5-92, was fixed as the next date in the case and notices were ordered to be issued to the Union for the next date. Since on 6-5-92 the P. O. was on leave hence the case was ordered to come up on 25-6-92.

3. Again on 25-6-92 none appeared from the side of the Union nor the claim statement in the case was filed. It therefore appears that the Union is not interested in prosecuting the case.

4. Therefore, in view of the above, a no claim award is given in the case.

5. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त 1992

का. आ. 2300.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जमुरिया ए एण्ड बी पिट्स कोलयरी आफ मैसर्स ई.सी. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/99/90-आईआर(सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2300.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamuria A & B Pits Colliery of M|s. E. C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-8-92.

[No. L-22012/99/90-IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL,

Reference No. 37|90

PRESENT :

Shri N. K. Saha.

Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Jamuria A&B Pits Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the Employers.—Sri P. Banerjee, Advocate.

For the Workman.—Sri B. Kumar, Joint Secretary of the Union.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 24th July, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(99)|90-IR(C.II) dated the 26th August 1990.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jamuria A&B Pit unit of Sripur Colliery under Sripur Area of M|s. ECL in not regularising Shri Abdul Rahaman, Fitter (M) as Asstt. Foreman (M) from the year 1981 basing on the jobs performed by him, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from what date ?"

2. To-day (24-7-92) Sri Bijoy Kumar the learned representative of the union submits that he has no instruction from the union to proceed with this case and makes endorsement to that effect in the order-sheet.

3. In such circumstances it appears to me that no dispute exists and as such a no-dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का. आ. 2301.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भगवान दास एंड कं. दादापारा स्टोन क्वरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/11/89 आई आर (विविध)]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O.2301.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bhagwan Das & Co. Dhadapara Stone Quarry and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-8-92.

[No. L-29012/11/89-IR (Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 23 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of M|s. Bhagwan Das and Co. Dhandapara Stone Quarry.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri J. D. Lall, Advocate.

For the Workmen.—Shri D. Mukherjee, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY . Stone Quarry.

Dated, the 16th July, 1992

AWARD

By Order No. L-29012|11|89-I.R. (Bibidh), dated, the 8th March, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of M|s. Bhagwan Das and Co., Dhadapara Stone Quarry, in terminating the service of Shri Santosh Kumar Pandey, Mining Mate w.e.f. 17-7-1987 is legal and justified. If not, what relief is the workman entitled to ?"

2. The case of the management of M|s. Bhagwan Das & Co., Dhadapara Stone Quarry, P.O. Pakur, Dist. Sahibganj (Bihar), as disclosed in the written statement, details apart, is as follows :

Santosh Kumar Pandey, the concerned workman, had been working as Mining Mate since 1984 in Dhadapara Stone Quarry Mines of M/s. Bhagwan Das & Co. P.O. Pakur Distt. Sahibganj (Bihar). Before that he was working as Superviser of Mine since 1975. As Mining Mate the concerned workman was responsible for general supervision of mining work next to the Manager. He was responsible for proper functioning of mines, proper utilisation, working and maintenance of various mining machineries, deployment of labourers and miners and proper maintenance of various statutory records. He was also officiating as Manager from time to time during absence of the Mining Manager. Thus the concerned occupied a responsible position and position of trust. However, he did not come upto the expectation of the management and indulged in various omission and commissions and neglect of work and indulged in mal-practices thereby betraying the trust and confidence of the employers reposed in him. He failed to discharge his duty as regards proper functioning and working of drill rods and their maintenance, as a result, serval drill rods were broken and became useless resulting in huge financial loss to the company. The work of the company also suffered due to want of drill rods. He was warned by the management in this regard but he did not pay any attention to his work and continued to neglect his work in this regard. He also did not obey order|instruction of the management in regard to deployment of labourers where urgent work was required and as a result company's work suffered during rainy season. He also unauthorisedly kept various statutory records in his house and in spite of order instruction to keep these records in the office of the mine and not to take them to his house, he did not return the records to the management. He also unauthorisedly realised sale proceeds amounting to Rs. 640 from the customers by sale of stone dust and when he was directed to deposit the money, he failed to do so. Because of above mentioned misconducts the management lost confidence on him and did not think it proper to keep him in service and terminated his service by order dated 17-7-87. It was not possible for the management to hold a formal enquiry as long as the concerned workman remained in service inasmuch as he could have influenced the witnesses because of his position. That apart, it would have delayed the appointment of a new hand in his place without which the working of the mines would not be possible. The management are ready to prive the misconducts as mentioned above before this Tribunal by adducing evidence in support of termination of service of the concerned workman. Termination of his service is quite legal, justified and bonafide in the interest of the business of the company. The concerned workman has since joined the service of M|s. Durga Stone Works, Pakur, after his services were terminated by the employer. The employers are small Entrepreneur who can ill afford to keep a person like the concerned workman in a position of trust and responsibility and confidence. In the circumstances, the action of the management in terminating the services of the concerned workman with effect from 17-7-1987 is quite legal and justified.

3. The case of the concerned workman, as appearing in the written statement submitted by him, is as follows :

He was originally appointed as Mining Mate on 1-1-1974 at Dhadapara Stone Mine of M|s. Bhagwan Das & Co. He had been working continuously and put in 240 days attendance in each calendar year. It is alleged that the management still believe in the theory of hire and fire and so the management terminated his service with effect from 17-7-87 without following the mandatory provision of Sec. 25-F of the Industrial Disputes Act. He represented before the management against the illegal and arbitrary retrenchment with a prayer to reinstate him in service with full back wages, but the anti-labour management refused to settle the issue amicably which forced him to raise the industrial dispute before Asstt. Labour Commissioner (C) under Section 2-A of the Industrial Disputes Act. The conciliation proceeding ended in failure due to the non cooperative and adamant attitude of the management. The appropriate Government has been pleased to refer the dispute before this Tribunal. The action of the management in terminating his service with effect from 17-7-87 is illegal arbitrary and against the principle of natural justice. In the circumstances, the concerned workman has prayed for reinstatement in service with full back wages.

4 In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has disputed that the concerned workman had worked continuously and in the process had put in 240 days attendance in each calendar year. The service of the concerned workman was terminated on the ground of various acts of misconducts as mentioned in the letter of termination and also as mentioned in the written statement. No representation by the concerned workman was received by the employer and there was no question of reinstating him because he made serious acts of misconduct

and lost confidence of his employer. The termination of service of the concerned workman is justified and he is not entitled to reinstatement in service with full back wages.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the concerned workman has stated that it is false to allege that he was responsible for general supervision of mining work next to the manager or that he was responsible for proper functioning of mines, proper utilisation and working and maintenance of mining machineries. He has stated further that it is absolutely false to suggest that it was his duty to deploy mining men, or that he was working as Manager from time to time in the absence of the Mines Manager. Expectation of the management was that the workmen would render service without taking wages and he could not fulfil such expectation. He has denied that he was ever been warned by the management as alleged. He has also denied that he has committed any neglect of work or had kept unauthorisedly any statutory records in his house or that he did not deposit sale proceeding amounting to Rs. 640 received from any customer on any day. His services were terminated without following the mandatory provision of law. He has further stated that it is absurd to suggest that it was not possible for the management to held proper enquiry. As per settled law of the land, the management has got no right to adduce evidence for alleged imaginary acts of omissions and commissions on his part.

6. In order to justfy its action the management has examined two witnesses, namely, MW-1 Sarbeshwar Jha and MW-2 Tufani Prasad and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. M-1 M-8.

On the other hand, the concerned workman has examined himself and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. W-1 to W-2.

7. The case of the management is that Santosh Kumar Pandey, the concerned workman, had been working as Mining Mate since 1984 in Dhandapara Stone Quarry Mines of M/s. Bhagwan Das & Co. and before that he was working there as Supervisor since 1975. The concerned workman has claimed that he was originally appointed as permanent Mining Mate on 1-1-74.

Parties arrayed have not filed any document in support of their respective contention. MW-1 Sarbeshwar Jha described himself as Incharge of the Stone Quarry sometime since February, 1987, has stated that the concerned workman Santosh Kumar Pandey, was a Mining Mate and he was looking after and supervising the working of the mine. The concerned workman has admitted in his testimony that he get letter of authorisation under the Rules and can produce it to show that he had been working as Mining Mate since 1-1-1974. But in the next breathe he has admitted that he was working as Mining Mate since 1983 and before that he was working as blaster from 1980 and before that he was working as helper to Mining Mate from 1-1-74. It appears from the evidence on record that he was holding the post of Mining Mate when his service was terminated on 17-7-87.

8. Shri J. D. Lall, learned Advocate for the management, has contended that the services of the concerned workmen were terminated for various acts of misconducts, but the management could not hold any domestic enquiry. He has further submitted that the management has got right to adduce evidence to prove the misconduct of the concerned workman. According to him, the management has also right to adduce evidence with regard to commission or omission of acts relating to performance of duty which are misconduct where there is no Certified Standing Orders.

Shri D. Mukherjee, learned Advocate for the concerned workman, has contended that the management has got no right to adduce evidence in support of alleged acts of misconducts as no chargesheet was issued to or received by the concerned workman.

9. In my view, the management has a right to adduce evidence with regard to the acts of misconduct allegedly committed by the concerned workman even though no formal chargesheet was issued to the concerned workman. The letter of termination of service of the concerned workman discloses various acts of misconducts. In my view, the management has a right to adduce evidence to prove these acts of misconduct. I am fortifide in this view by the decision reported in 1978 Lab. I.C. 1096 (SC) (Municipal Corporation of Greater Bombay VS P. S. Malvenkar & Ors). But the second contention of Shri Lall, in my view, is neither sound nor acceptable. Admittedly, Hadapara Stone Quarry has get no Certified Standing Orders for its workmen. Section 12-A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1947 envisages that prescribed Modal Standing Orders shall be deemed to be adopted in the establishment where there is no Certified Standing Orders. This being so, Modal Standing Orders in respect of industrial establishment not being industrial establishment in coal mines shall be applicable in the case of workman of Dhadapara Stone Quarry.

10. Before going to the heart of the case with regard to the alleged misconduct of the concerned workman, it is necessary to decide and dispose of certain points. The written statement submitted by the employers in this case on 20-10-89 was signed by Bhagwan Das himself. The earlier written statement submitted by the employer and received in the office of the Tribunal by post on 21-3-89 was signed by one Suresh Kumar on 15-3-89 presumably on behalf of Bhagwan Das. This Suresh Kumar, according to evidence of MW-1 Sarbeshwar Jha, is the brother of Bhagwan Das.

11. It appears that one Ganga Ram reported to Jhaji, presumably Sarbeshwar Jha, about negligence allegedly committed by the concerned workman with respect to handling of drill rods. He suggested that the concerned workman be warned in the matter (Ext. M-1). The evidence of Sarbeshwar Jha discloses that he directed the concerned workman to behave himself and execute his work properly. He has proved a letter addressed to Ganga Ram whereby he communicated that he had informed Shri Pandey to avoid loss of drill rods and informed also that the concerned workman had sold stone dust worth of Rs. 640 but did not deposit the amount with the company (Ext. M-2). In cross-examination he has stated that he does not know whether these documents Exts. M-1 and M-2 were submitted before A.L.C. (C) while conciliation proceeding was going on. This being the position, it is doubtful if these two documents were issued at all whom the dispute was pending before A.L.C. (C). Thereafter Ganga Ram issued a purported letter of warning to the concerned workman through Sarbeshwar Jha (Ext. M-3). The concerned workman has firmly stated that he did not receive any letter of warning from his employer. Sarbeshwar Jha has stated that he was directed to deliver the warning letter to the concerned workman and that he presented the letter to the concerned workman who refused to accept the same. There is an endorsement in this letter by Sarbeshwar Jha that the concerned workman refused to accept the leter after reading it. Now the question remains as to why the management did not issue that warning letter by registered post. There is no positive answer to this question. The concerned workman, on the other hand, has stated firmly that he never refused to carry out the order of his employer. In this context it is necessary to consider the status of Ganga Ram and his connection with Dhadapara Stone Quarry.

Sarbeshwar Jha has stated in his examination-in-chief that Ganga Ram is one of the Partners of the Company and that he was looking after the mine on behalf of the other Partners of the Company. In cross-examination he has admitted that Ganga Ram was the owner of Ghatapara Stone Mine and Bhagwan Das informed the Mines Department about the ownership of the mine. He has further admitted that Bhagwan Das and Co. was never a Partnership or a Limited company. It remains inexplicable as to how Ganga Ram could be a Partner of Bhagwan Das when it is not a partneship or limited company. The concerned workman has asserted firmly that Bhagwan Das is the owner of the company. From the evidence on record, I come to the conclusion that Ganga Ram was practically a non entity in Bhagwan Das & Co. There is nothing on evidence to indicate that he was looking after Dhadapara Stone Quarry under instruction from Bhagwan Das. This being so, he had no authority to issue orders either to Sarbeshwar Jha or to the concerned workman.

12. The letter of termination of service of the concerned workman was also issued by Ganga Ram (Ext. M-4).

In the letter of termination (Ext. M-4) several acts of misconducts have been alleged against the concerned workman, such as, (i) damage of drill rods due to negligence of the concerned workman, (ii) keeping of registers, books, diary etc. of the company by the concerned workman and (iii) non-deposit of sale proceed of stone dust amounting to Rs. 640 with the company. MW-1 Sarbeshwar Jha has stated that after drilling the concerned workman was not taking out drill rods and consequently after blasting of rerods were damaged or broken. During tenure of service some 15 to 20 rods were damaged leading to a loss of Rs. 400 on avegare per rod. In cross-examination he has admitted that drillers are responsible for drilling and that the concerned workman himself was not doing the operation of drilling. He was doing this work through the agency of other workmen. He has admited hat there can be no bigger whole than the diameter of the drill rods and unless the drill rods are removed explosive can not be put into the holes for drilling. He has further stated that he could not say if any of driller was visited with any charge-sheet. If explosives are put in the holes for blasting and if explosives cannot be put in the hole unless the drill rods are removed, the question of damage to the drill rods after blasting cannot normally arise. The concerned workman has also denied and disputed this fact firmly. Considering the entire operation of blasting as appearing in evidence, I held that there is hardly any scope for damage of the drill rods after blasting because explosives cannot be applied to the holes unless the drill rods are removed. Besides Drillers are responsible for drilling. There is no evidenc on record that the management has taken any action against any of them. This being so, I come to the conclusion that the charge of negligence, of duty and causing damage to the drill rods as ascribed to the concerned workman is not sustainable.

The next charge is keeping of records etc. of the company by the concerned workman in his custody. The letter of termination does not disclose actually what were statutory records etc that the concerned workmen kept in his custody. There is nothing in evidence in writing to show that the management directed him to return these records that the management has taken any action against any of them. This being so, I come to the conclusion that the charge of negligence of duty and causing damage to cogent evidence to prove this charge against the concerned workman.

The third charge is of non-deposit of sale proceed of stone dust amounting to Rs. 640 in the coffers of the company. The evidence on record reveals that Sarbeshwar Jha records etc. that the concerned workman kept in his custnot deposit the sale proceeds of stone dust worth Rs. 640 in the company. In order to estabilsh this charge it must be proved that (a) there was stone dust (b) that it was sold by the concerned to customer, and (c) that he received Rs. 640 as sale proceeds and (d) he did not deposit the amount with the company There is no evidence on record except ipse dixit of Sarbeshwar Jha that the concerned workman did not deposit the sale proceeds of Rs. 640. In order to prove that the concerned workman did not deposit the amount it has to be proved that he received the amount as sale proceeds of stone dust. There is no evidence on this score Stock Register of the Company has not been produced. Customer to whom stone dust was sold has not been examined. That being so, this charge also must founder on the ground.

13 Admittedly, the management terminated the service of the concerned workman without complying mandatory provision of Sec. 25-F of the Industrial Disputes Act. It has been attempted by the management to show that the concerned workman was gainfully employed elsewhere in Ramchandrapur Stone Mine of Shree Durga Stone Works. The management has produced a letter issued by Nabin Kumar Mishra, Manager of Shree Durga Stone Works stating that the concerned wrokman had been working in Shree Durga Stone Works from 4-11-87 till the date of issuance of the certificate on 1-4-89 Prescribed form submitted to the Director General of Mines Safety by the management of Shree Durga Stone Works for grant of Manager's permit has been produced by the management (Ext. M-5) Here also the concerend workman has been described as Mate. Sarbeshwar Jha has also stated that after he was dismissed from service the concerned workman started working in Shre Durga Stone Works of which Kuldip Singh was the Proprietor. The concerned workman of course denied this. But in this context of evidence on record, I am constrained to hold that he was gainfully employed in Shree Durga Stone Works for sometime after termination of his service.

Sarbeshwar Jha has further stated that the concerned workman has since left the service of Shree Durga Stone Works and has been working in Nalhati in the district of Birbhum But this statement of his is not supported by any documentary evidence.

The present reference for adjudication of the dispute was made on 8-3-1989. There is no knowing of the fact when the concerned workman left the service of Shree Durga Stone Works In the circumstances, the concerned workman, in my view, is entitled back wages with effect from 8-3-89 upon reinstatement in service.

14. Accordingly, the following award is rendered—

the action of the management of M/s. Bhagwan Das and Company, Dhadapara Stone Quarry in terminating the services of Santosh Kumar Pandey, Mining Mate, with effect from 17-7-87 is not justified. The management is directed to reinstate him in service and to pay him back wages with effect from 8-3-1989 with continuity of service and other benefits within one month from the date of publication of the award in official Gazette. The concerned workman is directed to join his duties within the time prescribed.

In the circumstances of the case, I award no cost.

This is my award.

S. K. MITRA, Presidng Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का. आ. 2302.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार न्यू बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-3-1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/337/81-डी-2(ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2302.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of New Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 31-7-1992.

[No. L-12012/337/81-D-2A]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 187/83

In the matter of dispute between:

Shri Suraj Prakash Sharma, 35-A, East Azad Nagar, Shahdara, Delhi-51.

Versus

The General Manager,
New Bank of India,
Tolstoy Marg.
Atma Ram House,
New Delhi.

APPEARANCES:

Shri P. P. Trikha for the workman

Shri N. C. Sikri, Sr. Advocate with

Shri V. K. Rao, Advocate for the Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012(337)/81-D.II(A) dated 11-5-83 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of New Bank of India in terminating the services of Shri Suraj Prakash Sharma, temporary Peon w.e.f. 1-7-92 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The claimant Mr. Suraj Prakash in his Statement of claim has alleged that he was appointed w.e.f. 19-12-75 at Ghaziabad Branch of the Bank and was posted to lookafter and check the movement of the stock in the godown of factory of M/s. Rathi Ispat Ltd. an allied concern at Ghaziabad, against which the Bank had made advances, that it was his duty to watch and safeguard the bank's interest involved in such stock. That the claimant as such was one of the Godown Watchmen employed by the bank for the aforesaid purpose, there being four such godown watchmen, two for the day-time and two for the night, their names being :—

1. Shri Chatar Singh,
2. Shri Satpal Singh Sharma, and
3. Shri Roop Chand Sharma.

3. That the claimant has further alleged that besides watching the godown in the factory as aforesaid, he was also looking after the goods that were pledged/hypothecated against the advances. That other godown watchmen too, as aforesaid were similarly engaged and were also performing the same duties as were performed by the claimant.

4. That pursuant to the aforesaid arrangement, the salary of the claimant was credited to his Saving Bank Account maintained with the Branch and as such, this arrangement continued. However, he, for the first-time, made a representation to the General Manager of the Bank in May, 1979 asking for his confirmation in the permanent staff i.e. for his regularisation in view of his temporary assignment. The bank, instead of regularising him, discontinued the arrangement w.e.f. 1-7-79 without assigning any reason, note or order for such discontinuation/termination. Accordingly, he has stated that his termination by the bank is unjustified and illegal in terms of the provision of Sastri/Desai Award, Bipartite Settlement dt. 19-10-66 and as such he has claimed his reinstatement with continuity of employment.

5. The case of the Bank is that there is no relationship of master and servant between the claimant and the Bank. He was not issued any appointment letter because of the fact that here was no privity of contract and/or relationship of master and servant between the Bank and the claimant. The bank has further stated that, in fact, the Central Govt. had previously accepted the contention case of the Bank and have refused to make the reference and as such the Bank has further alleged that the reference in question has been made at the bank of the bank without giving any opportunity in this behalf.

6. Both the parties have led their evidence in support of their respective contentions. The bank has further asserted that to the knowledge of the claimant, the other persons were similarly engaged as the claimant, had agitated the matter through their recognised Majority Union and the matter was settled as per the Undertaking/Settlement with the said Union viz :—

(i) That such other persons as the claimant herein have been engaged as peon as their had been no vacancies of watchmen with the bank w.e.f.

(ii) That the bank was prepared to treat him similarily at par with other persons, of course without prejudice to its rights and contentions. Significantly, the aforesaid averments of the Bank has not been repudiated by the claimant and instead he had made the following as the partinent admission :—

"That he was not made any offer of employment by the Bank as peon and that he was also ready for amicable settlement."

7 That on the above aspect, the bank has contended that it was always willing and ready to engage the claimant as a peon with the same terms and conditions as done in the case of other similarity situated persons/colleagues of the claimant persuant to the settlement/understanding with the Union viz.—

— That he would be engaged as peon ;

— That he would be given national seniority without any other benefits/backwages w.e.f.

8. That according to the Bank the fault lies with the claimant in not accepting the aforesaid offer at the material time alongwith his other colleagues.

9. I have perused the record and the bank representative has been reiterated the said offer besides in the written statement even in the written arguments as well with an emphasis that now that the bank is a public undertaking and as such another authority within the meaning of Art. 12 of the Constitution of India, the bank cannot give any discriminatory treatment for the obvious reason that

it would be violative of Art. 14 of Constitution of India, besides the propriety warrants that he be treated at par with other colleagues as done by the bank, more so in the larger interest of industrial peace and harmony, keeping in view the sanctity of the settlement|understanding reached in this behalf.

10. I have considered the rival contentions of the parties and also pressed the record. Without in any way going into the rival contentions of the parties, the matter can be adjudicated upon on the short aspect of the settlement as arrived at by the Bank with the majority recognised Union vis-a-vis other colleagues| persons, who were similarly engaged as the claimant herein viz—

1. Shri Chatar Singh;
2. Shri Satpal Singh Sharma; and
3. Shri Roop Chand Sharma

as aforesaid, which is not a disputed fact either.

11. In industrial adjudication, much weight and importance has been given by the Hon'ble Supreme Court in respect of settlement, more so in the larger interest of industrial peace and harmony. I am convinced by the aforesaid submissions of the Bank representative and it is supported by various decisions of the Hon'ble Supreme Court and High Courts as well. However, there is one aspect which requires consideration is in respect of benefits in respect thereof the parties are at issue and or at variance, the contention of the bank being that he was offered the post of peon even during conciliation proceedings, while the claimant ascert that it was not. But pertinent feature is that the bank has repeatedly given such offer even in its pleadings before this Tribunal and again reiterated the offer during the proceedings, which the claimant, I would say, has not responded timely.

12. In the peculiar circumstances, I am of the opinion that justice would be met if the claimant Mr. Suraj Prakash is given the assignment at party with his other colleagues in terms of the settlement as aforesaid; that he will be deemed to have been engaged as peon notionally w.e.f. 1st July, 1979 with continuity of service and as far as his back wages are concerned, he would be entitled to 25 per cent of the salary or wages that he would have drawn on 1-7-79 on such assignment as Peon, without any other benefits whatsoever. It is, however, further made clear that in view of my above findings, he will be entitled to the notional seniority, the claimant accordingly will be entitled to such benefits of seniority in terms of the settlement. Parties shall bear their own costs.

16th July, 1992.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1992

का. आ. 2303—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/636/86-डी. 2 (ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी।

New Delhi, the 6th August, 1992

S.O. 2303.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-8-1992.

[No. L-12012|636|86-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 129 of 1988

PARTIES :

Employer in relation to the management of United Bank of India

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice Manash Nath Roy, Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Management : Mr. Anil Kumar, Raw Officer of the Bank.

On behalf of Workmen : Mr. Depak Sarangi, Jt. Secretary with Mr. B. Chatterjee, President of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

On the question of justifiability of the action of the Management of United Bank of India (hereinafter referred to as the Bank, in terminating the services of (1) Sri Sambhu Kabiraj; and (2) Ashok Kumar Mondal, when who were claimed to be empanelled temporary sub-staff, and not considering them for further employment under Section 25H of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) and to what relief they were entitled, this Tribunal, by Order No. L-12012|636|86-D. II(A) dated September 7, 1987, was constituted, for adjudicating the matter.

2. The case of the employee concerned were represented by the United Bank of India Employees Association Central Committee, for short referred as

the said Union and they by their statement, claimed that under the relevant and prevelant Rules of the Bank, Recruitment to the temporary staff is made on invitation of applications and forming a panel thereafter, on the basis of selection. Such steps are stated to be taken by the Superintendent of Establishment and by the Banks' Agents in respect of Branches. The relevant provisions will appear from Ext. W-9, which has also been stated to be existing and continuing with some minor and necessary modifications. It has further been indicated that after completing the above process, for candidates interviewed and selection at the Branches, list is prepared, and sent to the Head Office, who in their turn, arrange the lists of successful candidates in order of merit and return them, to the respective Branches, with the direction that appointments of temporary staff to the Branches should be made according to seniority with the concurrance of the Head Office. It has further been stated that if, in case an employee, sent by the Head Office was not available on a given day for any reason whatsoever the Branches could appoint the person next to the said absentee candidate, as appearing from the list sent by the Head Office. The Head Office, it has been stated, maintains the seniority list and issues the appointment letters.

3. It was also the case of the Union that in all cases of vacancies in permanent cadre of sub-staff including permanent vacancies, are to be filled up from the list of the Head Office and that too according to seniority and really or in effect that is and should be the only source of appointment for the Bank and in case a panel, so framed, is exhausted, a fresh panel is prepared in the same process as indicated There is no doubt or any dispute that now appointments to the Bank in the cadre of sub-staff are made on the basis of lists available from the Employment Exchanges, but this policy was initially opposed by the Union, for reasons as indicated in the Written Statement. The said Union also stated that on principle they are not also against such policy. But, Mr. Saraugi claimed that such principle will not of course apply here and in the facts of this case.

4. It was pointed out that in or about June 1981, the Bank, on negotiation with the Union, decided to absorb sub-staffs like Canteen Boys, Drivers and Sweepers, for making provisions for new categories, for absorption in the subordinate cadre on division-wise percentage basis, by their Circular marked Ext. W-6, wherein the percentages for absorption have been indicated, apart from indicating|incorporating the date as June 23, 1981 i.e. immediately prior to the date of the said exhibit. It has been alleged, but by the notice under Section 9A of the Act, Ext. W-8, which was also marked as Ext. W-3, the Bank withdrew their aforementioned policy of absorption unilaterally and without any basis or justification.

5. It has been pointed out that Ext. W-6 indicated that the Bank should not give temporary appointment, to a fresh candidate without giving effect to the panel, after June 25, 1981, yet, such temporary appointments were continued to be given and the employee Sambhu Kabirai worked at Gaighata Branch for a total period of 338 days from August 26, 1980 on different dates in permanent as well as additional vacancies and was empanelled as a permanent staff by the Bank, by Order dated November 8, 1980 and similarly, the other employee Ashok Mondal, worked for 150 days in different posts|vacancies, including Additional vacancies from May 28, 1981 and in fact, both the said employees were allowed to work in different vacancies upto the end of 1985 and June 1982 respectively yet, their cases were not considered for such absorption. It was also pointed out that from a letter dated March 1, 1985, addressed to one Madhusudan Mondal, being Annexure 'D' to the Written Statement, the Bank informed that those, who worked for a single day before June 23, 1981 in any Branch temporarily, were entitled to be absorbed in the service and those terms have also been corroborated by Ext. M-4 and M-5 and that being the admited position, it was further indicated that both the concerned employees, because of their admitted character of employment and workings at least for a single date before June 23, 1981, were not absorbed and in fact, such available terms of service and conditions of employment were sought to be interfered with by Exts. W-8 or M-3, eventhough that exhibit, in the admitted facts of the case, was inapplicable in the case of the two employees concerned, for reasons as indicated earlier and as the guidelines of the Government of India, in respect of fresh recruitments, were not applicable in their case.

6. It was claimed that the actions as taken, were contrary to Sections 2(oo), 25G and 25H of the said Act as the case were nothing, but acts of retrenchment of the employees concerned and the Bank should have given them opportunities to be appointed, before filling up the vacancies with new hands, in addition to the contentions that the actions as taken, were also contrary to Rule 8(1) of the Rules. In short, it was claimed that the necessary procedure and formalities in the matter of retrenching the employees concerned, were not duly or at all followed and the procedure of recruitment as indicated to be made through Employment Exchange, was discriminatory. I have already indicated the ultimate views of the Union, which was specifically and fairly stated by Mr. Saraugi.

7. In view of the above, the Union has claimed, for the reinstatement of the employees concerned as subordinate staff, with continuity of service and other relevant and anciliary benefits.

8. In their Written Statement, filed on September 29, 1988, the Bank has stated that the dispute as raised and referred, was not an Industrial Dispute, as such, this Tribunal has no jurisdiction to decide or entertain the same. The basis of such claim or contention, was that the employees concerned were employed on temporary basis on various occassion and for fixed periods and as such, their terms of appointment lapsed on the expiry of their period of engagements and that being the position, there was no cause or any occassion of retrenchment as alleged and so, Sections 25G, 25H or 2(oo), will have no application.

9. It was indicated that the Bank was and is under the obligation, in terms of the provisions of Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act 1959, for short, the 1959 Act, to notify vacancies in the subordinate cadre to concerned Employment Exchanges, apart from recruiting employees in that cadre from other sponsored quota. The fact of employment on notification to the respective

Employement Exchanges, as stated, was not ultimately challenged or disputed by the Union. The question in this case would be, if such procedure, was retrospective or prospective from the relevant date and as such if the employees concerned were bound by the same or what would be the effect of Exts. M-4 and M-5, read alongwith Annexure 'D' to the Union's Written Statement. It was the furher case of the Bank that because of such directions as stated earlier, it had decided to have new recruitments in the subordinate cadre, done on that basis.

10. The basis for and the back ground of the actions as has been taken by the Bank and their justification, has been indicated earlier. It has also been agreed that by that record as above, a policy was evolved to absorb empanelled subordinate staff, who worked even for a day upto June 23, 1981. The character of the employees concerned in this case, do fit in come under that policy. But, it has been stated that this procedure was done away with, by the notice which is also marked as Ext. W-8 and Ext. M-3 and that was due, legal and bonafide and by the document, all the panels as existed at that time, were cancelled, excepting the panel of subordinate staff already prepared from the Employment Exchanges, amongst others, for recruitment to such categories. The days of appointment as claimed by the employees concerned were denied by the Bank and it was stated that the Agents of the concerned Branches had no authority to engage them or any other temporary sub-staff, after the issue of the notice in Ext. M-3|W-8 and in any event, those employees were employed for temporary and fixed periods and there was automatic cessession of their work|employments, after the periods, for which they were employed. So, the non renewal of their employment or refusal to give them any further employment, will not give rise to any dispute under the said Act or in any event. It has, in fact been alleged that the Union accepted the position and raised no dispute.

11. All actions in this case were claimed to be duly, legally and bonafide taken and it was reiterated that since the cases were not cases of retrenchment and taken for the reasons as indicated earlier, so, the provisions of the said Act as indicated earlier or the Rules as claimed, will have no application. It has further been stated that the Bank, no longer retains or follows the old policy and the same has been done away with, for the reasons and circumstances as indicated and that too duly. The actions as taken, were claimed to be due, legal, bonafide and not in violation of principles of natural justice as alleged. In view of the above, it has been claimed that there should be no interference by the Tribunal.

12. From the rejoinder filed on June 6, 1989, it will appear that the Union, apart from repeating their earlier stand|case, has denied the material allegations as put forward by the Bank

13. On the submission of Mr. Kumar as made on the basis and back ground of the aforementioned pleadings, it will appear that the basic facts were not in dispute and in support of the justification of the actions as taken, it was contended that the names of the employees concerned, were in the relevant panel in 1988, which was framed, on following the then recruitment policy, they were engaged on leave vacancies and their tenures came to an end as and when the specified terms, for which they were employed, were over and thereafter, they had no automatic right of absorption. In any event, it was indicated that the employees concerned were not employed continuously for the periods as alleged by them. It was stated that in manner as indicated, from 1980 to 1982, Shri Mondal was not employed for 150 days and from 1982 to May 1985 Shri Kabiraj was not also employed for 338 days as claimed. But, even if their cases were correct, since the practice of such absorption of subordinate staff, was discontinued vide Exts. M-3|W-8, following the directions to have appointments made through processing of the relevant Employment Exchanges and not otherwise, so, the claims of the Union were unjustified. It was stated that the Bank cannot act contrary to the directions as mentioned and that too, after discontinuance of the erstwhile policy or in other words fresh recruitments were and are to be made, in terms of the direction in Ext M-2.

14. It was claimed that the terms of the said 1959 Act, being binding, now, no recruitment is possible, which will be contrary to the said directions I have indicated earlier that the Union has neither disagreed nor disputed the validity of such directions or the bonafides of the same, but contended that those directions were not applicable in respect of the employees, who worked at least for one day upto June 23, 1981. It was also stated that the Bank offered to employ the employees concerned in this case, if their names were sponsored by the Employment Exchange, but the Union did not agree to such offer. It was further pointed out that there was no bonafides in the claim of the Union or the employees, as, much after evolving the recruitment procedure Ext. W-9, the pretended dispute was purported to be raised in 1986 and more particularly when, there was no legal evidence to establish the employment of the employees continuously for 240 days in a year and more particularly when, they were employed intermitently and according to the need of the Bank.

15. It was repeated that this case will not come under Section 2(oo) of the said Act, as there was only refusal to renew their contract of employment and that being the position, section 25H will also have no application or the provisions of Section 25G and 25H or Rule 78 as indicated, will apply.

16. Mr. Sarangi, on facts, pointed out that there is no doubt or any dispute that the employees concerned being temporary employees, will come under the four class of employees as indicated by the Bipartite Settlement and then come the Scheme of absorption. Ext W-6 dated June 25, 1981, which according to him, was not retrospective, but prospective, as no such earlier date of application was mentioned or indicated. So, according to him, Ext. M-5, which specifically protected the case of the employees, who even worked for a day upto June 23, 1981, will apply in this case, as the employees concerned, admittedly had acquired the necessary character and qualifications. Mr. Sarangi's contentions regarding the effect of the directions to appoint empolyees, I have already noted earlier. In fact, Union has not opposed the effect and involvement of the Scheme. But, it has indicated that the same will have no application in this case, for reasons as indicated earlier and if at all, the said

scheme will be applicable to the new entrants. To establish that the instant case was one of retrenchment, reference was made by him to the case of Santosh Gupta Vs-State Bank of India, 1980 (2) LLJ 72 and he contended that the principle as indicated therein, would apply with equal force, as the employees concerned, were recruited against permanent vacancies and thus, the action of the Bank, was not really according to or in terms of the Head Office instructions, but they were contrary thereto Mr. Kumar pointed out that the observations made in this case would not apply, as none of the employees have worked for 240 days continuously and in any event, for the views as indicated, it was not really a case of retrenchment. On the basis of the determination as above and particularly in view of the construction of the words "for any reason whatsoever" as indicated in the case, it is difficult to accept the contentions and submissions of Mr. Kumar in respect of the term retrenchment as indicated indicated in Section 2(oo) of the said Act.

17. On the basis of the pleadings, and considering the effect of the Scheme Ext. W6, which was withdrawn by Ext. M-3| W-9, there cannot by any doubt that the employees concerned in this case, had duly acquired the necessary qualifications in terms of Ext. M-5 and as such, their cases cannot be dealt with in the manner as has been sought to be done. For such acquisition of qualifications and right, the employees concerned in my view, had acquired the necessary qualifications to be absorved in terms of the Bank's own statement and records. The directions as indicated and involved, were not retrospective but prospective and that being the position, they were not applicable in the cases of these two employees and further more, the Rule of 240 days employment, will also have no application in this case. In view of the above, the case of Union of India—Vs—Harigopal and Ors. 1987 (II) LLJ 920 as cited by Mr. Sarangi is not required to be dealt with and discussed indetails, as the fact will distinguish the case from such determinations In view of the Supreme Court's determinations as indicated earlier, the case of Samson Jaysingh—Vs—Malayalam Plantations Ltd., 1988 (II) LLN 707 requires no further consideration and determination. Such being the position, I feel that the employees concerned should have been absorved in terms of Ext. M-5 and in not doing so, the Bank has not acted properly and duly.

18. So this reference should succeed and I order or accordingly and consequent to this order, the employees concerned, should receive their necessary legal benefits, as due.

19 This is my Award.
Dated, Calcutta
The 16th July, 1992.

MANASH NATH ROY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1992

का. आ. 2304.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि., का मधुदा क्षेत्र की मुरली डी. 20/21 पिटास कोलियारी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012(176)/90 आई आर. (कोल-1)]

वी. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th August, 1992

S.O. 2304.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1) Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Murlidih C 20|21 Pits Colliery in Mohuda Area No. II of M|s. B.C.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 3-8-92.

[No. L-20012(176)|90 IR(Coal-1)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 7 of 1991

PARTIES .

Employers in relation to the management of Murlidih 20|21 Pits Colliery in Mohuda Area No. II of M|s. BCCL.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen . Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 27th July, 1992

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012|176|90-I.R. (Coal-I), dated the 5th February, 1991 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of he dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the management of Murlidih 20|21 Pits Colliery in Mohuda Area No. II of M/s. BCCL is justified in not entertaining the age of the workmen Smt. Ram Piyari Devi

Harijan, Sweeper at 35 years as on 28-7-82 justified ? If not then what should be her age:"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of setlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be passed on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and pass an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Sec. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I DHANBAD

Ref. : 7|91

PARTIES :

Employers in relation to the management of 20|21 Pits Colliery of M|s. BCCL.

AND

Their workman

Joint Compromise petition of Employers and workman

The above mentioned Employers and the workman|sponsoring union most respectfully beg to submit jointly as follows :—

1. That the dispute covered by the above reference has been jointly negotiated between the employers and the sponsoring union with a view to arriving at an amicable and mutually acceptable settlement.

2. That as a result of much natural negotiations the parties have agreed to settle the dispute mutually on the following terms and conditions on an overall basis :—

(a) It is agreed that the age recorded in the appointment letter of Smt. Ram Piyari Devi W|o Late Ramadhar Harijan will be accepted by the management.

(b) It is agreed that the age of Smt. Ram Piyari Devi will be accepted as 46 yrs. as on 13|17-5-82.

(c) It is further agreed that this is an over-all settlement in full and final setlement of all the charges of the concerned workmen and the sponsoring union arising out of the above reference.

3. That the Employers and the workman|sponsoring union hereby declared and confirm that they consider the above terms of settlement to be fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above, both the parties jointly pray that the Hon'ble Tribunal I may be pleased to accept this joint compromise petition and give an Award in terms thereof and dispose of the above reference.

(B. MOHANTHY) (MM BHATTACHARYA)
Area Secy. BCKU. General Manager, BCCL,
Mohuda Area

Part of the Award.

R K MUKHERJEE Personnel Manager,
BCCL, Mohuda Area.

नई दिल्ली 10 अगस्त, 1992

का. आ. 2395 — औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कं. लि. की चासनाला कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-8-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012 (77)/90 आई आर (कोल-1)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th August, 1992

S.O. 2305.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1) Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of M|s. Indian Iron & Steel Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 3-8-92.

[No. L-20012(77)|90 I.R. (Coal-I)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 261 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of M|s. IISCO, Chasnalla.

-VS-

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen.—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 27th July, 1992

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/77/90-I.R. (Coal-I), dated the 15th November, 1990 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the demand of the Union for providing employment to the dependant of Shri Takan Chamar, Ex. P. No. 5064, Ex. Pump Khalasi of Town Deptt. of Chasnalla Colly. of M/s. IISCO, as per provision of clause 9 : 4 : 3 of the NCWA-III and relevant provisions of NCWA-IV, is justified ? If so, to what relief the workman is entitled and from what date ?"

2 The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be passed on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and pass an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

Sd/-

S. K. MITRA, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

Reference No. 261/1990

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Chasnalla Colliery of IISCO Ltd., P.O. Chasnalla, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

Joint compromise petition of the employers and Workmen :

The above mentioned employers and the workmen beg to submit jointly as follows :

1. That the matter covered by the above Reference was mutually negotiated between the Employers and the workmen with a view to arriving at an amicable and mutually acceptable overall settlement.

2. That as a result of such negotiation, the Employers and the Workmen have agreed to settle the dispute on the following terms and conditions :

   (a) It is agreed that the Employers shall provide employment to Shri Umesh Kumar Das son of Shri Tekna Chamar, Ex-P/No. 5064, Ex-Pump Khalasi of Chasnalla Colliery in the Post of Mazdoor in NCWA-IV pay scale of Cat. I (Pay Scale Rs. 38.47—0.70—48.27) subject to his medical fitness.

   (b) It is agreed that such employment will be provided as stated in clause (a) within a period of 6 months from the date of compromise petition.

   (c) It is agreed that this is an overall settlement in full and final settlement of all the claim of the workmen arising out of the above reference.

3. That the Employers and the workman consider and hereby declare that the above terms and conditions of settlement, are just, fair and reasonable to both the parties.

The Employers and the workman, therefore, jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this joint compromise petition and given an Award in terms thereof and dispose of the reference accordingly.

(D. Mukherjee)
Secretary, BCKU.
for and on behalf of Workman

(R. Mohan)
Manager (Personnel)
Chasnalla
For and on behalf of Employers

Witness :

1. Shri Tekna Chamar.
   Umesh Kumar Das.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992